चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 05 जून- 11 जून 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

खुल रहा नगा समझौते का 'रहस्य', दे रहे विद्रोहियों को 'आज़ादी'!

देश से कौन खेल रहा है

- गोपनीय क्यों रखा गया नगा शांति समझौते का मसौदा?
- कश्मीरी अलगाववादियों की 'आज़ादी' की मांग राष्ट्रद्रोह
- नगा अलगाववादियों की 'आज़ादी' की मांग राष्ट्रवाद कैसे!
- नगालैंड का होगा अपना जज, अपनी सेना और अपनी मुद्रा
- सेना बोली, ऐसा हुआ तो नगालैंड भी हाथ से निकला समझें
- क़ानून को ठेंगा, पीएमओ ने जेल से छुड़वाया ख़ूंख़ार विद्रोही

प्रभात रंजन दीन

क्या मोदी सरकार पूर्वोत्तर में एक और कश्मीर स्थापित करने की कोशिश में है, जिसका अपना संविधान होगा, अपनी न्यायिक व्यवस्था होगी, अपना झंडा होगा, अपनी मुद्रा होगी, अपना पासपोर्ट होगा और अपनी सेना होगी, जो भारतीय सेना के साथ साझा तौर पर काम करेगी! भारतीय सेना के शीर्ष अफसर भी यह संकेत दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नगाओं को 'आजादी' देने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में कश्मीर से ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है. पूर्वोत्तर के साथ-साथ शेष भारत के आम लोग भी पीएम मोदी से पूछ रहे हैं कि कश्मीरी अलगाववादियों की 'आजादी' की मांग राष्ट्र-द्रोह और नगा विद्रोहियों की 'आजादी' की मांग राष्ट्रवाद कैसे है? यह वाजिब लोकतांत्रिक सवाल है, इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना ही चाहिए.

केंद्र की सत्ता में आने के सालभर बाद ही तीन अगस्त 2015 को नरेंद्र मोदी सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड 'ईसाक-मुइवा' (एनएससीएन-आईएम) गुट के साथ एक समझौता किया, लेकिन देश के सामने इसका ब्यौरा नहीं रखा. केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया कि पहले इसका विवरण संसद के समक्ष रखा जाएगा, फिर बाद में इसे सार्वजनिक किया जाएगा. लेकिन केंद्र सरकार ने दोनों काम नहीं किया. न संसद में रखा और न जन-संसद को इस लायक समझा. समझौते के दो साल होने को आए, लेकिन केंद्र सरकार ने देश को यह बताने की जरूरत नहीं समझी कि समझौते के कौन-कौन से मुख्य बिंदु हैं और केंद्र सरकार ने एनएससीएन की क्या-क्या शर्तें मानी हैं. केंद्र ने इसे गोपनीय बना कर रखा है लेकिन पूर्वोत्तर मामलों के विशेषज्ञ वरिष्ठ सेनाधिकारी केंद्र सरकार द्वारा मानी गई शर्तों की परतें खोलते हैं और उन पर अपना क्षोभ जाहिर करते हैं. गृह मंत्रालय के एक आला अधिकारी ने कहा कि एनएससीएन (आईएम) के स्वयंभू लेफ्टिनेंट जनरल और विदेश मंत्री अंथोनी निंगखन शिमरे ने जमानत पर छूटने के बाद जो बातें कहीं, उसके बाद समझौते की गोपनीयता कहां रह गई. शिमरे के बयान को ध्यान से देखें, उसने तो बता ही दिया है कि क्या होने जा रहा है. शिमरे एनएससीएन प्रमुख मुइवा का भांजा है. शीर्ष सत्ता गलियारे में जिस तरह की सुगबुगाहटें हैं, उससे केंद्र सरकार के एनएससीएन (आईएम) के आगे दंडवत होने के कई उदाहरण सामने दिखने लगे हैं. विदेशों से बड़ी तादाद में हथियारों का जखीरा जमा करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए अंथोनी शिमरे की जमानत अर्जी पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) का कोई आपत्ति दर्ज नहीं करना और शिमरे को बड़े आराम से जमानत मिल जाना, केंद्र सरकार की दंडवत-कथा के बारे में काफी-कुछ कहता है. दिल्ली के पटियाला हाउस स्पेशल कोर्ट के जज अमरनाथ के समक्ष एनआईए के स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने 'ऑन-रिकॉर्ड' कहा था कि उन्हें ई-मेल पर एनआईए से निर्देश मिला है कि शिमरे की जमानत अर्जी पर कोई आपत्ति दाखिल न की जाए. एनआईए के वकील ने अदालत से यह भी कहा कि शिमरे की जमानत एनएससीएन (आईएम) के साथ चल रही शांतिवार्ता के कार्यान्वयन के लिए जरूरी है. शिमरे को सितम्बर 2010 में काठमांडू में गिरफ्तार दिखाया गया था. उसे चीन के साथ हथियारों की बड़ी डील करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन चार अगस्त 2016 को एनआईए ने ही शिमरे की रिहाई का रास्ता खोल दिया. रिहा होने के बाद अंथोनी शिमरे ने कहा कि बृहत्तर नगालिम की स्वायत्तता, अलग संविधान, अलग न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था, अलग मुद्रा और साझा सेना समझौते की मुख्य शर्त है. शिमरे ने इसकी पुष्टि की कि समझौते के आधार पर नए नगा राज्य की अपनी अलग न्यायिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था होगी. रक्षा मसले पर नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर आर्मी, भारतीय सेना और नगा सेना साझा तौर पर काम करेगी. नगालैंड और भारत की अपनी अलग-अलग स्वतंत्र पहचान होगी. नगालैंड की जमीन और संसाधनों का इस्तेमाल सिर्फ नगा ही करेंगे.

पूर्वोत्तर मामलों के विशेषज्ञ और पूर्वोत्तर में कोर कमांडर रहे लेफ्टिनेंट जनरल (रि.) जेआर मुखर्जी का कहना है कि अब तक जो सुराग मिले हैं उसके मुताबिक केंद्र सरकार नगाओं को अलग संविधान, अलग झंडा, अलग मुद्रा और अलग पासपोर्ट का अधिकार देने पर रजामंद हो गई है. जनरल मुखर्जी कहते हैं कि इस समझौते से नगालैंड का संयुक्त राष्ट्र में अपना प्रतिनिधि तैनात होना तय हो जाएगा. नगालैंड का विदेश और रक्षा का मसला भारत सरकार के साथ संयुक्त विषय होगा. नगालैंड की अपनी सेना होगी जो भारतीय सेना के साथ साझा तौर पर काम करेगी. समझौते के तहत नगा बसावट के सभी क्षेत्र बृहत्तर नगालैंड में शामिल किए जाने की भी अंदर-अंदर तैयारी चल रही है. बृहत्तर नगालिम में नगालैंड के साथ-साथ मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम के नगा बसावट के इलाके भी शामिल होंगे. इस प्रस्ताव का मणिपुर राज्य की तरफ से पहले से पुरजोर विरोध हो रहा है. लेकिन यह विडंबना ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ मणिपुर की अस्मिता को अक्षुण्ण रखने की तकरीरें देते हैं तो दूसरी तरफ बृहत्तर नगालिम की स्थापना के समझौते करते हैं. सेना की पूर्वी कमान से सम्बद्ध एक वरिष्ठ सेनाधिकारी कहते हैं कि नगा समझौते में केंद्र सरकार की सहमति के ये मुद्दे अगर सच हैं, तो नगालैंड को हाथ से निकला ही समझिए. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु और प्रादेशिक राष्ट्रवाद की भावना से ओत-प्रोत कई अन्य राज्यों में हिंसक आंदोलनों के भड़कने की भी आशंकाओं को खारिज नहीं किया जा सकता.

प्रधानमंत्री मोदी ने एनएससीएन के थुइंगलेंग मुइवा और ईसाक चीसी स्वू के नेतृत्व वाले गुट से शांति समझौता किया, लेकिन एनएससीएन के एसएस खापलांग और खोले कोन्याक के नेतृत्व वाले गुट समेत कई प्रमुख गुटों को शांति वार्ता से अलग रखा. दिलचस्प यह है कि नगालैंड की अलग सेना रखने की सहमति इस तर्क पर दी गई कि खापलांग गुट का मुकाबला करने के लिए मुइवा गुट को अलग से हथियार और सेना की जरूरत होगी. समझौते पर एनएससीएन की तरफ से मुइवा ने हस्ताक्षर किए हैं. विचित्र किंतु सत्य यह है कि नगा शांति समझौते में केंद्र सरकार द्वारा मानी जाने वाली शर्तों पर गृह मंत्रालय ने गहरी आपत्ति जताई थी, लेकिन प्रधानमंत्री और उनके सिपहसालारों ने इस आपत्ति को दरकिनार कर दिया. गृह मंत्री से बड़ी औकात सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की साबित हुई जिनकी सिफारिश पर आरएन रवि नगा शांति समझौते के मुख्य वार्ताकार नियुक्त कर लिए गए. शांति वार्ता में मध्यस्थता के लिए पूर्व खुफिया अधिकारी आरएन रवि का नाम प्रस्तावित किए जाने का भी गृह मंत्रालय ने विरोध किया था. गृह मंत्री ने संयुक्त खुफिया कमेटी के चेयरमैन अजित लालका नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन मोदी ने अपने गृह मंत्री राजनाथ सिंह की नहीं सुनी और डोवाल का कहना मान कर पूर्व खुफिया अधिकारी आरएन रवि को मुख्य वार्ताकार बना डाला. मुख्य वार्ताकार की दौड़ में लेफ्टिनेंट जनरल (रि.) आरएन कपूर और असम पुलिस के पूर्व प्रमुख जीएम श्रीवास्तव का भी नाम (शेष पृष्ठ 2 पर)

एनएससीएन (आईएम) को हथियार लाने ले जाने की छूट

भारत सरकार ने एनएससीएन (आईएम) को हथियार ख़रीदने, रखने और साथ लेकर चलने की खुली छूट दे दी है. लेकिन शर्त यह है कि उन्हें हथियार भारत सरकार से ही खरीदने होंगे. भारत सरकार ने एनएससीएन के कुछ ख़ास कैंपों को भी हथियार रखने की छूट दे दी है. एनएससीएन (आईएम) के सदस्यों को लाल, पीला और हरा कार्ड दिया गया है. एनएससीएन (आईएम) के जिन सदस्यों या कमांडरों के पास लाल कार्ड होगा, उन्हें अपने साथ हथियार लेकर चलने की छूट रहेगी. लाल कार्डधारी सदस्य या कमांडर अपने साथ हथियार ला और ले जा सकेंगे. भारत सरकार ने यह 'गैर-कानूनी' सुविधा केवल एनएससीएन (आईएम) के लिए दी है. इस कार्ड के जरिए एनएससीएन (आईएम) के कमांडर और सदस्य हथियार लेकर कहीं भी आ-जा सकेंगे. सेना के एक अधिकारी ने कहा कि नगा शांति समझौते की यह प्राथमिक शर्त है. अलग-अलग रंग के कार्ड अलग-अलग सुविधाओं के लिए दिए गए हैं. इन कार्डों पर बाकायदा भारत सरकार और एनएससीएन (आईएम) की आधिकारिक मुहर है. ये कार्ड इस बात की सनद भी हैं कि भारत सरकार और एनएससीएन (आईएम) के बीच समझौता लागू होने की प्रक्रिया में आ चुका है. ■

नगा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद एनएससीएन (आईएम) के मुखिया थुइंगलेंग मुइवा और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि आरएन रवि

देश से कौन खेल रहा है

पृष्ठ 1 का शेष

था, लेकिन पीएमओ में उनकी नहीं चली.

गृह मंत्रालय और पूर्वोत्तर मामलों के विशेषज्ञों की आपत्तियों को नजरअंदाज कर शांति वार्ता में केवल ईसाक-मुइवा गुट को ही क्यों शामिल किया गया और खापलांग गुट को क्यों अलग-थलग रखा गया? यह गंभीर सवाल है और समझौते की संदेहास्पद-अंतरकथा का संकेत देता है. वर्ष 2015 के अगस्त महीने में केंद्र सरकार एनएससीएन ईसाक-मुइवा गुट के साथ गुप्त समझौता करती है और 16 सितम्बर को एनएससीएन खापलांग गुट पर बैन लगाने का आदेश जारी कर देती है. केंद्र सरकार जून 2015 में मणिपुर में सुरक्षा बल के 18 जवानों के मारे जाने की घटना से खापलांग गुट को जोड़ कर, चार महीने बाद उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर उस पर प्रतिबंध लगाती है. प्रतिबंध लगाने के पहले ही म्यांमार सीमा में घुस कर खापलांग गुट के आतंकियों को मार डालने और ठिकानों को नष्ट किए जाने के 'मिलिट्री-स्ट्राइक' का खूब प्रचार-प्रसार किया जाता है. लेकिन यह असलियत देश को नहीं बताई जाती कि म्यांमार (बर्मा) सरकार ने अपने यहां सागाइंग डिवीजन को बाकायदा नगा सेल्फ-एडमिनिस्टर्ड ज़ोन घोषित कर रखा है, जिसमें म्यांमार के छह जिले तामू, मोलाइक, फुऑनपिन, होमालिन, खामटी और तानाई जिले शामिल हैं. हाल में म्यांमार सरकार ने तीन जिले वापस लिए. अन्य तीन जिलों लाएशी, लाहे और नामयुंग में खापलांग गुट का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्थापित है. खापलांग गुट लगातार यह मांग करता रहा है कि शांति वार्ताओं में उसे भी शामिल रखा जाए. लेकिन कुछ 'अज्ञात' वजहों से मोदी और उनके खास नुमाइंदों ने इस ताकतवर गुट को दूध की मक्खी बना कर बाहर कर दिया. पूरब के नगाओं को इस बात का गहरा मलाल है कि मोदी सरकार ने उनकी उपेक्षा की जबकि पश्चिम के नगाओं की खूब सुनी. खापलांग गुट न केवल नगालैंड बल्कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार तक नगाओं के बीच खासा प्रभावी और लोकप्रिय है. इससे समझा जा सकता है कि एक गुट के साथ शांति समझौता करके केंद्र सरकार ने पूरे क्षेत्र को किस हिंसक विद्रोष की आग में झोंकने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है.

वर्ष 1956 की बात है जब नगालैंड की स्वतंत्र पहचान की मांग हिंसक युद्ध की शक्ल में बदल गई थी और फीजो ने नगा नेशनल काउंसिल (एनएनसी) को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया था. इसके बाद ही नगा पर्वतीय क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया और उसे सेना के हवाले कर दिया गया था. तब से यह क्षेत्र लगातार अशांत ही है. तब नेहरू ने कहा था कि सेना कुछ ही महीनों में हटा ली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और विभिन्न कारणों से सेना की मौजूदगी वहां लगातार बनी हुई है. थल सेना की तीसरी कोर का मुख्यालय दीमापुर में स्थापित है. ईशाक-मुइवा गुट के नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन) के साथ 1997 से युद्ध विराम लागू है. तबसे लगातार भारत सरकार और एनएससीएन के साथ समझौता वार्ता भी जारी है. हम यह भी याद करते चलें कि नगा नेशनल काउंसिल और केंद्र सरकार के बीच 1975 में हुए शिलांग समझौते के विरोध में 31 जनवरी 1980 को ईसाक चिसी स्वू, थुइंगलेंग मुइवा और एसएस खापलांग ने मिल कर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड का गठन किया था. 1988 में खापलांग ने टूट कर अपना अलग गुट बना लिया. 25 जुलाई 1997 को केंद्र सरकार और एनएससीएन (आईएम) के साथ समझौता हुआ और दोनों तरफ से युद्ध विराम की घोषणा हुई. लेकिन इस दरम्यान कोई स्थायी समाधान नहीं ढूंढ़ा जा सका. 28 जून 2016 को ईसाक चिसी स्वू की मृत्यु के बाद थुइंगलेंग मुइवा एनएससीएन (आईएम) के अकेले प्रमुख हो गए. तीन अगस्त 2015 को मोदी सरकार ने एनएससीएन (आईएम) के साथ नगा शांति समझौता किया और दावा किया कि इस समझौते से 60 साल पुराने विवाद का हल निकल आया है. लेकिन क्या हल निकला, इस बारे में केंद्र सरकार ने देश को कुछ नहीं बताया. यह सवाल देश के सामने खड़ा ही रह गया कि आखिर नगा शांति समझौते का क्या परिणाम निकला? प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी खास तौर पर पूर्वोत्तर को लेकर संजीदा दिखते रहे और पूर्वोत्तर की तमाम योजनाओं का पूरा प्रचार-प्रसार भी होता रहा. लेकिन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि नगा शांति समझौते को लेकर मोदी ने चुप्पी क्यों साध रखी है. यह भी आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं किया गया है कि नगा शांति समझौता स्वतंत्र संप्रभु नगालिम राष्ट्र के लिए हुआ है या बृहत्तर नगालिम राज्य के लिए. सेना के सूत्र और खुद एनएससीएन (आईएम) के शीर्ष कमांडर शिमरे जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वह नगा आजादी की तरफ बढ़ने का ही संकेत है. केंद्र को यह तो बताना ही चाहिए कि स्वतंत्र संप्रभु नगालिम की मांग करने वाले एनएससीएन (आईएम) को आखिर किन शर्तों पर समझौते के लिए राजी किया जा सका. ऐसी गोपनीयता पहली बार बरती गई है. सरकार ने केवल इतना कहा है कि इस समझौते से पिछले 60 साल से चला आ रहा गतिरोध लगभग समाप्त हो गया है.

एनएससीएन समेत कई संगठन लंबे अर्से से बृहत्तर नगालिम या ग्रेटर नगालैंड की मांग करते चले आ रहे हैं. इसके तहत मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम के नगा समुदाय की बहुलता वाले पहाड़ी जिलों को मिलाकर ग्रेटर नगालैंड बनाने की मांग की जाती रही है. केंद्र सरकार एनएससीएन (आईएम) को स्वायत्तता देने पर राजी हो गई है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी और यह कैसे लागू होगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है. नगा शांति वार्ता की प्रक्रिया से जुड़े गृह मंत्रालय के एक अधिकारी कहते हैं कि नगा बहुल क्षेत्रों के बृहत्तर नगालैंड में शामिल करने के मसले को फिलहाल किनारे रख कर बाकी मसलों पर दोनों पक्षों में सहमति बन गई है. दोनों पक्ष खापलांग गुट और उसका साथ देने वाले गुटों का पूरी तरह सफाया करने पर रजामंद हैं. केंद्र ने नागालिम की मांग को सिरे से खारिज नहीं किया है. इसे फिलहाल भविष्य पर छोड़ दिया गया है क्योंकि असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में हो रहे तीखे विरोध के कारण ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है. लेकिन नगा समझौते की मूल मांग नगा बहुल क्षेत्रों को एक साथ करने की है. एनएससीएन (आईएम) प्रमुख थुइंगलेंग मुइवा मणिपुर के उखरूल जिले के शोनग्राम (सोमडाल) गांव के रहने वाले हैं, इसलिए नगा बहुल इलाकों के विलय की मांग उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा मसला है.

बहरहाल, एनएससीएन प्रमुख थुइंगलेंग मुइवा के भांजे अंथोनी शिमरे की गिरफ्तारी और फिर नाटकीय रिहाई से सैन्य और खुफिया एजेंसियों का एंटीना सजग हुआ, लेकिन इस सजगता का कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला. निरंकुश पीएमओ और ताकतवर सुरक्षा सलाहकार के कारण सेना और खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी खुले तौर पर भले ही कुछ न कहें, लेकिन उनके अपने दायरे में इस बात को लेकर चर्चा और गहरी चिंता है कि चीन सम्बन्धों के संदर्भ में नगा समझौता भारत के लिए एक और खतरे का मुहाना खोलने जैसा होगा. पूर्वोत्तर में आतंकवाद भड़काने के लिए चीन हथियारों की अंधाधुंध सप्लाई में लगा है. शिमरे की गिरफ्तारी इसकी आधिकारिक पुष्टि है. हथियार के एवज में चीन पैसा कम भारत की जासूसी अधिक चाहता है, ताकि उसे पूर्वोत्तर में तैनात हो रही मिसाइल प्रणालियों और सैन्य ठिकानों का पता चलता रहे. कुछ वर्ष पहले यह आधिकारिक खुलासा हुआ था कि चीनी अधिकारियों ने मणिपुर के यूएनएलएफ नेताओं से भारतीय मिसाइलों की तैनाती और सैनिकों की आवाजाही के बारे में जानकारियां मांगी थीं. लेकिन भारत सरकार ने इस मसले को नहीं उठाया और न अपना विरोध जताया.

शिमरे ने एनएससीएन की तरफ से चीन के सबसे बड़े हथियार निर्माता नोरिंको को एक लाख डॉलर का अग्रिम भुगतान किया था. चीन के हथियार निर्माता को शिमरे ने बैंकॉक में पैसा दिया था. नोरिंको के चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन और एनएससीएन (आईएम) के बीच 10 हजार असॉल्ट राइफलें, पिस्तौलें, रॉकेट प्रक्षेपित हथगोलों और गोला-बारूद की खरीद के लिए डील हुई थी. यह सूचनाएं सूत्रों के हवाले से नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय के आधिकारिक दस्तावेजों के हवाले से लिखी जा रही हैं. सैन्य खुफिया एजेंसी के अधिकारी कहते हैं कि नोरिंको चीनी सेना का ही एक कवर-फेस है. नोरिंको और एनएससीएन (आईएम) का काफी पुराना रिश्ता है. यानि, एनएससीएन (आईएम) चीन का ही एक मुहरा है. कुछ वर्ष पहले बांग्लादेश में जो हथियारों का बड़ा भारी जखीरा पकड़ा गया था, वह एनएससीएन (आईएम) के लिए ही आया था. उसी समय नोरिंको का नाम उजागर हुआ था. विडंबना यह है कि चीन द्वारा इस तरह हथियारों की निर्बाध सप्लाई का मसला भारत सरकार ने द्विपक्षीय संवाद में या अंतरराष्ट्रीय फोरम पर कभी नहीं उठाया. नगालैंड और पूर्वोत्तर के आतंकवादी आराम से चीन जाकर हथियारों की डील कर लेते हैं. चीन पूर्वोत्तर के आतंकी संगठनों को अपनी धरती पर ठिकाने बनाने की इजाजत भी देता है. एनएससीएन और उल्फा समेत कई संगठन चीन के यून्नान समेत कई अन्य सीमाई प्रांतों से संगठन चलाते रहे हैं. यहां तक कि चीन की सेना द्वारा आतंकियों को ट्रेनिंग देने की खबरें भी मिलती रही हैं और पीएमओ में दबती रही हैं. चीन में ट्रेनिंग लेने वाले आतंकियों में मणिपुर के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के प्रमुख मेघेन का भी नाम है जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया था. मेघेन मणिपुर राजघराने से सम्बद्ध है. उसके पास से चीन की हरकतों के जुड़े तमाम दस्तावेज बरामद किए गए थे.

अटल-मोदी लोकप्रिय, पर किन शर्तों पर!

पूर्वोत्तर राज्यों में खास तौर पर नगालैंड का मसला इतना उलझा रहा है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक किसी भी प्रधानमंत्री को नगालैंड की धरती पर उपेक्षा और असम्मान

ही प्राप्त हुआ है. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अपवाद हैं. वाजपेयी ने नगाओं की दुर्लभ ऐतिहासिक संस्कृति की प्रशंसा की थी और केंद्र सरकार द्वारा की गई गलतियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था. अटल ने 1962 से लेकर 1965, 1971 और करगिल युद्ध तक नगालैंड के सैनिकों के योगदान और बलिदान को खास तौर पर रेखांकित किया था. इसीलिए नगाओं में अटल काफी लोकप्रिय प्रधानमंत्री हुए. कोहिमा में 28 अक्टूबर 2003 को हुए अटल बिहारी वाजपेयी के ऐतिहासिक भाषण को आज भी नगालैंड के लोग याद करते हैं. अगस्त 2015 में नगाओं के साथ शांति समझौता कर नरेंद्र मोदी भी खासे लोकप्रिय हो गए, लेकिन इस समझौते को लेकर अरुणाचल, मणिपुर और असम में उनकी निंदा भी हो रही है. कांग्रेस के शासनकाल में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने तो कभी भी कोहिमा की यात्रा ही नहीं की. 30 मार्च 1953 को जवाहरलाल नेहरू कोहिमा गए थे, लेकिन उनकी सभा में पांच हजार नगा नागरिक नेहरू की तरफ पीठ घुमा कर बैठ गए थे. इससे नेहरू ने काफी अपमानित महसूस किया था. मोरारजी देसाई और एचडी देवेगौड़ा भी नगालैंड गए, लेकिन उनकी यात्रा कहीं भी किसी भी प्रसंग में उल्लेखनीय नहीं है.

'संदेहास्पद' समझौते में पेट्रोल का 'संदेहास्पद' रोल

एनएससीएन (आईएम) और मोदी सरकार के बीच हुए 'संदेहास्पद' समझौते के पीछे तेल का भी खेल है. एनएससीएन (आईएम) तेल-ब्लॉक का पूरा ठेका अपने हाथ में लेना चाहता है, जबकि कई प्रमुख उद्योगपति इसे हथियाने की फिराक में हैं. 2012 के नगालैंड पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस रेगुलेशंस के तहत नगालैंड के तेल-फील्ड नगालैंड सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गए

(शेष पृष्ठ 3 पर)

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 09 अंक 14
05 जून- 11 जून 2017
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के - 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय	0120-6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022-65500786
	+91-8451050786
	+91-9266627379
फैक्स न.	0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

देश से कौन खेल रहा है

पृष्ठ 2 का शेष

और सरकार ने तेल का ठेका निजी कंपनियों को दे दिया. एनएससीएन व अन्य संगठनों के हिंसक विरोध को देखते हुए जब ऑयल एंड नैचुरल गैस कमीशन ने नगालैंड में तेल और गैस के स्रोत तलाशने का काम छोड़ दिया, तब ओएनजीसी द्वारा छोड़े गए तेल-फील्ड पर भी नगालैंड सरकार ने कब्जा कर लिया. धन का सबसे मजबूत स्रोत होने के कारण पूर्वोत्तर के तेल-ब्लॉक नगा शांति समझौते की जड़ में हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि ये तेल-ब्लॉक अगर भारत सरकार के हाथ से निकल गए तो बड़ा पूंजी स्रोत एनएससीएन के हाथ लग जाएगा, जिसके दूरगामी नकारात्मक नतीजे निकल सकते हैं. सरकारी आकलन है कि अकेले नगालैंड में 60 करोड़ (छह सौ मिलियन) टन तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है. अगर इसका पूरा दोहन हुआ तो देश के तेल-गैस उत्पादन में 75 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो जाएगी. केंद्र ने बहुत दिनों के बाद एक बार फिर नई नीति बना कर ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में रहे तेल-ब्लॉक्स को नीलाम करने का फैसला किया, लेकिन वह फैसला भी नगा शांति समझौते के पेंच में फंस गया है.

समझौता कहीं आत्मघाती न साबित हो

पूर्वोत्तर और चीन मामलों के विशेषज्ञ अधिकारी इस बात से आशंकित हैं कि एनएससीएन (आईएम) से हुआ समझौता भारत के लिए कहीं आत्मघाती न साबित हो जाए. उनका मानना है कि एनएससीएन हमेशा से चीन-परस्त रहा है, उसकी प्रतिबद्धता चीन के प्रति अधिक है. कहीं ऐसा तो नहीं कि एनएससीएन भारत सरकार के साथ समझौता करके चीन की रणनीति को ही अमल में ला रहा हो. खुफिया एजेंसियों को चीन की प्लानिंग से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले थे. ये दस्तावेज चीन से ट्रेनिंग लेकर आए आतंकियों की गिरफ्तारी में बरामद हुए थे. चीन का प्लान रहा है कि भारत पर पहले तिब्बत के दक्षिण की तरफ से 'सिलीगुड़ी गलियारे' पर धावा बोला जाए, जिससे पूरे पूर्वोत्तर को शेष भारत से काटा जा सके. फिर विद्रोही गुटों की मदद से भारतीय सेना को लंबे समय तक उलझाए रखा जाए और आराम से अरुणाचल प्रदेश के विस्तृत इलाके पर कब्जा कर लिया जाए. इसी रणनीति के तहत चीन लगातार नगा, मिजो, मणिपुरी, उल्फा समेत कई अन्य आतंकी गुटों को न केवल आधुनिक हथियार मुहैया करा रहा है बल्कि उन्हें अपने यहां सुरक्षित अड्डे और सैन्य प्रशिक्षण भी उपलब्ध करा रहा है. लेकिन मोदी सरकार के लिए यह विचारणीय प्रश्न नहीं है.

पीएमओ ने एनआईए पर दबाव डालकर शिमरे को छुड़वाया

नगा शांति समझौते में विचित्रताएं भरी पड़ी हैं. इसमें शांति कहीं नहीं है, केवल समझौता है. आज स्थिति यह है कि एनएससीएन (आईएम) देश की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को अपना दुश्मन मानता है. चीन के साथ हथियारों की बड़ी डील करने के आरोप में बड़ी मशक्कतों से पकड़े गए एनएससीएन (आईएम) के कथित लेफ्टिनेंट जनरल अंथोनी शिमरे को एनआईए छोड़ना नहीं चाहता था. लेकिन पीएमओ की तरफ से एनआईए पर भीषण दबाव था. एनआईए का आधिकारिक तौर पर कहना था कि एनएससीएन (आईएम) एक

अंथोनी शिमरे

नगाओं के कई गुट सक्रिय तो एक से इतना प्यार क्यों!

बहुप्रचारित नगा शांति समझौते को लेकर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि केंद्र सरकार ने शांति वार्ता में केवल एनएससीएन के ईसाक-मुइवा गुट को ही क्यों शामिल रखा? केंद्र सरकार ने खापलांग गुट को प्रतिबंधित करके ईसाक-मुइवा गुट का हित क्यों साधा? बृहत्तर नगालैंड को लेकर पूर्वोत्तर के कई संगठन लंबे अर्से से आंदोलन चला रहे हैं, फिर समझौता वार्ता में उन संगठनों को शामिल क्यों नहीं किया गया? ईसाक-मुइवा गुट के साथ समझौता करने के एक महीने बाद ही केंद्र ने गैरकानूनी गतिविधियां निषेध कानून के तहत खापलांग गुट को बैन करने की अधिसूचना किस दबाव में जारी की. केंद्र सरकार का कहना है कि मार्च 2015 में खापलांग गुट ने ही शांति वार्ता में शरीक होने से मना कर दिया था. बहरहाल, नगालैंड में खापलांग गुट के अलावा फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नगालैंड 'नॉन-एकॉर्डिस्ट' (एफजीएन-एनए), फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नगालैंड 'एकॉर्डिस्ट' (एफजीएन-ए), नॉन एकॉर्डिस्ट फैक्शन ऑफ नगा नेशनल काउंसिल (एनएनसी-एनए), नगा नेशनल काउंसिल 'एकॉर्डिस्ट' (एनएनसी-एकॉर्डिस्ट) और झेलिआंगरोंग यूनाइटेड फ्रंट (ज़ेडयूएफ) जैसे संगठन काफी सक्रिय हैं. इनके अलावा नगा नेशनल काउंसिल 'अडीनो' (एनएनसी-अडीनो), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड 'यूनिफिकेशन' (एनएससीएन-यू), नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड 'खोल-किटोवी' (एनएससीएन-केके) और नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड 'रिफॉर्मेशन' (एनएससीएन-आर) जैसे गुट भी अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं. खापलांग गुट न केवल नगालैंड बल्कि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ जिलों में भी सक्रिय है. खापलांग गुट को पूर्वोत्तर का सबसे खतरनाक और ताकवर गुट कहा जाता है. नगा आदिवासियों की करीब 17 प्रमुख जातियां और 20 उप जातियां हैं. नगा संगठन इन्हीं प्रमुख जातियों का अलग-अलग प्रतिनिधित्व करते हैं. इन सभी संगठनों में इस बात की गहरी नाराजगी है कि समझौता वार्ता में उन्हें शामिल नहीं किया गया. खापलांग गुट शांति वार्ता में शरीक होने की फिर से पहल कर रहा है. खापलांग गुट के डिप्टी कमांडर इन चीफ नीकी सूमी ने सार्वजनिक बयान दिया कि खापलांग गुट के सैन्य प्रमुख ईसाक सूमी ने म्यांमार में भारत के राजदूत विक्रम मिसरी से मिल कर शांति वार्ता में शरीक किए जाने का औपचारिक आग्रह किया. राजदूत ने भारत सरकार को इस बारे में इत्तिला भी कर दी, लेकिन केंद्र ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. खापलांग गुट द्वारा युद्ध विराम संधि तोड़े जाने को लेकर केंद्र की नाराजगी भी अपनी जगह जायज है. ■

खापलांग

आतंकवादी संगठन है और उसके एक शीर्ष सरगना का छोड़ा जाना देश के लिए कतई उचित नहीं है. लेकिन मोदी सरकार के सामने एनआईए की नहीं चली. पीएमओ के दबाव में एनआईए ने शिमरे की जमानत अर्जी पर कोई आपत्ति दाखिल नहीं की और शिमरे को जमानत मिल गई. दुखद पहलू यह है कि जिस संगठन के आगे भारत सरकार नतमस्तक है, वह संगठन भारत में आतंकवादी संगठनों के बारे में खुफिया जानकारियां हासिल करने वाली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अपना दुश्मन बताता है. एनएससीएन (आईएम) का कमांडर शिमरे खुलेआम कहता है कि एनआईए नगा शांति समझौते की वार्ता प्रक्रिया को बाधित करने की साजिश कर रहा था. भारत सरकार इस पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करने के बजाय चुप्पी साधे रह जाती है. शिमरे कहता है कि उसे काठमांडू से गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि उसे अगवा किया गया था. शिमरे को इस बात का भी गुस्सा है कि एनआईए ने हथियारों के कुख्यात डीलर विल्ली नारू को क्यों गिरफ्तार किया. जमानत मिलने के बाद केंद्र सरकार ने अंथोनी शिमरे को शांति वार्ता प्रक्रिया का स्थायी सदस्य बना दिया और एनआईए खंभा नोचती रह गई. आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नगा समझौता वार्ता के मुख्य मध्यस्थ आरएन रवि एनएससीएन (आईएम) कमांडर अंथोनी शिमरे के गहरे दोस्त भी हैं. इसी दोस्ती का नतीजा है कि उन्होंने एनएससीएन (आईएम) के प्रमुख थुइंगलेंग मुइवा के समक्ष उनके पांच हजार हथियारबंद कैडरों को पुनर्वास योजना के तहत बीएसएफ में भर्ती कराने का आश्वासन दे डाला. सरकार की तरफ से नियुक्त मुख्य वार्ताकार आरएन रवि के इस आश्वासन पर जब विवाद गहराया, तब केंद्र सरकार को सामने आकर इससे इन्कार करना पड़ा. केंद्र ने इस खबर को गलत बता कर सिरे से पल्ला झाड़ लिया.

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) नगालैंड सरकार और वहां के आतंकी संगठनों की साठगांठ का आधिकारिक खुलासा कर चुकी है. नगालैंड के कई सरकारी अधिकारी एनआईए के हाथों गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं. यही वजह है कि एनएससीएन (आईएम) समेत अन्य कई आतंकी संगठन एनआईए को फूटी आंख नहीं देखना चाहते. राज्य के विकास की विभिन्न योजनाओं का धन सरकारी अधिकारियों के जरिए आतंकी संगठनों के पास पहुंचता है. एनआईए ने केंद्र सरकार को इस बात के सबूत दिए हैं कि नगालैंड सरकार आतंकी संगठनों को विकास के फंड डायवर्ट कर देती है. एनआईए ने नगालैंड में कई जगह छापामारी अभियान चलाए और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए, जिनसे यह खुलासा हुआ कि नगालैंड सरकार एनएससीएन (आईएम), खापलांग व कुछ अन्य गुटों को धन देती है. एनआईए ने आतंकी संगठनों को देने के लिए रखे कुछ सरकारी धन भी बरामद किए और कई सरकारी अधिकारियों से पूछताछ भी की. यह भी पता चला कि सरकारी मुलाजिमों के वेतन से 24 प्रतिशत अंश काट कर सीधे आतंकी संगठनों को पहुंचाया जाता है. सरकारी कर्मचारियों के वेतन से

24 प्रतिशत हिस्सा काटने का काम खुद सरकार करती है. नगालैंड से सरकारी कर्मचारियों से यह अघोषित टैक्स काटा जा रहा है. सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार और सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटकर उसे आतंकी संगठनों को दिए जाने के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान चलाने वाले सामाजिक संगठन 'अगैंस्ट करप्शन एंड अनऐबेटेड टैक्सेशन' (एसीयूटी) ने नगालैंड के कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराई और इस बारे में राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को पत्र लिखा. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. एसीयूटी ने केंद्र सरकार को बार-बार लिखा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन का जबरन काटा गया 'टैक्स' एनएससीएन (ईसाक-मुइवा) गुट वसूलता है, लेकिन इसका केंद्र सरकार पर कोई असर ही नहीं पड़ा. उल्टा संगठन के सदस्य एनएससीएन से जान बचाए फिर रहे हैं. एनआईए ने एनएससीएन खापलांग गुट से साठगांठ रखने वाले समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक तुलुला पोंजेन, भूसंसाधन विभाग के संयुक्त निदेशक (डीडीओ) एलेन्बा पैंगजुंग और उसी विभाग के कैशियर के. लाशितो शेकी को गिरफ्तार किया था. ये अधिकारी भी एनएससीएन के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से व्यापक पैमाने पर वसूली और गैर कानूनी टैक्स काटा करते थे. इन अधिकारियों के जरिए एनएससीएन समेत कई अन्य आतंकी संगठन धन कमा रहे थे. याद रहे कि नगालैंड के आतंकी संगठनों को सरकारी कर्मचारियों द्वारा दिए जा रहे धन के बारे में चौथी दुनिया ने पहले भी ध्यान दिलाया था.

कूकी और मैतेयी की कोई सुनने वाला नहीं

केंद्र से शांति समझौता करने वाले एनएससीएन (आईएम) ने पहले से ही घोषणा कर रखी है कि स्वायत्त नगालैंड राज्य आधिकारिक तौर पर ईसाई राज्य नहीं बल्कि धर्म-निरपेक्ष राज्य रहेगा, लेकिन अन्य धर्म के लोगों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा. अगर बृहत्तर नगालिम बना तो कूकी जनजाति जैसी कई जनजातियां बेमौत मारी जाएंगी. एनएससीएन (आईएम) के शीर्ष कमांडर अंथोनी सिमरे ने स्पष्ट कहा है कि कूकी जनजाति के लोग चाहें तो नगालैंड में रह सकते हैं, लेकिन उन्हें उनकी जमीन का स्वामित्व नहीं मिलेगा. मणिपुर के कूकी और मैतेयी समुदाय और नगा समुदाय के बीच जो खाई गहराई है, उसे राज्य और केंद्र ने और गहरा करने का काम किया है. यह आने वाले समय में भीषण हिंसक शक्ल लेने वाला है. कूकी जनजाति भी नगाओं की तरह ही नगालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय जैसे जिलों में बसी हुई है. कूकी जनजाति के लोग भी लंबे अर्से से अलग राज्य की मांग कर रहे हैं. मणिपुर में कूकी जनजाति की संख्या अधिक है. मणिपुर में छोटे बड़े करीब तीन दर्जन उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं. इनमें कूकर नेशनल आर्मी (केएनए), कूकी नेशनल फ्रंट (केएनएफ), कूकी लिबरेशन आर्मी (केएलए) और कूकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (केएनओ) प्रमुख हैं. दूसरे सक्रिय संगठनों में यूनाइटेड रेवोल्यूशनरी फ्रंट (यूआरएफ), पीपुल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पीआरपीके) और कांगलेई यावोल कानलुप (केवाईके) और कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी पखांगलाक्पा (केसीपी-पी) प्रमुख हैं. कूकी जनजाति के लोगों की पुरानी मांग है कि सेनापति जिले के सदर हिल्स अनुमंडल को एक अलग जिला बना दिया जाए जबकि नगा जनजाति के लोग इस मांग का शुरू से ही विरोध कर रहे हैं. कूकी जनजाति के संगठन कई बार अलग राज्य की मांग पर व्यापक आंदोलन कर चुके हैं. कूकी और नगाओं में परस्पर हिंसा भी खूब होती रही है. एनएससीएन (आईएम) और भारत सरकार के बीच हुए नगा शांति समझौते में कूकी जनजाति या ऐसी कई अन्य उपेक्षित जनजातियों के उत्थान और उनकी सुरक्षा के बारे में कोई विचार नहीं हुआ है.

हालांकि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने यह वादा किया है कि वे कुछ चमत्कार कर दिखाएंगे. जबकि सच यह है कि मणिपुर की मौजूदा राजनीति भी भारत सरकार और एनएससीएन (आईएम) के बीच हुए समझौते की परिधि में ही घूम रही है. मणिपुर के लोगों को आशंका है कि केंद्र सरकार ने समझौते में राज्य की क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किया है. मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से कहा है कि मणिपुर के लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है. मणिपुर के लोग इससे आशंकित हैं कि बृहत्तर नगालिम में कहीं मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के नगा बहुल क्षेत्रों का विलय न कर दिया जाए. बीरेन सिंह ने कहा है कि यह भारत सरकार और मणिपुर सरकार को तय करना है कि नगा बसावट के क्षेत्र उन्हें दिए जाएं या नहीं. मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि मैदानी क्षेत्र में रहने वाले मैतेयी समुदाय के लोगों और पहाड़ पर रहने वाले नगा और कूकी समुदाय के लोगों को करीब लाने का प्रयास किया जा रहा है. राज्य में तीन प्रमुख जनजातियां नागा, कूकी और मैतेयी हैं. मैतेयी लोग वैष्णव हिंदू धर्म को मानते हैं. लंबे समय से चले आ रहे नागा कूकी संघर्ष का खामियाजा मणिपुर के लोगों को भुगतना पड़ा है. बीरेन सिंह ने यह भी आश्वासन दिया है कि जेल में बंद यूनाइटेड नगा काउंसिल के नेता रिहा कर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि मणिपुर में म्यांमार और बांग्लादेश से काफी लोग आकर बस गए हैं. लिहाजा, अब इस बेरोकटोक आगमन को रोकने के लिए एक अधिनियम लाने की आवश्यकता है. यह कानून भविष्य में होने वाले आगमन को नियंत्रित करेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

कश्मीर में दिल्ली से गई टीम का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस

संवाद से ही निकलेगा कश्मीर का समाधान

हारून रेशी

'जम्मू कश्मीर: आगे का रास्ता' यह शीर्षक था श्रीनगर के मशहूर होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में आयोजित होने वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का. इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस नामक एक गैर सरकारी संस्था ने किया था. इसमें शामिल होने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता ओपी शाह, वरिष्ठ पत्रकार और चौथी दुनिया के एडिटर इन चीफ संतोष भारतीय, हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा के अलावा कई गणमान्य लोग दिल्ली से पहुंचे थे.

23 मई की दोपहर बाद, जब कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रतिभागी जमा होने लगे, तब सभी यह देख कर हैरान रह गए कि पहली बार कश्मीर की मुख्यधारा की पार्टियों के नेताओं के साथ अलगाववादियों के दो प्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे. हुर्रियत का प्रतिनिधित्व अब्दुल मजीद बांडे ने की, जबकि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के एक गुट के नेता जावेद अहमद मीर भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे. मुख्यधारा की पार्टियों नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस और कई अन्य राजनैतिक दलों के नेता कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए. आयोजकों ने सभी सहभागियों को उक्त विषय पर अपनी बात रखने का मौक़ा दिया. कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हमारे पास कश्मीर समस्या का कोई हल नहीं है, लेकिन इस तरह के कॉन्फ्रेंस आयोजित करने से आम राय बनाने और समस्या के अलग-अलग पहलुओं को समझने का मौक़ा मिलता है. बहरहाल, उन्होंने भाजपा की कश्मीर नीति और इस विषय पर भाजपा नेताओं के बयानों का खुलकर विरोध किया. उन्होंने कहा कि आज अमित शाह कह रहे हैं कि कश्मीर में केवल तीन जिले ही हिंसा प्रभावित हैं. मणिशंकर अय्यर का कहना था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज वायसराय का भी कुछ ऐसा ही कहना था कि समस्या भारत के कुछ जिलों में ही है. मणिशंकर अय्यर ने इस बात को स्वीकार किया कि कुछ नेशनल टीवी न्यूज़ चैनल कश्मीर के हालात की सही रिपोर्टिंग नहीं करते और इसकी वजह से यहां की जनता में काफी नाराज़गी और गुस्सा है. उन्होंने कहा कि कश्मीर समस्या का समाधान बातचीत से किया जा सकता है. यह कॉन्फ्रेंस इस बात का सबूत है कि बातचीत के लिए संबद्ध लोगों को एक जगह जमा किया जा सकता है. उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि वे पिछले 35 वर्षों में लगभग 35 बार पाकिस्तान जा चुके हैं. वे जानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अमन और शांति में यकीन रखते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के संबंध अच्छे हों. कई वक्ताओं ने अपने संबोधन में मणिशंकर अय्यर को याद दिलाया कि कांग्रेस ने कश्मीर समस्या को बिगाड़ने में एक अहम रोल अदा किया. इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकारों ने इसे हल करने में भी लापरवाही दिखाई. इन वक्ताओं के चुभते हुए शब्दों का जवाब देते हुए मणिशंकर अय्यर ने साफ तौर पर स्वीकार किया कि कांग्रेस ने कश्मीर में कई गलतियां की हैं. उनकी दलील थी कि यहां सभी पार्टियों से गलतियां हुई हैं. उन्होंने कहा कि इस हमाम में सभी नंगे हैं. अगर हम सबसे गलतियां नहीं हुई होतीं, तो आज कश्मीर की ये स्थिति नहीं होती.

कश्मीर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वालों ने कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज, कांग्रेस विधायक उस्मान मजीद, सीपीआई (एम) नेता मो. युसूफ तारीगामी, अमामी इत्तेहाद पार्टी के नेता इंजीनियर रशीद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आगा रूहुल्लाह, बीजेपी की नेता हिना भट्ट, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अब्दुल मजीद बांडे और जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जावेद अहमद मीर शामिल थे. उनके अलावा वकीलों, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए. अलगाववादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अब्दुल मजीद बांडे और जावेद अहमद मीर ने समस्या के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देते हुए कहा कि कश्मीर समस्या का समाधान किए बगैर इस क्षेत्र में स्थायी शांति बहाल नहीं की जा सकती है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधियों ने अपने संबोधन में नई दिल्ली से शिकायत की कि उसने कश्मीर में मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों, जिन्होंने कश्मीर और भारत के रिश्तों को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण किरदार अदा किया था, की भी विश्वसनीयता खत्म कर दी. इस संदर्भ में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कश्मीर की स्वायत्तता से संबंधित प्रस्ताव का जिक्र किया, जिसे विधानसभा ने दो तिहाई बहुमत से पास किया था और केंद्र सरकार ने उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था. इंजीनियर रशीद ने अपने स्वाभाविक अंदाज में कश्मीर की मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि नई दिल्ली ने अपनी नीतियों की वजह से सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज मौलवी उमर फारूक और मोहम्मद यासीन मलिक जैसे वरिष्ठ अलगाववादी नेताओं को हाशिए पर ला खड़ा किया. नतीजतन आज जाकिर मूसा जैसे उग्रपंथी कमांडर सामने आ गए हैं. उन्होंने कहा कि पहले तो हम आजादी चाहते थे, लेकिन अब यहां खिलाफत कायम करने की बातें हो रही हैं.

सीपीआई (एम) के नेता युसूफ तारीगामी ने अपने संबोधन में केंद्र की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज गृहमंत्री कह रहे हैं कि वो एक साल में कश्मीर समस्या का समाधान कर देंगे. लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो काम पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ और जो काम बीजेपी की अब तक तीन साल पुरानी सरकार नहीं कर सकी, वो काम अब एक साल में कैसे होगा? तारीगामी ने अपने संबोधन में कश्मीरियों का आह्वान किया कि वो भारत के बुद्धिजीवियों और अमनपसंद जनता को कश्मीर की वास्तविक स्थिति से रूबरू कराने की कोशिश करें. उनके मुताबिक कश्मीर समस्या के हल में यही एक बात रुकावट बनी हुई है कि हमने भारत के बुद्धिजीवी वर्ग तक यहां की सही स्थिति पहुंचाने की कोशिश नहीं की. उन्होंने कहा कि इस तरह के कॉन्फ्रेंसों के जरिए यह मकसद पूरा किया जा सकता है.

पत्रकार विनोद शर्मा ने अपने संबोधन में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि वहां जनता की आवाज को दबाया जा रहा है. वहां इस तरह के कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का विचार भी नहीं किया जा सकता है. कॉन्फ्रेंस के आयोजक ओपी शाह ने यकीन दिलाया कि वो घाटी के हालात और घटनाओं को देश में सेकुलर सोच रखने वाले लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे.

नई दिल्ली से आने वाले प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के गवर्नर एनएन वोहरा, अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, शब्बीर अहमद शाह और सैयद हसन बडगामी के अलावा कई विशिष्ट राजनैतिक शख्सियतों से मुलाकातें कीं. उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली की ये प्रबुद्ध हस्तियां देशभर में कश्मीर के बारे में जारी नकारात्मक प्रचार को तोड़ने में एक अहम भूमिका अदा करेंगी. नेशनल मीडिया पिछले कुछ समय से कश्मीर की वास्तविक स्थिति का चित्रण करने में अपनी जिम्मेदारियों से इंसाफ नहीं कर रहा है, इसलिए देश की सिविल सोसायटी की तरफ से उठाए गए इस तरह के कदम देश और कश्मीर के बीच बढ़ती खाई को पाटने में सहायक साबित हो सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड : वाडिया संस्थान की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं

एक और हादसे का ख़ामोशी से इंतज़ार कर रहे हैं लोग

चौथी दुनिया ब्यूरो

उत्तराखंड में 2013 की तबाही में कई सारी जलविद्युत परियोजनाएं बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और इसके साथ ही तबाही का पैमाना भी काफी बढ़ गया. जैसे, निर्माणाधीन तपोवन विष्णुगाड़ जलविद्युत परियोजना 16 जून, 2013 को हुई वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई. बांध बह गया और इससे आस-पास की सड़कों का काफी नुकसान हुआ. जेपी एसोसिएट्स की 400 मेगावाट विष्णु प्रयाग जलविद्युत परियोजना ने इस आपदा से फैली तबाही को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. माटू जनसंगठन के अनुसार इस परियोजना के कारण लंबागाड़ गांव को नुकसान हुआ. कह सकते हैं कि उत्तराखंड की 2013 की आपदा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा थी.

दूसरी तरफ, दो साल से वाडिया संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड की रिपोर्ट सरकार के पास पड़ी है. अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. जीवीके कंपनी की सहायक अलकनन्दा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन द्वारा अलकनंदा नदी पर बनाए गए श्रीनगर बांध से प्रभावित लोगों पर बांध कंपनी मौन और सरकार भी सुस्त दिखाई देती है. श्रीनगर बांध से विद्युतघर की ओर जाने वाली सैकड़ों किलोमीटर लम्बी खुली नहर जिसे पावर चैनल कहा जाता है, कई स्थानों से क्षतिग्रस्त है. 2015 में मानसून के बाद पावर चैनल के रिसाव के कारण इस चैनल और नदी के बीच रहने वाले मगंसू गांव, जिसमें ज्यादातर दलित परिवार रहते हैं, के निवासियों का जीवन खतरे में है. पूर्व विधायक श्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने जनदबाव के बाद वाडिया संस्थान को इस पर रिपोर्ट देने के लिए कहा था. रिपोर्ट 30 दिसंबर, 2015 को आ गई. सवाल है कि जीवीके कंपनी ने वाडिया संस्थान की इस रिपोर्ट पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? पूर्व विधायक श्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने 30 दिसंबर 2015 को रिपोर्ट आने के बाद सत्ता में रहने पर भी क्यों कार्रवाई नहीं की? मंत्री जी अब तक मौन क्यों रहे, जबकि रिपोर्ट के निष्कर्ष बहुत ही गंभीर हैं.

पानी के रिसाव से बनने वाला पोर प्रेशर (जो फंसा हुआ है) से पावर चैनल के बाहरी ढांचे पर असर पड़ेगा, जो आस पास के क्षेत्र में बाढ़ लाकर घरों और खेतों को डूबा सकता है. यह प्रभावित लोगों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है. दरार क्षेत्र में पावर चैनल का टूट जाना एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर ठीक से विचार किया जाना चाहिए. स्पष्ट रूप में पावर चैनल का तटबंध अस्थिर है, जिसका पता पानी का रिसाव होने से चलता है.

30-12-2015 की वाडिया संस्थान की रिपोर्ट में कहा गया है कि पावर चैनल के 200 मीटर विस्तृत क्षेत्र (प्रभावित रिसाव साइट) को वाडिया संस्थान देहरादून के संरचनात्मक भूवैज्ञानिकों के साथ परामर्श कर पुनः सुदृढ़ किया जाना चाहिए. इसके अलावा पावर चैनल के ढांचे की विस्तृत जांच करने की जरूरत है. उत्तराखंड में नई सरकार को आए हुए भी 75 दिन हो गए हैं. नहर व नदी के बीच में रहने वाले गांवों के लोग श्रीनगर बांध बनने के कारण पहले ही खेती का पानी, जमीन की उर्वरता, नदी का पानी और रास्ते खोकर कठिन जीवन जीने को मजबूर हैं. इनकी जमीन बांध कंपनी ने विभिन्न कार्यों के लिए बहुत कम दामों पर, सालाना समझौते की शर्त के साथ लीज़ पर ले ली थी. अब यह ज्यादातर जमीन बेकार हो चुकी है. चूंकि सिंचाई की पुरानी छोटी नहरें पावर चैनल के कारण बंद हो गई हैं, इसलिए काफी जमीनें अब बंजर हो गई हैं. पीने का पानी भी बांध कंपनी द्वारा अनियमित रूप से लोगों को मिल पाता है.

पावर चैनल (अलकनन्दा हाइड्रोपावर कॉर्पोरेशन, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड) के रिसाव पर यह रिपोर्ट कई सारे तथ्यों को सामने रखती है. यह रिपोर्ट सवाल उठाती है कि पावर चैनल की खुदाई प्रक्रिया के दौरान छिद्रित पाइप चैनल के नीचे क्यों डाले गए, रिसाव की घटना में पुराने चैनल की क्या भूमिका रही और कैसे पावर चैनल का निर्माण पुराने चैनल के झुके हुए हिस्से पर किया गया?

यह रिपोर्ट बताती है कि जांच के दौरान पावर चैनल 10 से अधिक स्थानों पर टूटा हुआ पाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में पानी का रिसाव हुआ. इसके साथ ही पावर चैनल के साथ नई दरारें भी विकसित हो रही हैं. पावर चैनल का 100 मीटर विस्तृत क्षेत्र भूमि की सतह के पास हो रहे रिसाव से प्रभावित है. इस क्षेत्र में तीन सक्रिय दरारें पहचान में आई हैं. रिसाव होते पानी की वजह से पावर चैनल के नीचे की ओर दवाब में वृद्धि होगी. इस रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है कि पावर चैनल का निचला हिस्सा सक्रिय नदी तल दरारों से प्रभावित हुआ है. इसलिए ये संरचना मजबूत की जानी चाहिए और इन तकनीकी खामियों की तत्काल मरम्मत की जानी चाहिए. इसे नजरअंदाज करना दोबारा इस खतरे को आमंत्रण देना होगा. पानी के रिसाव से बनने वाला पोर प्रेशर (जो फंसा हुआ है) से पावर चैनल के बाहरी ढांचे पर असर पड़ेगा, जो आस पास के क्षेत्र में बाढ़ लाकर घरों और खेतों को डूबा सकता है. यह प्रभावित लोगों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है. दरार क्षेत्र में पावर चैनल का टूट जाना एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर ठीक से विचार किया जाना चाहिए. स्पष्ट रूप में पावर चैनल का तटबंध अस्थिर है, जिसका पता पानी के रिसाव होने से चलता है. वाडिया संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि पावर चैनल के लगभग 200 मीटर विस्तृत क्षेत्र (प्रभावित रिसाव साइट) को वाडिया संस्थान देहरादून के संरचनात्मक भूवैज्ञानिकों के साथ परामर्श कर पुनः सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए. इसके अलावा पावर चैनल के ढांचे की विस्तृत जांच करने की भी जरूरत है. ■

feedback@chauthiduniya.com

फ्लोराइड युक्त पानी से असम में एक हज़ार से अधिक बच्चे फ्लोरोसिस की चपेट में

ज़हरीले पानी से विकलांग हो रहे बच्चे

चौथी दुनिया ब्यूरो

उपभोक्तावादी समाज ने अमृत समान पानी को इतना मैला कर दिया है कि अब ये प्यास तो बुझा रहा है, लेकिन साथ में दे रहा है धीमी मौत. उत्तर-पूर्वी राज्य असम के होजई में पिछले छह वर्षों में पांच वर्ष से कम उम्र के एक हजार से अधिक बच्चे फ्लोरोसिस की चपेट में आने से विकलांग हो गए हैं. हालत ये है कि राज्य में 11 जिलों में लोग फ्लोराइड युक्त पानी का सेवन करने को मजबूर हैं. असम के नागांव तथा होजई में कुल 485 गांव फ्लोराइड प्रदूषण के शिकार हैं. इन जिलों में 1 मिलीग्राम प्रति लीटर की स्वीकार्य सीमा से पानी में फ्लोराइड की मात्रा कई गुना अधिक है. एक आधिकारिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में साढ़े तीन लाख से अधिक लोग इस बीमारी के शिकार हैं. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस बीमारी से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय नहीं किया, तो ये संख्या और बढ़ सकती है.

असम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (पीएचडी) के अधिकारियों का कहना है कि पानी में फ्लोराइड मिलने से ये दूषित और जहरीला हो जाता है. इस पानी का सेवन करने से बच्चे अपंग हो जाते हैं. पानी में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है. ये बीमारी नवजात बच्चों को जल्दी अपनी चपेट में ले लेती है. इसका सबसे स्पष्ट लक्षण है, पैरों का टेढ़ा हो जाना या फिर दांतों का तिरछा होना. अब तक ये माना जाता रहा था कि फ्लोरोसिस शारीरिक रूप से विकसित युवाओं तथा प्रौढ़ों में अधिक होता है. लेकिन ये 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अधिक घातक होता है. इस आयु वर्ग के बच्चों का शरीर बढ़ रहा होता है. इस उम्र में उनके शरीर के ऊतक भी कोमल होते हैं, जिससे फ्लोरोसिस जल्द आक्रमण कर शरीर में घुसपैठ कर लेता है. गर्भवती मां अगर फ्लोराइड युक्त जल का सेवन करती है, तो गर्भ में बढ़ रहे शिशु के लिए भी यह बहुत हानिकारक होता है. आमतौर पर बच्चे 2-3 वर्ष की उम्र पार करते-करते अपंग और रोगग्रस्त हो जाते हैं. साधारण पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने पर मानव शरीर में फ्लोराइड अस्थियों से हाइड्रॉक्साइड को हटाकर खुद जमा हो जाता है और अस्थि फ्लोरोसिस को जन्म देता है. सबसे हैरानी की बात तो यह है कि अस्थि फ्लोरोसिस को शुरुआती दौर में पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है. फ्लोरोसिस की चपेट में आकर मनुष्य असमय वृद्ध होने लगता है. उसकी कमर झुकने लगती है और वह चलने से लाचार हो जाता है. कभी-कभी तो वह गूंगेपन का भी शिकार हो जाता है.

देश के फ्लोरोसिस प्रभावित ज़िलों के नाम

आंध्र प्रदेश	16 :	कुडप्पा, हैदराबाद, कृष्णा, मेडक, वारंगल, अनन्तपुर, करनूल, करीमनगर, नालगोंडा, प्रकाशम, चित्तूर, गुंटूर, खम्मम, महबूब नगर, नेल्लौर, रंगारेड्डी,
असम	3 :	कार्बी आंगलूंग, नौगांव, कामरूप
बिहार	6 :	डाल्टनगंज, गया, रोहतास, गोपालगंज, पश्चिम चम्पारण, मुंगेर
हरियाणा	12 :	रेवाड़ी, फरीदाबाद, करनाल, सोनीपत, जिंद, गुड़गांव, महेन्द्रगढ़, रोहतक, कुरुक्षेत्र, कैथल, भिवानी, सिरसा
झारखंड	4 :	पाकुर, पलामू, साहेबगंज, गिरीडीह
मध्य प्रदेश	14 :	शिवपुरी, झाबुआ, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, धार, विदिशा, सिवनी, सिहोर, रायसेन, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, ग्वालियर
महाराष्ट्र	10 :	भण्डारा, चन्द्रपुर, बुलधाना, जलगांव, नागपुर, अकोला, अमरावती, नांदेड़, सोलापुर, यवतमाल
ओड़ीशा	18 :	अंगुल, धानकनाल, बौद्ध, नयागढ़, पुरी, बालासोर, भद्रक, बालंगीर, गंजम, जगत सिंहपुर, जाजपुर, कालाहांडी, केवनझार, खुर्दा, कोरापुर, मयुरभंज, पुलवानी, रायगढ़
पंजाब	17 :	मांसा, फरीदकोट, भटिंडा, मुक्तसर, मोगा, संगरूर, फीरोजपुर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, रोपण, जालंधर, फतेहगढ़ साहिब, कपूरथला, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर
राजस्थान	32 :	भिलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, टोंकनगर, जालौर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर, सीकर, अलवर, चुरू, भरतपुर, झुंझनु, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, राजसमन्द, बांसपाड़ा, डुंगरपुर, बिकानेर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बुंदी, झालावाड़, गंगानगर, बाटन, हनुमानगढ़,
उत्तर प्रदेश	7 :	वाराणसी, कन्नौज, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, रायबरेली, उन्नाव, सोनभद्र
पश्चिम बंगाल	4 :	वीरभूम, बांकुड़ा, वर्धमान, पुरुलिया

असम में पानी के जहरीले होने की जानकारी सबसे पहले पीएचईडी विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता एबी पॉल ने लगाई थी. उन्होंने बताया कि 1999 में वे कार्बी आंगलोंग जिले के तेकेलागुइन गांव में गए थे. इस दौरान उन्होंने एक लड़की को देखा जिसके दांतों की संरचना अजीब और धब्बेदार थी. अन्य बच्चों में भी डेंटल और स्केलेटल फ्लोरोसिस के लक्षण दिखे. जांच करने पर पता चला कि पानी में फ्लोराइड का स्तर 5-23 मिलीग्राम प्रति लीटर तक है. असम पीएचईडी के पूर्व अतिरिक्त मुख्य अभियंता नजीबुद्दीन अहमद के अनुसार, कुछ साल पहले होजई जिले में पांच साल से कम उम्र के एक हजार से अधिक बच्चे फ्लोराइड प्रदूषण की चपेट में आने से अपंग हो गए.

वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ वर्षों में भूजल के उपयोग में वृद्धि हुई है, जिसके कारण फ्लोराइड प्रदूषण का खतरा और बढ़ गया है. यह स्थिति केवल होजई की ही नहीं, बल्कि राज्य में अन्य जगहों की भी है. नजीबुद्दीन अहमद कहते हैं, पहले अपनी दैनिक जरूरतों के लिए लोग सतही जल संसाधनों पर अधिक निर्भर थे. आज कुल आबादी के मात्र 15 फीसदी लोग ही सतह के जल पर निर्भर हैं. बाकी 85 फीसदी लोग भूमि के अंदर के जल का उपयोग करते हैं. जल स्तर में गिरावट आने से भूजल में फ्लोराइड जैसी खनिजों की मात्रा बढ़ गई है. एन्वायरमेंट कंजर्वेशन सेंटर के सचिव धरानी सैकिया बताते हैं कि फ्लोराइड पानी में पाए जाने वाला एक प्राकृतिक खनिज है. जल में इसकी मात्रा बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं. जलवायु में परिवर्तन होने से भी ऐसा हो रहा है. लंबे समय से सूखा पड़ने से पानी जमीन के अंदर कम जा रहा है. इसके अलावा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से यह समस्या और विकराल हुई है. इन कारणों से भूजल की पुन: पूर्ति कम हो रही है. उन्होंने बताया कि जिस साल खूब बारिश होती है, उस साल जल में फ्लोराइड की मात्रा सामान्य रहती है. लेकिन बारिश कम होने की वजह से जल में फ्लोराइड का स्तर बढ़ जाता है. इसके अलावा खेती में फॉस्फेट और सल्फेट भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पानी में फ्लोराइड की मात्रा दिनोंदिन बढ़ रही है.

पानी के जहरीले होने का एक बड़ा कारण बोरिंग के लिए जमीन की खुदाई भी है. खुदाई के दौरान चट्टानें टूटकर भूजल में मिल जाती हैं. ये चट्टानें खनिजों से भरपूर होती हैं इसलिए पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि गुवाहाटी में पहले 150-200 फीट पर पानी निकल आता था, लेकिन पानी के अत्यधिक दोहन के कारण भूजल अब 250-300 फीट नीचे चला गया है.

भारत में फ्लोरोसिस सर्वप्रथम 1930 के आस-पास आंध्र प्रदेश में देखा गया था. छह करोड़ भारतीय फ्लोरोसिस की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें बच्चों और महिलाओं की संख्या साठ लाख है. 20 राज्यों में इसके प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखते हैं. इनमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात व राजस्थान में तो यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है. राजस्थान के कई भागों में फ्लोराइड की मात्रा पेयजल में 24-41 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पाई गई है. देखा गया है कि गरीब व कुपोषित ग्रामीणों में यह बीमारी बहुत ही जल्दी पनप जाती है. ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति चिकित्सक वर्ग की उदासीनता गांवों में फ्लोरोसिस की दिनों-दिन बढ़ोत्तरी में एक अहम कारण बन रही है.

समस्या से राहत के लिए पीएचईडी ने असम में प्रदूषित जल युक्त ट्यूबवेलों को लाल रंग से रंग दिया है, ताकि लोग पीने या खाना पकाने के लिए इस पानी का इस्तेमाल न करें. करबी अंगलांग, नागौन और कामरूप जिलों में सुरक्षित पानी के लिए रिंग कुएं का निर्माण किया गया है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी यह स्वीकार किया है कि फ्लोराइड के अत्यधिक इस्तेमाल से शरीर की हड्डियों में क्षति की भरपाई संभव नहीं है. सैकिया बताते हैं कि इस समस्या का अंतिम समाधान प्रकृति की ओर लौटने में है. हम निर्माण और कृषि के लिए जल निकायों को समाप्त कर रहे हैं. जबकि सतह जल थोड़े बहुत उपचार के बाद मनुष्य के लिए सबसे सुरक्षित है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सूचना के सिपाहियों का

क़ब्रगाह बनता जा रहा है ओड़ीशा

निरंजन मिश्रा

जिस सूचना के अधिकार (आरटीआई) को सुशासन का सशक्त हथियार बताया जाता है, वही अब आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए जानलेवा बनता जा रहा है. अप्रैल 2016 में मिले एक आरटीआई जवाब में बताया गया था कि ओड़ीशा में अब तक 12 आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं. आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले के मामले में तब ओड़ीशा का स्थान आठवां था. तब 63 मामलों के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर था. लेकिन हाल के दिनों में आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों ने इस मामले में ओड़ीशा को शीर्ष के राज्यों में शामिल कर दिया है. अप्रैल के अंतिम सप्ताह से अब तक 5 आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा चुके हैं. लेकिन किसी भी मामले में अब तक पुलिसिया कार्रवाई रंग लाती दिख नहीं रही है. ऐसा भी नहीं है कि ऐसे हमलों के कारणों से पुलिस अनभिज्ञ है. आरटीआई के जरिए सामने आए विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के घपले-घोटाले आरटीआई कार्यकर्ताओं की जान के दुश्मन बन रहे हैं. कई विभागों में पैसों की हेराफेरी में सफेदपोशों के नाम सामने आए हैं. इसलिए अब वे ऐसी आवाजों को हमेशा के लिए शांत करने पर तुले हुए हैं. हाल के दिनों में जिन आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं, उनमें से किसी ने वन विभाग में घोटाले का पर्दाफाश किया था, तो किसी ने निजी संस्थान द्वारा सरकारी जमीन के अतिक्रमण का खुलासा किया था.

श्रीकांत पकल, कोर बोर्ड मेंबर, ओड़ीशा सूचना अधिकार अभियान

स्थानीय कार्यकर्ताओं का संगठन ओड़ीशा सूचना अधिकार अभियान इस मामले को लेकर आवाज उठाता रहा है. इस संगठन की ओर से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी चिट्ठी लिखकर इस मामले से अवगत कराया गया है. लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई होती दिख नहीं रही है. ओड़ीशा सूचना अधिकार अभियान के कोर बोर्ड मेंबर और आरटीआई कार्यकर्ता श्रीकांत पकल का कहना है कि आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले दुर्भाग्यपूर्ण हैं. सूचना का अधिकार कानून हमें संविधान की तरफ से मिला है और हम इसके जरिए भ्रष्टाचार के मामले उजागर करते रहेंगे.

आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हाल में हुए हमले

सुभाष महापात्रा- 24 अप्रैल को तब इस युवा आरटीआई कार्यकर्ता पर हमला हुआ, जब वे शाम में अपने घर लौट रहे थे. हमला करने वाले बाइकर्स ने बंदुक की नोक पर इन्हें धमकी भी दी कि अगर ये कलिंगा इंस्टीच्युट ऑफ इंडस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी (केआईआईटी) के अच्युत सामंत के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हैं, तो इन्हें जान से मार दिया जाएगा. इस घटना के बाद सुभाष महापात्रा ने खांडिगरी थाने में अच्युत सामंत के खिलाफ केस दर्ज कराया. हालांकि अब तक उस केस पर पुलिस कार्रवाई शुरू नहीं हुई है. गौरतलब है कि सुभाष महापात्रा की आरटीआई से ही खुलासा हुआ था कि पटिया, भुवनेश्वर स्थित केआईआईटी ने वन विभाग की 18 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है. इस खुलासे के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ओड़ीशा सरकार को केआईआईटी से जमीन वापस लेने का आदेश दिया था.

प्रदीप प्रधान- युवा आरटीआई कार्यकर्ता प्रदीप प्रधान ओडीशा सूचना अधिकार अभियान के राज्य संयोजक भी हैं. इनके आरटीआई के माध्यम से कई सरकारी योजनाओं में अनियमितताएं उजागर हुई हैं. यही कारण है कि कुछ लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं. बीते 3 मई को भुवनेश्वर स्थित इनके घर के ठीक सामने कुछ लोग इनकी बहन के शरीर पर पेट्रोल फेंक कर भाग गए. घटनास्थल से मात्र 50 मीटर की दूरी पर मैत्री विहार पुलिस पोस्ट है, लेकिन अपराधी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके. घटना के बाद प्रदीप प्रधान ने एफआईआर दर्ज कराया. अब तक अपराधी पकड़ नहीं जा सके हैं. हालांकि प्रशासन की तरफ से प्रदीप प्रधान के परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया कराया गया है.

शंकर पानीग्रही- इनके द्वारा मांगे गए आरटीआई जवाब से ओड़ीशा सरकार की कई सोशल वेलफेयर स्कीम्स में सरकारी पैसों की हेराफेरी का खुलासा हुआ था. शंकर पानीग्रही आरटीआई के जरिए भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने के साथ-साथ नौजवानों को भी सूचना के अधिकार के उपयोग की ट्रेनिंग देते हैं. वे ओड़ीशा सूचना अधिकार अभियान के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं. 10 मई को रात 08:02 बजे उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले ने बिना कुछ पूछे भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी. उसने शंकर को जान से मारने और पत्नी के रेप की भी धमकी दी. शंकर ने उस कॉल को रिकॉर्ड कर लिया और उसी के आधार पर 12 मई को बोलनगीर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया. कार्रवाई जारी है, लेकिन अब तक अपराधी पकड़े नहीं जा चुके हैं.

केशब महाकुड़- दिव्यांग होने के बावजूद केशव महाकुड़ की भ्रष्टाचार से लड़ने की प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं है. पिछले 12 मई को वे डीएफओ नयागढ़ से संबंधित वन विभाग के एक भ्रष्टाचार के मामले की शिकायत करने भुवनेश्वर गए थे. वहां उन्होंने वन पर्यावरण मंत्री विजय राउत्रे से मिलकर उन्हें भ्रष्टाचार के मामले से अवगत कराया. भ्रष्टाचार के इस मामले को उजागर करने को लेकर मंत्री जी ने उनकी सराहना भी की. केशव जब वहां से लौट रहे थे, तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उनका ऑटो रोका और बुरी तरह से उनकी पिटाई की. केशव किसी भी तरह से पुलिस स्टेशन पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई. हालांकि अब तक उनके कंप्लेन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. पिछले साल भी केशव पर अज्ञात लोगों ने हमला किया था, जिसमें वे बुरी तरह से जख्मी हो गए थे. तब उन्हें पूरा एक महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ा था. गौरतलब है कि केशव ने वन विभाग से जुड़े करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के एक मामले को लेकर डीएफओ नयागढ़ के कार्यालय में आरटीआई डाला था. इस भ्रष्टाचार के मामले में स्थानीय बीजद नेता की भी सहभागिता सामने आई थी. इस मामले के सामने आने के बाद से ही केशव पर हमले होने लगे. केशव का ये मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी दर्ज हुआ है.

प्रियव्रत गड़नाईक- अवैध पत्थर खनन और उससे अवैध वसूली को लेकर प्रियव्रत गड़नाईक ने आरटीआई दाखिल की थी, लेकिन लोक सूचना अधिकारी ने उन्हें जवाब देने से मना कर दिया. इसके बाद उन्होंने ओड़ापाड़ा तहसील में पिटीशन दायर किया. पिछले साल 16 जून को जब वे ओड़ापाड़ा तहसील से अपने पिटीशन की पहली सुनवाई के बाद लौट रहे थे, तभी एनएच-55 पर ढेंकानाल जिले में 6 अज्ञात लोगों ने उनपर हमला कर दिया और उन्हें पास की नदी में धक्का दे दिया. प्रियव्रत के हाथ और पैर की हड्डियां टूट गईं. इसके बाद लंबे समय तक उन्हें बेडरेस्ट में रहना पड़ा. हमले के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. आरोपी पकड़े भी गए, लेकिन पुलिस ने कोर्ट में केस को मजबूती से नहीं रखा और आरोपी बेल पर रिहा हो गए. प्रियव्रत अब भी इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

छत्तीसगढ़ में सियासत की 'भू' चाल

ओमप्रभा

छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों एक भूचाल के दौर से गुजर रही है. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और भाजपा पर लगातार हमलावर रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल खुद व्यक्तिगत हमलों से घिर गए हैं. उनपर हो रहा ये हमला दो तरफा है. एक तरफ विरोधी हैं, तो दूसरी तरफ समाज का वो गरीब और पिछड़ा तबका है, जिसकी आवाज उठाने का दावा कांग्रेस करती है.

दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से भूपेश के खिलाफ दो शिकायतों की चर्चा होती रही है. भिलाई की मानसरोवर परियोजना में ईडब्ल्यूएस के 6 भूखंडों को जोड़कर बने उनके घर पर विरोधी सवाल उठाते रहे हैं. एक दूसरा मामला है, भूमिहीनों को आवंटित जमीन पर कब्जे का. दुर्ग की पाटन तहसील के भुपेश के पुस्तैनी गांव कुरुदडीह में भूमिहीनों को सरकारी की तरफ से जमीन आवंटित की गई थी. विरोधी ये आरोप लगाते हैं कि उन जमीनों पर भुपेश बघेल ने कब्जा कर रखा है. ईडब्ल्यूएस के भूखंडों को जोड़कर घर बनाए जाने के मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी. मामले की औपचारिक जांच के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भूखंडों को जोड़कर बड़ा मकान बनाने को गैरकानूनी मानते हुए एफआईआर की सिफारिश कर दी. इसके बाद आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा में भूपेश की मां और पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया. भूमिहीनों की जमीन पर कब्जा करने के मामले में राजस्व विभाग ने जांच के बाद जमीन को सरकारी बता दिया. दोनों मामलों में भूपेश खुंदक की लड़ाई पर उतर आए. वे अपनी मां और पत्नी को साथ लेकर ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंच गए और तीन घंटे तक अफसरों को

एक तरफ, किसानों की समस्या हल करने के नाम पर भूपेश बघेल ने सीधे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से मिलकर उन्हें जमीन देने की मांग कर दी. वहीं दूसरी तरफ, जोगी कांग्रेस ने भूपेश से पहले ही किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से मिलवा दिया. बघेल से मुलाकात के दौरान सीएम ने कहा कि जितनी भी घास जमीन है, उस पर तार का घेराव किया जाएगा. परीक्षण कराने व राजस्व विभाग से रिपोर्ट मिलने के बाद इस पर निर्णय होगा. 19 मई को तहसील दफ्तर में पेशी है. पहले तो उसके कब्जे का निराकरण होगा.

बयान लेने की चुनौती देते रहे. हालांकि किसी ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की. वे लौट आए, लेकिन सरकार को संदेश दे दिया. उसके अगले दिन उन्होंने जमीन के मुद्दे पर दांव खेला. उन्होंने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा. सीएम ने उन्हें समय दिया, दोनों की मुलाकात भी हुई. इधर रमण सिंह अपने बयानों से उन्हें आम फरियादियों की तरह दिखाने की कोशिश करते रहे. पिछले 14 वर्षों में यह भूपेश और रमन सिंह की पहली औपचारिक मुलाकात थी. इस बार भूपेश ने गेंद सरकार के पाले में डाल दिया. मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने भी दो टूक कह दिया कि वो सरकारी जमीन है और किसान उसका पट्टा मांग रहे हैं, सरकार उन्हें पट्टा दे दे. भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि अगर वहां उनकी जमीन है, तो उसे भी किसानों को दे दिया जाए. हालांकि सरकार इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है. राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने उसी समय स्पष्ट कर दिया कि सरकार पहले विवादित जमीन को अपने कब्जे में लेगी उसके बाद तय होगा कि उसका क्या किया जाना है. राजस्व अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा नियमों के तहत वो जमीन किसानों को नहीं दी जा सकती है.

क्या है कुरुदडीह ज़मीन विवाद

दुर्ग जिले की पाटन तहसील कुरुदडीह गांव की 77 एकड़ जमीन पर बघेल परिवार का कब्जा है. इसमें करीब 55 एकड़ कास्त भूमि है. आरोप है कि ये जमीन बघेल परिवार ने अपनी मालगुजारी जमीन में शामिल कर ली है. भूपेश बघेल स्थानीय विधायक होने के साथ ही पीसीसी चीफ भी हैं. किसानों का कहना है कि बघेल के विधायक बनने के बाद उनके परिवार ने हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया. वहीं, भूपेश बघेल इन आरोपों को गलत बताते हैं. उनका कहना है कि मेरे कब्जे में कोई जमीन नहीं है.

विवाद या सियासत

कुरुदडीह के किसानों की आड़ में भाजपा, कांग्रेस और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जोगी कांग्रेस) आपस में सियासी शह-मात का खेल खेल रही हैं. एक तरफ, किसानों की समस्या हल करने के नाम पर भूपेश बघेल ने सीधे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से मिलकर उन्हें जमीन देने की मांग कर दी. वहीं दूसरी तरफ, जोगी कांग्रेस ने भूपेश से पहले ही किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से मिलवा दिया. बघेल से मुलाकात के दौरान सीएम ने कहा कि जितनी भी घास जमीन है, उस पर तार का घेराव किया जाएगा. परीक्षण कराने व राजस्व विभाग से रिपोर्ट मिलने के बाद इस पर निर्णय होगा. 19 मई को तहसील दफ्तर में पेशी है. पहले तो उसके कब्जे का निराकरण होगा. बात यहीं खत्म नहीं हुई. मुख्यमंत्री और बघेल की मुलाकात के बाद राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडे स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि कुरुदडीह की जमीन पर हुए बेजा कब्जे को हटाकर सरकार जमीन को अपने कब्जे में लेगी. गौर करने वाली बात ये है कि रमण सिंह और भुपेश बघेल की मुलाकात में वे भी मौजूद थे. मुलाकात के बारे में बताते हुए पाण्डेय ने कहा, बघेल ने सीएम से कहा कि सरकार उनके गांव कुरुदडीह की शासकीय जमीन का पट्टा वहां के किसानों को दे दे. इस मामले में सरकार पर राजनीति करने के भूपेश के आरोपों पर पाण्डेय का कहना था कि इसमें राजनीति वाली कोई बात नहीं है. यदि पट्टा दिया जाने लायक रहता, तो 2003 के पहले ही दे दिया गया होता. ये भूपेश बघेल के गांव का मामला है. सरकार के पास जब जमीन आ जाएगी, तब इस पर विचार किया जाएगा कि क्या करना है.

ईओडब्लू के एडीजी पर बघेल का पलटवार

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के खिलाफ ईओडब्लू में मामला दर्ज होते ही बघेल ने जमीन आवंटन के राजनीतिक विवाद में ईओडब्लू के एडीजी मुकेश गुप्ता को भी घसीट लिया. भूपेश ने गुप्ता पर आरोप लगाया कि उन्होंने स्पेशल एरिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (साडा) के सदस्य के तौर पर प्लॉट लेने में गड़बड़ी की है. उन्होंने कहा कि साडा के भंग होने के बाद गुप्ता ने वहां सस्ते दर पर प्लॉट की रजिस्ट्री कराई और बाद में उसे 42 लाख रुपए में बेच दिया. गुप्त पर उनका ये आरोप पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि गुप्ता ने ईओडब्लू में इसी तरह के जमीन आवंटन के 22 साल पुराने मामले में भूपेश के खिलाफ केस दर्ज किया है.

दिल्ली तक पहुंची ज़मीन विवाद की आंच

कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी से फ्री हैंड मिलने के बाद भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस को अपने अनुसार मिशन-2018 के लिए एकजुट करने और भाजपा से मुकाबले के लिए तैयार करने में जुटे हुए हैं. इस बीच विरोधियों ने इस जमीन विवाद के जरिए उन्हें सियासी तौर पर घेरने की कोशिश शुरू कर दी है. इस बहाने पार्टी के अंदर के कुछ लोगों को भी मौका मिल गया और उन्होंने दिल्ली दरबार में भूपेश की शिकायत कर दी. लिहाजा, भूपेश के लिए दिल्ली से बुलावा आ गया. इसे कुछ नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की कवायद के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया. हालांकि, दिल्ली दरबार की तरफ से तत्काल कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन भविष्य में भी कांग्रेस आलाकमान का भरोसा भूपेश पर बना रहता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी.■

feedback@chauthiduniya.com

महंगाई का कारण राजनीति, मजबूरी नहीं

ए यू आसिफ

मोदी सरकार के तीन साल में महंगाई इस हद तक बढ़ी है कि सरकारी आंकड़े भी इसका साथ नहीं दे पा रहे हैं. खाद्य सामग्रियों की मूल्य वृद्धि ने तो आम जनता का बुरा हाल कर दिया है. गत तीन वर्षों में चना दाल का मूल्य 75 प्रतिशत बढ़ गया है. मई 2014 में ये रिटेल में 49 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता था, जो अब 86 रुपए प्रति किलो बिक रहा है. उड़द दाल के मूल्य में भी 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. यह तीन वर्ष पूर्व 68 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा था, वहीं अब 99 रुपए प्रति किलो मिल रहा है. अरहर दाल के मूल्य में भी 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

ये हाल तब है, जब हम पूरे तीन साल की औसत मूल्य वृद्धि की बात कर रहे हैं. बीच के समय में कई बार खाद्य पदार्थों के मूल्य में और भी उछाल आया है. उदाहरण के तौर पर, सितम्बर-नवंबर 2015 में अरहर दाल का मूल्य 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था. एक वर्ष पूर्व चीनी 50 रुपए प्रतिकिलो बिक रही थी. मोदी के सत्ता में आने के पहले वर्ष में प्याज 100 रुपए प्रति किलो बिक रही थी. इसीप्रकार अक्टूबर 2015 में सरसो तेल का दाम 150 रुपए प्रति किलो से भी ऊपर चला गया था.

अब हम भारत द्वारा आयात किए जाने वाले विभिन्न क्रुड ऑयल के मूल्यों पर एक नजर डालते हैं. ये जानना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनका मासिक औसत मूल्य क्या है और आयात के बाद भारत में ये किस दर पर बिक रहे हैं. हम ये भी देखेंगे कि गत वर्षों में इनके मूल्य में क्या अंतर आया है. मोदी के सत्ता में आने के बाद जून 2014 तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रुड ऑयल की कीमत 109 डॉलर प्रति बैरल थी. जनवरी 2015 में इसमें भारी कमी देखी गई और क्रुड ऑयल की कीमत कम हो कर 47 डॉलर प्रति बैरल हो गई. हालांकि मई 2015 में इसके दाम में फिर बढ़ोतरी हुई और ये 64 डॉलर प्रति बैरल हो गया. जनवरी 2016 में एक बार फिर इसके दाम में भारी कमी हुई और ये 28 डॉलर प्रति बैरल पर बिकने लगा. तब से लेकर अब तक के कई उतार-चढ़ाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अभी ये लगभग 50 डॉलर प्रति बैरल के भाव से बिक रहा है.

जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रुड ऑयल के इस कम मूल्य का सकारात्मक प्रभाव भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मूल्य पर भी पड़ना चाहिए था और इनके दामों में कमी होनी चाहिए थी. लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमारे यहां इस मामले में उल्टी गंगा बह रही है. ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल अर्थात डीजल की बात करें, तो इसका मूल्य 56.71 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 59.02 रुपए प्रति लीटर हो गया है. जबकि मुंबई में पेट्रोल 73-74 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है. गौर करने वाली बात ये भी है कि इन तीन वर्षों में पीडीएस किरासन तेल एवं सब्सीडाइज्ड एलपीजी की कीमतों में भी उछाल आया है. हालांकि ये पेट्रोल-डिजल के मुकाबले थोड़ा कम है. किरासन तेल 14.96 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 18.77 प्रति लीटर हो गया है, वहीं एलपीजी का मूल्य 414 रुपए प्रति सिलिंडर से बढ़कर 443 रुपए प्रति सिलिंडर हो गया है.

मई 2014 में ये रिटेल में 49 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता था, जो अब 86 रुपए प्रति किलो बिक रहा है. उड़द दाल के मूल्य में भी 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. यह तीन वर्ष पूर्व 68 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा था, वहीं अब 99 रुपए प्रति किलो मिल रहा है. अरहर दाल के मूल्य में भी 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

अब प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ऐसा क्यों हुआ? दरअसल, मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कम कीमतों का फायदा आम लोगों को देने के बजाय अपने राजकोष को मजबूत करना बेहतर समझा. इसलिए दाम में कमी के बाद टैक्स वृद्धि हुई. इन सबके कारण केंद्र सरकार को जबरदस्त फायदा हुआ. नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से पहले 2013-2014 में केंद्र सरकार को तेल से आने वाले टैक्स के जरिए 1.06 लाख करोड़ रुपए मिले थे, जो अगले वित्त वर्ष में बढ़कर 2.1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया. उल्लेखनीय है कि टैक्स से वसूली गई ये राशि दो वर्ष पूर्व इस मद में वसूली गई राशि से दोगुनी थी. इसका मतलब साफ है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के नाम पर एक भारतीय हाउस होल्ड से सालाना 4250 रुपए अधिक वसूल किया. ज्ञात रहे कि ये सिर्फ वही राशि है, जो इन प्रोडक्ट्स पर टैक्स के रूप में सीधे वसूली गई है. यह भी एक कारण है आम भारतीयों पर महंगाई के बोझ का.

तीन वर्षों के दौरान तमाम वस्तुओं की कीमतों में हुई ये बेतहासा वृद्धि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वादे को झुठला रही है, जो उन्होंने चुनाव से पहले अच्छे दिन के आकर्षक नारे के साथ किया था. उन्होंने महंगाई को लेकर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया था और कहा था कि भाजपा की सरकार आई, तो महंगाई को काबू में किया जाएगा. लेकिन हुआ इसका उल्टा. एक तो महंगाई बढ़ती गई और उसके बाद रही-सही कसर नोटबंदी ने पूरी कर दी.■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड

डायन बिसाही अंधविश्वास की वजह से हत्याओं का दौर जारी

डायन बताकर महिला एवं उसके परिवार को प्रताड़ित करने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है. हद तो तब हो जाती है जब डायन बताकर महिला को मल-मूत्र पिलाया जाता है. निर्वस्त्र कर उसका सामूहिक बलात्कार किया जाता है. एक से एक अमानवीय घटना को सुन कर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन डायन के नाम पर हत्याओं का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है.

प्रशान्त शरण

डायन बिसाही के नाम पर झारखंड के गांवों की औरतें अमानवीय अत्याचार की शिकार हो रही हैं. डायन होने का आरोप लगाकर औरतों को मल-मूत्र पिलाने, नंगा कर गांवों में घुमाने और उनके साथ सामूहिक बलात्कार करने जैसी खबरें झारखंड में आए दिन सुनने को मिल रही हैं. डायन के नाम पर जघन्य हत्या को अंजाम दिया जा रहा है. झारखंड गठन के बाद से अब तक डायन होने का आरोप लगाकर लगभग 1,600 महिलाओं की हत्या की जा चुकी है. केवल 2016 में ही डायन होने के संदेह में 54 महिलाओं की हत्या कर दी गई. डायन के नाम पर औरतों के साथ ज्यादती की तो कई कहानियां हैं, लेकिन हाल में एक विधवा महिला के साथ जो घटना घटित हुई, उसने पूरे मानवता को शर्मसार कर दिया. वृद्ध महिला को डायन बताकर उसके पूरे शरीर से सिरींज के जरिए खून निकाला गया. इतना ही नहीं, उसके नाजुक अंगों में सुई चुभोया गया. राज्य में इसके खिलाफ सख्त कानून बने हैं और सरकार से लेकर अदालत तक इस मुद्दे पर संवेदनशील है, लेकिन फिर भी किसी औरत को डायन बताकर उसकी हत्या कर देना आम बात है. झारखंड के लिए ये कलंक है, लेकिन इस मुद्दे पर समाज अभी तक जागरूक नहीं हो सका है. इस गंभीर समस्या के निराकरण के लिए कई लोग और कई संस्थाएं लड़ाई लड़ रही हैं. लेकिन ये कुप्रथा गांवों में इस तरह से फैली हुई है कि इतनी जल्दी इससे छुटकारा संभव नहीं लग रहा. तमाम तरह की योजनाओं और कई संस्थाओं के काम करने के बावजूद इस कुप्रथा को लोगों के दिमाग से नहीं निकाला जा सका है. लोग इसे ही सही मानकर जी रहे हैं. लेकिन डायन के नाम पर औरतों के साथ जुल्म करने वाले लोग समझ नहीं पा रहे कि वे ऐसा कर के इस सामाजिक बिमारी को और बढ़ावा ही दे रहे हैं.

पलामू के एक गांव में सुबह-सुबह एक भैंस ने जब दम तोड़ा, तो उसके मालिक को लगा कि उसके घर के बगल में रहने वाले दंपति ने तंत्र-मंत्र के सहारे उसे मार डाला. इसके बाद भैंस वाले ने उस पूरे परिवार को घेर लिया और डायन होने के आरोप में महिला और उसके पति को फरसा से मारकर उनकी नृशंस हत्या कर दी. ऐसी ही एक घटना रांची से सटे मांडर गांव में भी घटित हुई. यहां एक नवजात की मौत के आरोप में बगल की एक महिला को डायन बताकर मार दिया गया. बच्चे के घरवालों ने कहा कि वो महिला डायन थी और उसने ही बच्चे को नजर लगा दी, जिससे बच्चे की मौत हो गई. जबकि सच्चाई ये थी कि नवजात की मौत बीमारी से हुई थी. स्थानीय डॉक्टर ने भी इसकी पुष्टि की.

हजारीबाग के कर्णपुरा में तो इसप्रकार की एक दिल दहलाने वाली घटना घटी. पति की मौत के बाद मायके में रह रही एक बेसहारा बूढ़ी महिला को उसी के परिवार वालों ने डायन बताकर नंगा कर दिया. उसके शरीर के हर अंग से सूई घोंपकर खून निकाला गया. इतना ही नहीं, उसके नाजुक अंगों से भी सिरींज लगाकर खून खींचा गया. वो महिला हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर लोगों का वहशी व्यवहार जारी रहा. उसके खून के साथ ओझा रात भर तंत्र-मंत्र करता रहा. पुलिस अधिकारी मुकेश कुमार का कहना है कि इस बारे में कोई लिखित शिकायत आने पर ही कार्रवाई करेंगे. वृद्ध महिला दबंगों के डर से प्राथमिकी तक दर्ज नहीं करा पा रही है.

चाईबासा जिले के एक सुदूर गांव का रहने वाला मोहन भुईयां बहुत दिनों से बीमार था. उसकी बिमारी ठीक नहीं हो पा रही थी. उसके घरवालों ने गांव के ही एक दंपत्ति पर आरोप लगाया कि उन्होंने जादू-टोना कर के मोहन को बीमार कर दिया है. उस महिला को पंचायत में लाया गया और उस पर जादू-टोना का आरोप

> राज्य में डायन कुप्रथा दूर करने के लिए राज्य सरकार स्कूली बच्चों को जागरूक करने का काम कर रही है. साथ ही पाठ्य पुस्तक में भी इससे जुड़ा अध्याय शामिल किया गया है. साक्षरता विभाग ने कक्षा छह की किताब सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था नामक पुस्तक में डायन कुप्रथा के नाम से एक अध्याय शामिल किया है. इस अध्याय में डायन प्रथा को एक सामाजिक समस्या बताया गया है. इसमें बताया गया है कि डायन बिसाही का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये महज एक सामाजिक कुरीति एवं अंधविश्वास है.

लगाते हुए मोहन पर से नजर उतारने को कहा गया. महिला पंचायत में हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पंचायत ने उसकी एक न सुनी. उसपर डायन होने का आरोप लगाते हुए उसे जबरन मानव मल खाने को विवश किया गया. इतना ही नहीं, बाद में जब बीमारी बढ़ जाने के कारण मोहन भुईयां की मौत हो गई, तो उसके परिवार वालों ने उस महिला और उसके पति की भी हत्या कर दी.

डायन बताकर महिलाओं को मारने और उसके परिवार को प्रताड़ित करने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है. हद तो तब हो जाती है, जब डायन बताकर महिला को मल-मूत्र पिलाया जाता है. निर्वस्त्र कर उसका सामूहिक बलात्कार किया जाता है. ऐसी अमानवीय घटनाओं के बारे में सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. साल 2000 से 2016 तक डायन के नाम पर 1554 महिलाओं की हत्याएं हुई हैं. राज्य सरकार द्वारा कानून बनाए जाने के बाद भी हर साल औसतन 45 महिलाओं की नृशंस हत्या डायन बिसाही के नाम पर कर दी जाती है. पिछले पांच वर्ष में डायन के नाम पर प्रताड़ना के आरोप में 3300 मामले दर्ज हुए, लेकिन पुलिस इस मामले को लेकर हमेशा उदासीन बनी रही है. पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई नहीं किए जाने से ग्रामीणों का भी मनोबल हमेशा बढ़ा रहता है.

समाज के कुछ पढ़े-लिखे जागरूक लोग इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाते हैं और इस अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देने की बात कहते हैं, तो उन्हें ही डायन करार दिया जाता है. खूंटी जिले के राजा कुंजला गांव की सावित्री ने जब इस अंधविश्वास के खिलाफ आवाज बुलंद की तो, उसपर ही डायन होने का आरोप लगा दिया गया. काफी प्रताड़ना के बाद उसे लोगों ने गांव से निकाल दिया. दरअसल, इसके पीछे सावित्री का दस एकड़ खेत का भी मामला था. उसके खेतों पर दबंग कब्जा करना चाहते थे. लेकिन सावित्री का परिवार इस पर खेती कर गुजर-बसर कर रहा था. खेत हथियाने के लिए ही उन लोगों ने सावित्री पर डायन होने का आरोप लगाया. ठीक इसी तरह राजधानी रांची से सटे गांव बरटोली चौनपुर की सुषमा टोपनो ने जब अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद अपने पैरों पर खड़े होकर भाई-बहन को भी पढ़ाना शुरू किया, तो ये दबंगों को नागवार गुजरा. टोपनो पर भी डायन होने का आरोप लगाया गया. दबंगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया. इस घटना के बाद सुषमा ने हर जगह न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल सका. इससे क्षुब्ध होकर सुषमा ने आत्महत्या कर लिया. इस तरह की घटनाएं झारखंड के गांवों में आम हैं. किसी की जमीन पसंद आ जाय या कोई औरत पसंद आ जाय और वो अगर दबंगों की बातें नहीं माने, तो उसके साथ रूह कंपा देने वाली ज्यादतियां की जाती हैं. बलात्कार की बात सामने नहीं आए, इसलिए उसे डायन बताकर उसकी हत्या कर दी जाती है.

मिशन से ही निकलेगा समाधान : प्रेमचंद

फ्री लीगल एड कमिटी संस्था इस सामाजिक कुरीति को खत्म करने के लिए काम करती है. इस संस्था के संयोजक प्रेमचंद का कहना है कि डायन बिसाही के नाम पर महिलाओं पर अमानवीय प्रताड़ना का सिलसिला आज भी जारी है. राज्य में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 बना. इसके बावजूद ऐसी घटनाओं में कमी नहीं आ रही है. इस सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाने के लिए सामाजिक संगठनों को आगे आना होगा. प्रेमचंद का मानना है कि इस गंभीर समस्या को तभी दूर किया जा सकता है, जब सबलोग अपनी नैतिक व मानवीय जवाबदेही समझें. महिलाओं पर होने वाले अत्याचार अपने आप में अमानवीय हैं. प्रेमचंद का कहना है कि हम इस सामाजिक कुरीति को पूर्णतः समाप्त करने को लेकर कृतसंकल्प हैं. अपनी संस्था फ्री लीगल एड कमिटी के माध्यम से हम पूरे राज्य में जनजागरण अभियान चला रहे हैं. प्रेमचंद का मानना है कि बिना लोगों को जागरूक किए इस समस्या से निजात नहीं पाया जा सकता है. केवल सरकार द्वारा कानून बना दिए जाने से इस पर काबू नहीं पाया जा सकता. इस कानून को कैसे अमल में लाया जाय, इस पर चिंतन करने की जरूरत है. जब तक सभी लोगों में इसे लेकर पूर्णरुपेण इच्छाशक्ति नहीं होगी, तब तक इस गंभीर समस्या को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है. अंधविश्वास उन्मूलन मिशन बनाकर इसे दूर करने की दिशा में प्रयास किया जा सकता है. इसके लिए ग्रासरुट से ऊपर तक के स्तर पर काम करने की जरूरत है. साथ ही सामाजिक सशक्तिकरण का अभियान चलाने की जरूरत है. प्रेमचंद्र ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा ऑपरेशन अंधविश्वास अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के लिए उन्हें युनिसेफ का भी सहयोग मिल रहा है.

पंचायतें निभा सकती हैं कारगर भूमिका : लुईस मरांडी

राज्य की समाज कल्याण मंत्री डॉ. लुईस मरांडी डायन प्रथा को एक गंभीर समस्या मानती हैं और इसे दूर करने के लिए कानूनी और सामाजिक स्तर पर लड़ाई लड़ने के पक्ष में हैं. वे इस बात से चिंतित दिखती हैं कि झारखंड में अंधविश्वास और डायन के नाम पर हर साल सैकड़ों हत्याएं होती हैं. उनका कहना है कि ये समस्या समाज के लिए तो एक बड़ा अभिशाप है ही, सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है. सरकार इस समस्या को खत्म करने के लिए निश्चित रुप से प्रयास कर रही है. इसके लिए कानून बनाए गए हैं और साथ ही राज्य सरकार कई योजनाएं भी चला रही है. झारखंड मंत्रिमंडल ने 3 जुलाई, 2001 को ही डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम को स्वीकृति दी थी. इस कानून के तहत डायन के नाम पर किसी को प्रताड़ित करने पर जुर्माना और कैद दोनों ही करना अनिवार्य है. लेकिन इसे केवल सरकारी योजना और प्रयास से खत्म नहीं किया जा सकता है. गांव समाज के हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा, तभी इस अंधविश्वास को खत्म किया जा सकता है. राज्य की पंचायतें भी इसमें अहम भूमिका निभा सकती हैं.

ये पूछे जाने पर कि कानून लागू होने के बाद भी ठोस नतीजे क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, इन्होंने कहा कि लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, जहां भी डायन उत्पीड़न का मामला पकड़ में आता है, वहां मामले दर्ज होते हैं और कार्रवाई भी होती है. लेकिन ये भी सच है कि कानून को लेकर लोगों में जो भय होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है. एक कमी ये भी है कि इस कानून को लागू करने वाली एजेंसियों और इससे प्रभावित होने वाले लोगों के बीच कहीं न कहीं गैप है. इसे और भी सख्ती से लागू करने की जरूरत है. लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार की तरफ से प्रचार गाड़ियां और रथ निकाले गए हैं. साथ ही इसके लिए बजट में एक बड़ी राशि का भी प्रावधान किया गया है. समाज कल्याण विभाग की तरफ से इसके लिए आंगनबाड़ी सेविका और पोषण सखी की भी सहायता ली जा रही है. इस मामले में पुलिस की भी भूमिका महत्वपूर्ण है. समाज कल्याण मंत्री का ये भी मानना है कि इस प्रथा को खत्म करने में पंचायती राज संस्थाएं सबसे कारगर साबित हो सकती हैं. सरकार को इनसे काफी अपेक्षाएं भी हैं. जिला परिषद के अध्यक्ष, पार्षद से लेकर मुखिया और वार्ड सदस्य इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. गांव समाज के एक-एक व्यक्ति तक पंचायती राज संस्थाओं की व्यापक पहुंच है और पूरा समाज इनके इर्द-गिर्द रहता है. इस कारण इनकी भूमिका अहम हो सकती है. जब ये पूछा गया कि आपके मंत्री बनने के बाद भी घटनाओं में वृद्धि हुई, आपने क्या कदम उठाया, तो इनका जवाब था कि सरकार की तरफ से जितना प्रयास हो सकता है, हम वो सब कर रहे हैं. लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हम नुक्कड़ नाटक और प्रचार गाड़ी एवं अन्य माध्यमों की भी सहायता ले रहे हैं. साथ ही पुलिस प्रशासन को भी इस संबंध में सख्त हिदायत दी गई है.

डायन कुप्रथा दूर करने के लिए बच्चों को किया जा रहा जागरूक

राज्य में डायन कुप्रथा दूर करने के लिए राज्य सरकार स्कूली बच्चों को जागरूक करने का काम कर रही है. साथ ही पाठ्य पुस्तक में भी इससे जुड़ा अध्याय शामिल किया गया है. साक्षरता विभाग ने कक्षा छह की किताब सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था नामक पुस्तक में डायन कुप्रथा के नाम से एक अध्याय शामिल किया है. इस अध्याय में डायन प्रथा को एक सामाजिक समस्या बताया गया है. इसमें बताया गया है कि डायन बिसाही का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये महज एक सामाजिक कुरीति एवं अंधविश्वास है. गांव में कोई बीमारी फैलती है और इससे किसी की मौत होती है, तो इसकी कोई खास वजह होती है, किसी अंधविश्वास के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता. इस अध्याय इससे जुड़ी एक कहानी भी दी गई है. इसमें बताया गया है कि एक गांव में एक महिला रहती थी, जिसके पति की मृत्यु हो गई. बाद में बेटे की भी मौत हो गई. बरसात के मौसम में बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगे, तो गांव के लोग उस महिला के घर पहुंचे और उसके पति और बेटे की मौत के लिए उसे जिम्मेदार बताने लगे. लेकिन फिर आंगनबाड़ी की दीदी ने गांव के लोगों का ईलाज कराया, तो सभी ठीक होने लगे. इस पुस्तक में डायन प्रथा समाप्त करने के लिए बने कानून के बारे में भी बताया गया है.■

feedback@chauthiduniya.com

कश्मीर भारत का उपनिवेश नहीं है

www.kamalmorarka.com

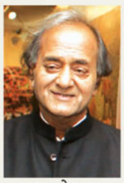

कमल मोरारका

कश्मीर पर सरकार का दृष्टिकोण क्या है, मुझे जानना है. ये सरकार कहती है कि कश्मीर नेहरू की गलती है. नेहरू की क्या गलती थी? क्या ये कोशिश करना गलती थी कि कश्मीर को भारत के साथ मिलाया जाए? संयुक्त राष्ट्र संघ में जाना गलती थी या बाद में इस नतीजे पर पहुंचना कि जनमत संग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं को वापस नहीं बुलाया? तो उनकी गलती क्या थी? वे इस बात का खुलासा नहीं करते. सरदार पटेल, जो उनके मौजूदा हीरो हैं, का मानना था कि हमें कश्मीर को छोड़ देना चाहिए. जब हम मुस्लिम बहुमत के अनुसार विभाजन पर सहमत हुए हैं और कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो उसे पाकिस्तान के साथ जाने देना चाहिए. महाराजा हरि सिंह डरे हुए थे. वे पाकिस्तान के साथ मिल गए होते, यदि शेख अब्दुल्ला नहीं होते.

कश्मीर के हालात निश्चत रूप से बेकाबू होते जा रहे हैं. हालांकि ये कहा जा सकता है कि जम्मू-कश्मीर समस्या 1948 से ही मौजूद है. लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में, खास तौर पर 1987 के चुनाव के बाद (जिसके बारे में ये धारणा है कि इसमें धांधली हुई थी), कश्मीर में वास्तविक समस्या की शुरुआत हुई. 1990 के दशक में हालात ख़राब रहे. स्थिति को किसी तरह व्यवस्थित कर वहां चुनाव हुए. पीडीपी-भाजपा गठबंधन के बाद हालात फिर बेकाबू हो गए हैं. इसका कारण ये है कि अपने पूरे राजनीतिक सफ़र में भाजपा आर्टिकल 370 को रद्द करने की बात करती रही है. उसके मुताबिक कश्मीर को भारत के साथ एकीकृत करने का यही एक मात्र तरीका है. दूसरी तरफ पीडीपी ये कहती आई है कि आर्टिकल 370 ही कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने वाली एक मात्र कड़ी है. यदि इसे रद्द किया गया, तो कश्मीर में लोग इसे कबूल नहीं करेंगे और फिर कश्मीर भारत का अंग नहीं रहेगा. ये दो बिल्कुल उलट विचार एक साथ मिलकर कैसे सरकार बना सकते हैं? ज़ाहिर है, केवल पद हासिल करने और सत्ता की मलाई खाने के लिए. कुछ मंत्री पैसे कमाएंगे, पीडीपी कुछ पैसे इकट्ठा करेगी, कुछ पैसे भाजपा इकट्ठा करेगी. दरअसल, इस पैसे इकट्ठा करने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है. मुफ़्ती मोहम्मद सईद के पैतृक शहर बिजबेहरा के लिए उनका जनाज़ा एक झटका था, क्योंकि उसमें कुछ हज़ार लोग ही शामिल हुए थे. मुफ़्ती हमेशा ये सोचते थे कि शेख अब्दुल्ला के बाद वे कश्मीर के दूसरे महत्वपूर्ण नेता हैं. शेख अब्दुल्ला के जनाज़े में शरीक होने वालों की संख्या लाखों में थी. महबूबा मुफ़्ती के पैरों तले से ज़मीन निकल गई. लिहाज़ा, वो सरकार बनाना नहीं चाहती थीं. उन्होंने सरकार बनाने में उस समय तक विलंब किया, जब तक उनके और भाजपा के बीच में कोई ऐसा समझौता नहीं हो गया, जो दोनों के लिए आकर्षक था. बहरहाल, उन्होंने एक राजनैतिक गलती की, जिसने शायद उनकी राजनीति को खत्म कर दिया.

खैर, वो बात अब बीत चुकी है. अब सवाल ये है कि हालात को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि वो प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं. आर्मी ने एक नागरिक को अपनी जीप के आगे बांध कर इसलिए घुमाया, ताकि उनके ऊपर पत्थर न फेंके जाएं. कोई भी कहेगा कि ये असभ्य तरीका था. निश्चित रूप से ये सेना का तरीका तो नहीं हो सकता है. ट्विटर पर अरुंधति रॉय, जो एक उदारवादी लेखिका हैं, को ले कर डिबेट चल रहा है. कुछ गैर ज़िम्मेदार लोग कह रहे हैं कि उन्हें ही गाड़ी के आगे बांध कर घुमाना चाहिए. ज़ाहिर है, ये कोई गंभीर सुझाव नहीं है. मैं समझता हूं कि देश में बहस का स्तर नीचे गिरता जा रहा है. जो भाषा हम इतेमाल कर रहे हैं, वो असभ्य है. इस पर सरकार का क्या रुख है?

इन सब मामलों से अपना पल्ला झाड़ते हुए रक्षा मंत्री अरुण जेटली कहते हैं कि कश्मीर के फैसले को सेना के ऊपर छोड़ देना चाहिए. मैंने इस तरह का बयान पहले कभी नहीं सुना. क्या कश्मीर भारत का उपनिवेश है? कश्मीर एक राज्य है, जहां एक चुनी हुई सरकार है. हमारे संविधान के मुताबिक सेना चुनी हुई सरकार के आग्रह पर आती है. बेशक, कश्मीर में अफ्स्पा लागू है, लेकिन उसे असीमित अधिकार नहीं दिए जा सकते. इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं. केंद्र सरकार कश्मीर में अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है. हम पाकिस्तान को कौन सा संदेश दे रहे हैं. हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कौन सा संदेश दे रहे हैं. ये बयान अर्थहीन है. हमें अपने सभ्य आचरण को पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है. लोगों को ये बताना चाहिए कि चाहे उनकी सोच जो भी हो, वे बातें तो सभ्य करें.

कश्मीर पर सरकार का दृष्टिकोण क्या है, मुझे जानना है. ये सरकार कहती है कि कश्मीर नेहरू की गलती है. नेहरू की क्या गलती थी? क्या ये कोशिश करना गलती थी कि कश्मीर को भारत के साथ मिलाया जाए? संयुक्त राष्ट्र संघ में जाना गलती थी या बाद में इस नतीजे पर पहुंचना कि जनमत संग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं को वापस नहीं बुलाया? तो उनकी गलती क्या थी? वे इस बात का खुलासा नहीं करते. सरदार पटेल, जो उनके मौजूदा हीरो हैं, का मानना था कि हमें कश्मीर को छोड़ देना चाहिए. जब हम मुस्लिम बहुमत के अनुसार विभाजन पर सहमत हुए हैं और कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो उसे पाकिस्तान के साथ जाने देना चाहिए. महाराजा हरि सिंह डरे हुए थे. वे पाकिस्तान के साथ मिल गए होते, यदि शेख अब्दुल्ला नहीं होते. शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे. अब ये लोग दुनिया में नहीं हैं. अब आपका (केंद्र सरकार) दृष्टिकोण क्या है? आज नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लगभग सारे राज्य उनके कब्जे में हैं. क्या आप कश्मीर चाहते हैं? क्या आप कश्मीर नहीं चाहते हैं? केवल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और आर्मी चीफ की बातें सुनना समस्या के समाधान का तरीका नहीं है. कश्मीर की बात समझ में आती है, कल यदि किसी दूसरे राज्य में कोई बात होती है, तो क्या आप उस राज्य को सेना के हवाले कर देंगे? तो फिर पाकिस्तान की तरह सेना ये सवाल करेगी कि हमें सिविलियन सरकार की क्या जरूरत है? सेना सत्ता पर क़ब्ज़ा कर लेगी. वे ये नहीं समझ रहे हैं कि वे आग से खेल रहे हैं. ये तरीका सही नहीं है. सरकार को चाहिए कि वो आर्मी चीफ, एनएसए और कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस के साथ बातचीत करे, रास्ता निकाले. राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं, वे कश्मीर का दौरा भी नहीं कर रहे हैं. तो सवाल ये उठता है कि क्या कश्मीर को गृह मंत्रालय से अलग कर दिया गया है?

कांग्रेस संवाद करती है. वो बातचीत का दरवाजा खोल कर रखती है. भारत-पाकिस्तान बातचीत लगभग आज़ादी के साथ ही शुरू हुई है. करण सिंह ने सिन्धु जल संधि पर अपना बहुत समय लगाया था. बातचीत ही एकमात्र रास्ता है और आज इसका महत्व इसलिए बढ़ गया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं. सरकार की रणनीति क्या है? उसे चाहिए कि वो लोगों को विश्वास में रखे. लोगों की राय ले. अगर लोग युद्ध चाहते हैं, तो आप पाकिस्तान के साथ युद्ध कर लीजिए. जब आपको चुना जाता है तो अच्छे काम के लिए चुना जाता है या बुरे काम के लिए?

देश में नीतिगत निष्क्रियता (पॉलिसी पैरालिसिस) की स्थिति है. ये बातें भाजपा मनमोहन सिंह से कहती थी. मनमोहन सिंह खामोश रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा. मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी की चुप्पी बेचैनी पैदा करती है. उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोला है. या तो वे अपनी पार्टी के लोगों को पैसा बनाने, लूट करने की छूट दे रहे हैं, ताकि वे चुनाव जीत सकें. मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक चीज सीखी है, वो है कांग्रेस की गलत चीज़ें. चुनाव जीतो, सरकार बनाओ, चाहे जैसे भी बने. उनका पूरा ध्यान इन्हीं चीज़ों पर है. गोवा में भाजपा को 40 में से 13 सीटें मिली थीं, लेकिन वे वहां सरकार बनाना चाहते थे और बनाया भी. मणिपुर में कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी, सरकार बनाने के लिए चाहिए 31, लेकिन सरकार बनी भाजपा की. भाजपा ने कांग्रेस से हर गलत काम सीख लिया है. कांग्रेस में भले ही अभी निराशा हो, लेकिन मैं इस देश को पिछले 60-70 सालों से देख रहा हूं. कांग्रेस में कई अच्छाइयां भी हैं. इनमें से एक सबसे अच्छी बात है, संवाद. कांग्रेस संवाद करती है. वो बातचीत का दरवाजा खोल कर रखती है. भारत-पाकिस्तान बातचीत लगभग आज़ादी के साथ ही शुरू हुई है. करण सिंह ने सिन्धु जल संधि पर अपना बहुत समय लगाया था. बातचीत ही एकमात्र रास्ता है और आज इसका महत्व इसलिए बढ़ गया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं. सरकार की रणनीति क्या है? उसे चाहिए कि वो लोगों को विश्वास में रखे. लोगों की राय ले. अगर लोग युद्ध चाहते हैं, तो आप पाकिस्तान के साथ युद्ध कर लीजिए. जब आपको चुना जाता है, तो अच्छे काम के लिए चुना जाता है या बुरे काम के लिए?

प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का मतलब होता है, सच्चाई लिखना. मैंने देखा कि अभिजीत भट्टाचार्या को ट्विटर से हटाए जाने पर लोग ट्विटर का ही विरोध कर रहे हैं. वे कहते हैं कि क्या ये प्रेस की आज़ादी है? वे सभी उदारवादी लोग कहां हैं? अब सवाल ये उठता है कि आज़ादी क्या है? परेश रावल, अरुंधति रॉय को जीप से बांधने की बात करते हैं. किस तरह की सहिष्णुता है ये? ये ऐसे लोग हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में और संगीत जगत में अपना नाम बनाया है. उनके ऐसे विचार हैं! ये बहुत ही दुखद स्थिति है. इनका आईक्यू कम है. आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस के बारे में उन्होंने सुना ही नहीं है.

ज़रूरत इस बात की है कि कैबिनेट को तत्काल बैठ कर कश्मीर मसले पर बात करनी चाहिए. ज़रूरत हो तो कश्मीर के मुद्दे पर संसद का एक सत्र बुलाया जाए. बहस के बाद इस मुद्दे पर अपनी नीति स्पष्ट कीजिए कि आखिरकार आप कश्मीर में करना क्या चाहते हैं. यशवंत सिन्हा कश्मीर गए, मैं भी गया था. लेकिन सरकार ऐसे लोगों से कश्मीर के बारे में सुनना ही नहीं चाहती कि कश्मीर पर इनकी क्या राय है? सरकार को मालूम है कि असलियत उसे असहज कर देगी. जितनी जल्दी ये सब समझ लिया जाए, उतना ही बेहतर होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

कश्मीरी छात्रों का ग़ुस्सा समझिए

शुजात बुख़ारी

कश्मीर में सरकार को सबसे नई चुनौती छात्रों की ओर से मिल रही है. यहां छात्रों का क्रोध काफी समय से सुर्खियों में रहा है. दो सप्ताह की अवधि तक थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद कॉलेजों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को बंद किया गया. फ़िलहाल छात्रों के विरोध की तीव्रता कम हो गई है, लेकिन चिंगारी अभी बुझी नहीं है. इससे ये ज़ाहिर होता है कि छात्रों ने कश्मीर समस्या के राजनीतिक समाधान के संकल्प को कैसे स्वीकार किया है. सरकार के खिलाफ कॉलेजों और माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के व्यापक प्रदर्शन को यहां बढ़ती हुई निराशा के विरोध में आ रही प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है.

इसकी शुरुआत 15 अप्रैल को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, पुलवामा से हुई, जहां सेना के एक मेजर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित कराने का प्रस्ताव लेकर गए थे. वे वहां एक माइन रेसिसटेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड कैस्पीयर व्हेइकल में बैठ कर गए थे. इस वाहन का इस्तेमाल खासकर बारूदी सुरंग और घात लगाकर किए जाने वाले हमलों से बचने के लिए किया जाता है. ये कश्मीर के संघर्ष वाले क्षेत्रों में अपने प्रभाव के लिए जाना जाता है. वहां इसे देखकर छात्र उग्र हो गए और उन्होंने इसपर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए. हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस ने लगभग एक घंटे तक गोलीबारी की, जिसके कारण दर्जनों छात्र घायल हुए.

ये घटना घाटी में क्रोध भड़काने के लिए पर्याप्त थी. स्कूलों और कॉलेजों के छात्र बड़ी संख्या में बाहर निकलने लगे. यहां तक कि लड़कियां और महिलाएं भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं. उन्हें पहली बार पुलिस पर पत्थर फेंकते देखा गया. सोशल मीडिया में एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें एक लड़की एक हाथ से पुलिस वाहन को मार रही थी और दूसरे में बास्केटबॉल लिए हुए थी. दस दिनों के लिए कॉलेज और स्कूल बंद रहे. कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए स्कूल-कॉलेज बंद किए गए. शैक्षणिक संस्थानों में विरोध प्रदर्शन अब आम हो गए हैं. कश्मीर युनिवर्सिटी स्टुडेंट्स यूनियन ने शुरू में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, लेकिन बाद में छात्रों को अपने-अपने क्लास में लौट जाने के लिए कहा. पुलिस ने दावा किया कि कुछ संस्थानों में एक आतंकवादी संगठन अपने मजबूत नेटवर्क के माध्यम से विरोध जारी रखे हुए हैं. लेकिन देखा जाय, तो पहली नज़र में ये क्रोध स्वत:-स्फूर्त लगता है. जिस तरह से लड़के-लड़कियां इस राजनीतिक संघर्ष से जुड़ रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में इसमें कमी होगी.

कश्मीर की हिंसक राजनीति में मजबूत छात्र आंदोलनों का बड़ा योगदान रहा है. 1960 के दशक के शुरुआती दिनों में सशस्त्र ग्रुप अल फतह ने भारत को चुनौती दी थी. अल फतह मुख्य रूप से छात्रों का एक ग्रुप था. यंग मैन लीग ने भी वही रास्ता अपनाया. हालांकि दोनों भारत की ताकत के खिलाफ खड़े नहीं रह सके. लेकिन जमात-ए-इस्लामी की छात्र शाखा इस्लामिक जमात-ए-तलबा जैसी संगठनों ने प्रतिरोधी आंदोलन को एक वैचारिक ढांचा प्रदान किया.

पिछले दो दशकों से जारी हिंसा ने युवाओं के दिमाग पर असर डाला है. उन्हें ये विश्वास हो गया है कि अब बदलाव की गुंजाइश नहीं है. इस विश्वास ने उनके अन्दर ये सोच पैदा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि वे समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं. ऑक्सफेम द्वारा 2003 में कश्मीरी युवाओं पर किए गए एक अध्ययन में दावा किया गया था कि 90.38 प्रतिशत युवा नाराज हैं. उस अध्ययन के अनुसार 63.44 प्रतिशत युवा ऐसे थे, जिनका परिवार सीधे तौर पर हिंसा से प्रभावित हुआ था. उस समय छात्रों में हिंसा के गंभीर प्रभाव दिख रहे थे, जो उनकी पेंटिंग, लेख और बातचीत से ज़ाहिर होते थे.

जिन लोगों ने 1988 में जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के बैनर तले विद्रोह किया और भारत से आजादी के लिए बंदूक उठाई, उनमें से ज्यादातर इस्लामी छात्र लीग के सदस्य थे. उन्होंने ही 1980 के दशक के मध्य में भारत और ऑस्ट्रेलिया और भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले दो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का विरोध किया था.

अभी ऐसा लगता है कि कश्मीर में युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का कोई व्यवस्थित ढांचा नहीं है. हालांकि ये कहना मुश्किल है कि ये विरोध प्रदर्शन किस दिशा में जाएगा. कश्मीर की आबादी का 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सा युवा है. ये ऐसा वर्ग है, जिसपर राजनीतिक संघर्ष का गहरा प्रभाव पड़ा है. सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज़ उमर फारूक और यासीन मलिक के नेतृत्व वाले संयुक्त हुर्रियत कांफ्रेंस को इसे नियंत्रित करने में मुश्किल हो रही है. तेज़ी से फैलती अराजक स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए कोई वास्तविक नेतृत्व नहीं है. कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ये सवाल उठाते हैं कि हमारे युवा किस दिशा में जा रहे हैं? ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है और हमें देखना होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है.

पिछले दो दशकों से जारी हिंसा ने युवाओं के दिमाग पर असर डाला है. उन्हें ये विश्वास हो गया है कि अब बदलाव की गुंजाइश नहीं है. इस विश्वास ने उनके अंदर ये सोच पैदा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि वे समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं. ऑक्सफेम द्वारा 2003 में कश्मीरी युवाओं पर किए गए एक अध्ययन में दावा किया गया था कि 90.38 प्रतिशत युवा नाराज हैं. उस अध्ययन के अनुसार 63.44 प्रतिशत युवा ऐसे थे, जिनका परिवार सीधे तौर पर हिंसा से प्रभावित हुआ था. उस समय छात्रों में हिंसा के गंभीर प्रभाव दिख रहे थे, जो उनकी पेंटिंग, लेख और बातचीत से ज़ाहिर होते थे. उस अध्ययन में कहा गया था कि कश्मीर में आज सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होना केवल शादियों और मस्जिदों के कार्यक्रमों तक सिमट कर रह गया है. उसी तरह, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (मेडिसिन सैन्स फ्रंटियर) ने एक अध्ययन में पाया है कि हिंसा ने यहां लोगों को मानसिक तौर पर प्रभावित किया है. इस अध्ययन में बताया गया है कि हिंसा के कारण आत्महत्या की दर में 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और 58.69 प्रतिशत युवाओं ने गोलियों और विस्फोटों जैसी वारदातों का अनुभव किया है. हालांकि बीते 20 वर्षों में यहां धर्म का प्रभाव काफी बढ़ा है. लेकिन धर्म समाज के उदार दृष्टिकोण को बदलने में नाकाम रहा है. कश्मीर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग द्वारा 2010 में किए गए एक अध्ययन में 15-18 आयु वर्ग के 72 प्रतिशत युवाओं ने कहा था कि वे धार्मिक सहिष्णुता और धर्मों के सह-अस्तित्व में विश्वास रखते हैं.

अपनी ही जन्मभूमि में घेराबंदी का अहसास, आर्थिक तंगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वंचित रखे जाने के कारण यहां लोगों में निराशा पैदा हुई है. निराशा के इसी भाव ने युवाओं को पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों से मुकाबला करने पर मजबूर किया है. वर्ष 2010 में सुदूर माचिल इलाके में फर्जी मुठभेड़ की एक घटना में सेना ने तीन युवाओं को मार दिया था. मुठभेड़ का मकसद कथित तौर पर पुरस्कार और पदोन्नति पाना था. लेकिन इस घटना के बाद घाटी में हिंसक अशांति का लंबा दौर शुरू हुआ. इस हिंसक दौर के समाप्त होने तक 120 नागरिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. मरने वालों में 5-10 आयु वर्ग के 3, 11-20 आयु वर्ग के 44, 21-30 आयु वर्ग के 44 और 31 वर्ष से ऊपर के 16 लोग शामिल थे. मारे जाने वालों में सबसे ज्यादा 39 छात्र थे और शेष कुशल या अकुशल श्रमिक और व्यवसायी थे.

वर्ष 2008 और 2009 में भी अमरनाथ भूमि विवाद और शोपियां में दो महिलाओं के कथित बलात्कार और हत्या की घटना (जिसके लिए लोग सुरक्षा बलों को ज़िम्मेदार मानते थे) के बाद युवाओं ने विरोध-प्रदर्शनों में सक्रिय भूमिका निभाई थी. हालांकि सीबीआई ने अपनी जांच में सेना को क्लीन चिट दे दिया और कहा कि महिलाओं की मौत डूबने की वजह से हुई है. 20 वर्षों के सशस्त्र विद्रोह की पृष्ठभूमि में इन विरोध प्रदर्शनों में युवाओं की भागीदारी का वर्णन कई लोगों ने कश्मीर के हिंसा से अहिंसा की तरफ जाने के रूप में किया था.

2010 के आंदोलन को लेकर नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर डायलॉग एंड रिकॉन्सिलिएशन (सीडीआर, कश्मीर अनरेस्ट 2010) ने एक अध्ययन किया था, जिसमें एक दिलचस्प टिप्पणी की गई थी. उस अध्ययन में कहा गया था कि अधिकांश युवाओं का कोई राजनीतिक जुड़ाव नहीं है. राजनीतिक जुड़ाव के सवाल पर पीड़ितों के परिवारों से एक दिलचस्प जवाब मिला. जब उन परिवारों से पूछा गया कि क्या उनकी या जो मारे गए थे उनकी कोई राजनीतिक सम्बद्धता थी, तो उनमें से 78 प्रतिशत ने इससे इंकार किया. इसे लेकर अब तक सवाल उठते रहे हैं कि इन प्रदर्शनों का नेतृत्व किसने किया और इन्हें कैसे प्रायोजित किया गया, लेकिन जहां तक विरोध प्रदर्शनों के पीड़ितों का सवाल है, तो न तो वे और न ही उनके परिवार ये मानते हैं कि उनकी कोई राजनीतिक सम्बद्धता है.

कश्मीर से एक खतरनाक हकीकत ये सामने आ रही है कि युवा अब अपने माता-पिता की भी नहीं सुन रहे हैं. युवाओं द्वारा किए जा रहे ऐसे कामों को जिस तरह से सामाजिक स्वीकृति मिली है, उसे देखते हुए इन्हें समझाना और सही रास्ता बताना भी बुजुर्गों के लिए मुश्किल होता जा रहा है. हाल में विरोध प्रदर्शन का केंद्र रहे एक कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षक का कहना है कि यहां जो कोई भी पुलिस पर पत्थर फेंकता है, उसे एक योद्धा के रूप में देखा जाता है और जो लोग जवाबी कार्रवाई में मारे जाते हैं, वे शहीद कहलाते हैं. लिहाज़ा, सामाजिक स्वीकृति से साफ हो जाता है कि ये स्थिति कैसे सामने आई. वास्तव में राजनीतिक संदर्भ ही इस तरह की कार्रवाई को वैधता प्रदान कर रहा है.■

-लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

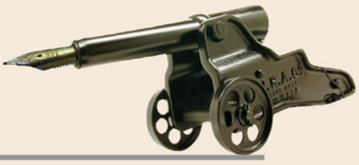

प्रधानमंत्री जी, एक बार कश्मीर के लोगों से मन की बात तो करिए

अब कश्मीर में क्या होगा? ये बड़ा सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि केंद्र सरकार बातचीत शुरू करने का कोई संकेत नहीं दे रही है. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पहले पत्थरबाजी बंद हो और उसके बाद बातचीत हो. कश्मीर में लोग कह रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ये याद नहीं कि अक्टूबर से लेकर अप्रैल के शुरू तक कश्मीर में शांति ही शांति थी. उसके पहले नौ महीने से ज्यादा पूरा कश्मीर, चाहे शहर हो या गांव कंप्लीट स्ट्राइक पर थे. हुर्रियत का कैलेंडर चलता था. दूसरी तरफ, भारत सरकार इन सारी चीजों से बिल्कुल परेशान नहीं दिखाई दे रही और उसे लग रहा है कि कश्मीर में जो भी हो रहा है, वो पाकिस्तान से सम्बंधित लोग कर रहे हैं. तीसरी तरफ टेलीविजन, लगभग सारे टेलीविजन चैनल, कश्मीर के लोगों में नफरत और गुस्सा भर रहे हैं. उन्हें लगता है कि टेलीविजन वो सब दिखा रहे हैं, जो न कश्मीर में हो रहा है न कश्मीर के लोग चाहते हैं, बल्कि टेलीविजन चैनलों ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है, मानो कश्मीर के लोग भारत के शत्रु हों. भारत का शत्रु जितना बड़ा चीन है, जितना बड़ा पाकिस्तान है, उससे भी बड़ा शत्रु कश्मीर के लोग हैं. टेलीविजन चैनलों ने रोज रात में बहस कर देश में तो माहौल बनाया ही, कश्मीर में भी ऐसा ही माहौल बना दिया है.

मैं तीन महीने के बाद कश्मीर गया. देश के कई क्षेत्रों के पत्रकार कश्मीर में मिले. सबने लगभग यही राय बताई. लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार और टेलीविजन चैनल कश्मीर की समस्या से जरा भी परेशान नहीं दिखाई दिए. वो क्यों परेशान नहीं हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम ये बता दें कि कश्मीर में जब से लड़कियों ने हाथ में पत्थर उठाए हैं, तब से वहां माहौल अजीब तरह से बदल रहा है. हमने जब पता किया कि लड़कियों ने पत्थर क्यों उठाए, तो इसके कई कारण नजर आए. लेकिन जिस कारण की ओर सबने इशारा किया, वो ये है कि टेलीविजन चैनल जिस तरह से लड़कियों के पत्थर चलाने को एक इवेंट बनाकर देश के सामने और दुनिया के सामने रख रहे हैं, उसकी वजह से हर स्कूल के भीतर छात्रों के बीच पत्थर चलाना दुख का, दर्द का, परेशानी प्रकट करने का और साथ ही एक ग्लैमरस इवेंट का हिस्सा होने का कारण बन गया है.

आख़िर, कश्मीर में क्या होगा? अगर भारत सरकार के नजरिए से देखें, तो चाहे वो गृहमंत्री हों, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हों या कश्मीर के वो मंत्री हों, जो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, इन सबका मानना है कि कश्मीर में सख्ती बरतनी चाहिए और किसी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहिए. इन्हें ये लगता है कि जिस तरह इन्होंने पिछले साल सात-आठ महीने तक जो सख्ती बरती, जिसकी वजह से लोग हुर्रियत से दूर चले गए और अपने आप उन्होंने दुकानें खोल लीं, उसी तरीके से जनता को फिर से थकाओ, पत्थर चले, अखबारों में बयान हों, सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. शायद भारत सरकार उनकी एक सूची बनाने के बारे में भी सोच रही है, जो वहां अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त हैं या जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं या जो पत्थर चलाने में लिप्त हैं. सरकार चाहती है कि उन्हें पकड़ा जाए और न पकड़ पाएं, तो उन्हें गोली मार दी जाए. जो माहौल बन रहा है, वो यही बन रहा है कि कश्मीर में सेना को खुली छूट दी जाए और सेना इस स्थिति को नियंत्रित करे. कश्मीर के लोग, सिविल सोसायटी के लोग और राजनीतिक दलों के लोग भारत सरकार से ये मनुहार करते-करते थक गए कि कश्मीर के लोगों के साथ किसी तरह की बातचीत जल्दी से जल्दी शुरू की जाए. जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी बीच-बीच में ये कहती रही हैं कि कश्मीर के लोगों से बातचीत होनी चाहिए, जिनमें हुर्रियत के लोग भी शामिल हैं. इन सारी चीजों का भारत सरकार के ऊपर असर नहीं है. इसलिए अब ये लगता है कि भारत सरकार बातचीत के रास्ते पर नहीं जाएगी, जैसे वो तीन साल से नहीं गई और अब वो सेना के कानून और नियम पर चलेगी, जिससे वो कश्मीर को नियंत्रित कर सके. मैं यहां साफ कर दूं कि कश्मीर को नियंत्रित करने का मतलब वहां के लोगों को नियंत्रित करने से है, जमीन तो भारत सरकार के नियंत्रण में है ही.

दूसरी तरफ, कश्मीर में लगभग सभी लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं. वे भारत सरकार से बातचीत करना चाहते हैं. हालांकि उन्हें लगता है कि बातचीत से क्या निकलेगा, क्योंकि भारत की सरकार कश्मीर के लोगों को वो चीजें भी मुहैया नहीं करा रही है, जो मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश के लोगों को हासिल है. यानि वो आजादी, जिसे मीटिंग करने की आजादी कहते हैं, अपनी शिकायत करने की आजादी कहते हैं, जलसे-जुलूस निकालने की आजादी कहते हैं, वो कश्मीर के लोगों को नहीं है. कश्मीर में अब सरकार उसी रास्ते जा रही है, जिस रास्ते वो आज से 15 साल पहले पंजाब में गई थी. 14 साल से ऊपर के लड़कों पर नज़र है और अगर कश्मीर के लोगों के बताए जाने वाले किस्सों पर भरोसा करें, तो 14 साल से लेकर 24 साल तक के उम्र के लोगों के ऊपर पुलिस वजह-बेवजह सख्ती कर रही है. कश्मीर के लोग एक जुबान में बोल रहे हैं. अपने दर्द का इजहार कर रहे हैं. वे चाहते हैं कि हिन्दुस्तान से लोग कश्मीर जाएं और वहां के हालात को देखें. ये एक अजीब सच्चाई है कि पिछले 60 सालों में हिन्दुस्तान से लोग पर्यटन के लिए तो गए, लेकिन हिन्दुस्तान के लोगों ने कश्मीर के लोगों की तकलीफ क्या है या दर्द क्या है या वो क्या चाहते हैं, इसके बारे में कभी बातचीत ही नहीं की. इस समय कश्मीर के लोगों की चाह है कि भारत के राजनीतिक दलों के लोग, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हैं, वो कश्मीर आएं और कम से कम दो दिन, तीन दिन वहां रहकर, जिससे चाहें बातचीत कर, कश्मीर का दर्द जानने की कोशिश करें. उनका ये भी कहना है कि भारत के वो पत्रकार, जो महाराष्ट्र में हैं, दिल्ली में हैं, पटना में हैं, लखनऊ में हैं, इंदौर में हैं, कोलकाता में हैं, हैदराबाद में हैं, इन सब प्रेस क्लबों से एक-एक टीम कश्मीर जाए, श्रीनगर जाए और वहां जाकर वो लोगों से तो मिले, कम से कम अपनी बिरादरी के लोगों से यानि कश्मीर के पत्रकारों से भी मिले और देखे कि कश्मीर के पत्रकार क्या कह रहे हैं. कश्मीर के पत्रकारों में बड़े अखबारों के संपादक और संवाददाता शामिल हैं. लेकिन छोटे अखबारों के संपादक और संवाददाता भी इसमें शामिल हैं. कश्मीर के टेलीविजन चैनलों के लोगों से भी बात करें और इतना ही नहीं कश्मीर में जब पत्रकार जाएं तो उन जगहों पर भी जाएं, जिन्हें सबसे ज्यादा आतंकग्रस्त माना जा रहा है. कश्मीर के लोगों की ये इच्छा पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, मैं नहीं जानता. लेकिन उनकी इच्छा बिल्कुल तार्किक है और अगर वो आमंत्रित कर रहे हैं, राजनीतिक दलों के लोगों को और पत्रकारों को, तो उन्हें एक बार कश्मीर जरूर जाना चाहिए. उन लोगों को तो जरूर जाना चाहिए, जो टेलीविजन चैनल में एंकरिंग करते-करते भारत सरकार से ज्यादा भारत सरकार के प्रवक्ता बन जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि पत्रकार का काम दोनों तरफ की चीजों को दिखाना है. दरअसल, पत्रकारिता की एक नई परिभाषा हमारे टेलीविजन चैनल लिख रहे हैं. बहुत सारे बड़े नाम, जिन्हें पत्रकारिता की एबीसीडी नहीं आती, सिर्फ टेलीविजन पर बैठकर चीखते हैं, उन्हें पूरे हिन्दुस्तान में कितनी गालियां मिल रही हैं, अभी नहीं पता, लेकिन आगे पता चलेगा.

> मैं तीन महीने के बाद कश्मीर गया. देश के कई क्षेत्रों के पत्रकार कश्मीर में मिले. सबने लगभग यही राय बताई. लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार और टेलीविजन चैनल कश्मीर की समस्या से जरा भी परेशान नहीं दिखाई दिए. वो क्यों परेशान नहीं हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम ये बता दें कि कश्मीर में जब से लड़कियों ने हाथ में पत्थर उठाए हैं, तब से वहां माहौल अजीब तरह से बदल रहा है. हमने जब पता किया कि लड़कियों ने पत्थर क्यों उठाए, तो इसके कई कारण नजर आए. लेकिन जिस कारण की ओर सबने इशारा किया, वो ये है कि टेलीविजन चैनल जिस तरह से लड़कियों के पत्थर चलाने को एक इवेंट बनाकर देश के सामने और दुनिया के सामने रख रहे हैं, उसकी वजह से हर स्कूल के भीतर छात्रों के बीच पत्थर चलाना दुख का, दर्द का, परेशानी प्रकट करने का और साथ ही एक ग्लैमरस इवेंट का हिस्सा होने का कारण बन गया है.

सिविल सोसायटी के लोग दिल्ली में, मुंबई में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और केन्द्र सरकार के पास अपनी प्रार्थना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कश्मीर के लोगों से बातचीत करें. सिविल सोसायटी के लोग कश्मीर जा रहे हैं. हालांकि ये सच है कि उनके जाने से स्थिति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन कश्मीर के लोगों को ये सांत्वना मिल रही है कि कम से कम हिन्दुस्तान में एक तबका है जो उनकी तकलीफ समझना चाहता है. लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जब तक सरकार प्रतिक्रिया नहीं देती या बातचीत करने का इशारा नहीं देती, तबतक कश्मीर की समस्या के हल की तरफ एक इंच भी नहीं बढ़ा जा सकता.

कश्मीर में स्थिति हर महीने बदल रही है. कश्मीर में स्थिति बदलने का दारोमदार कश्मीर के प्रशासन पर है. स्थिति बदलने का कारण भारत सरकार का बातचीत न करने का हठ है. स्थिति बदलने का कारण नौजवानों का अपने से बड़ी उम्र की लीडरशिप के ऊपर से विश्वास का उठना भी है. हकीकत ये है कि राजनीतिक पार्टियों के लोग अपने चुनाव क्षेत्रों में नहीं जा पाते. गिने-चुने लोग हैं, जो चुनाव क्षेत्रों में जाते हैं. मेरी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हुई, पीडीपी के लोगों से हुई, कांग्रेस के लोगों से हुई, मेरी मुलाकात हुर्रियत के लोगों से हुई और सबने जो भाषा बोली उस भाषा में कौमा और फुलस्टॉप से ज्यादा का अंतर नहीं है. किसी ने पूरे वाक्य में कौमा लगाया, किसी ने नहीं लगाया, बस इतना ही फर्क है. लेकिन भाषा का तथ्य, भाषा का तत्व, भाषा का मिजाज और भाषा का दर्द लगभग सबकी जुबान में एक ही जैसा मिला. पूरे कश्मीर में लोगों को ये दर्द है कि टेलीविजन चैनलों में जो लोग बैठकर बातचीत करते हैं, वो कभी कश्मीर आए भी हैं या नहीं आए हैं या वे किसी एक एजेंडे के तहत कश्मीर के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, मानो कश्मीर के लोग भारत के दुश्मन हैं और उनके ऊपर वैसे ही बम गिरा देना चाहिए जैसे हम दुश्मनों के ऊपर, अगर जरूरत पड़े तो बम गिराएंगे.

ये जो कश्मीर की तकलीफ है, कश्मीर का दर्द है, कश्मीर की शिकायत है, कश्मीर के आंसू हैं, इन सबको हिन्दुस्तान के लोगों को समझने की जरूरत है. हम अपनी नादानी में या प्रशासनिक महाबुद्धिमानी में उन लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जिन्हें हम अपना अभिन्न अंग कहते हैं. कश्मीर में कई लोगों ने मुझे कहा कि अगर भारत का ये कहना है कि कश्मीर उसका अभिन्न अंग है, तो क्या अभिन्न अंग ऐसा ही होता है कि उससे बातचीत न की जाए, उससे तकलीफ न पूछी जाए, उसकी समस्याओं को हल न किया जाए. अब ये बात परेशान करने वाली है कि एक तरफ तो हम कश्मीर के लोगों को हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग मानते हैं और दूसरी तरफ हम उनसे बात नहीं करते. भले ही सही, भले ही गलत, भले ही कुटिल, कोई भी बात हो, लेकिन क्या सरकार इतनी कमजोर है कि बातचीत करने से उसकी शान चली जाएगी या साख चली जाएगी. सरकार बड़ी चीज है. सरकार सारे देश की सरकार है और उसे अपने लोगों से बातचीत करने में शर्म क्यों आनी चाहिए. उसे अपने लोगों से बातचीत करने में हिचक क्यों होनी चाहिए. लेकिन कश्मीर के लोगों का ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी के विश्वासपात्र जब तक नहीं आते, तब तक कोई भी बातचीत करने का किसी तरह का फायदा नहीं है. आखिर में एक चीज और. कश्मीर के कुछ दर्दमंद लोगों ने एक राय दी कि सरकार को चाहिए कि फौरन कश्मीर के नौजवानों से बातचीत करे. जब मैंने पूछा कि बातचीत करने का तरीका क्या हो सकता है, तो लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो स्कूलों और कॉलेजों में जाएं और उनसे बातचीत शुरू करें. इन नौजवानों का कोई लीडर नहीं है. इन नौजवानों का लीडर इनका मूड है और इनकी निराशा है. इसलिए सरकार को चाहिए कि कश्मीर के छात्रों से बातचीत करे और उन छात्रों के मन से निराशा को निकाल कर उन्हें अच्छे भविष्य का विश्वास दिलाए. कश्मीर के नौजवान मिले और उन्होंने कहा कि जो पत्थर मारते हैं, उनसे ज्यादा वे लोग हैं, जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जो अच्छे संगीतज्ञ हैं, जो अच्छा वाद-विवाद करते हैं, जो अच्छे समाजशास्त्री हैं, इन लोगों के लिए कश्मीर में कोई आशा नहीं है, इनके लिए कोई जगह नहीं है. क्या सरकार कोई ऐसी योजना नहीं बना सकती, जिससे कश्मीर के नौजवानों को अपना भविष्य दिखाई दे. मेरा ख्याल है, ये सब हो सकता है, बशर्ते प्रधानमंत्री स्वयं इस तरफ ध्यान दें. कश्मीर के लोगों का किसी और मंत्री में कोई विश्वास नहीं है. उन्हें लगता है कि जिस तरह संपूर्ण भारत को या संपूर्ण नीतियों को प्रधानमंत्री अपनी सोच से प्रभावित करते हैं, उसी तरह उन्हें कश्मीर में भी वहां की स्थिति को प्रभावित करना चाहिए और कश्मीर के लोगों से एक बार मन की बात करनी चाहिए.■

> कश्मीर में लगभग सभी लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं. वे भारत सरकार से बातचीत करना चाहते हैं. हालांकि उन्हें लगता है कि बातचीत से क्या निकलेगा, क्योंकि भारत की सरकार कश्मीर के लोगों को वो चीजें भी मुहैया नहीं करा रही है, जो मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश के लोगों को हासिल है. यानि वो आज़ादी, जिसे मीटिंग करने की आज़ादी कहते हैं, अपनी शिकायत करने की आज़ादी कहते हैं, जलसे-जुलूस निकालने की आज़ादी कहते हैं, वो कश्मीर के लोगों को नहीं है. कश्मीर में अब सरकार उसी रास्ते जा रही है, जिस रास्ते वो आज से 15 साल पहले पंजाब में गई थी.

editor@chauthiduniya.com

उकसावे और ध्रुवीकरण की राजनीति का प्रयोगस्थल बन गया सहारनपुर

सियासत जारी, हिंसा जारी

अंबेडकर जयंती से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा

सूफी यायावर

सहारनपुर का मसला दिल्ली तक पहुंच गया. अंबेडकर जयंती से उठा विवाद अब तक सुलग रहा है. सहारनपुर विवाद में हत्या, हमला, हिंसा, प्रदर्शन सब हुए, लेकिन इसे तूल देने का सिलसिला नहीं थमा. अब दिल्ली घेरने का क्रम भी इसमें शामिल हो गया. सहारनपुर के एसएसपी आवास पर हुए हमले के बाद प्रदेश के राजनीतिक दलों ने भी अपनी-अपनी रोटियां सेंकीं. समाजवादी पार्टी ने अपना अलग से जांच दल भेज दिया तो ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट से जुड़े संगठनों ने भी अपना जांच दल भेजा और योगी सरकार पर तमाम आरोप मढ़े. किसी भी पार्टी ने सहारनपुर विवाद की जड़ में झांकने की कोशिश नहीं की और न ही वहां हुई हत्या के कारणों की ओर ईमानदारी से देखने की कोशिश की. राजनीतिक दलों को वैसे भी वोट-बैंक के अलावा कहां कुछ दिखता है!

समाजवादी पार्टी ने अपनी जांच रिपोर्ट में घटना के लिए भाजपा नेताओं के कोप को कारण बताया. सपाई जांच दल के मुखिया महबूब अली थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि सहारनपुर कांड को अंजाम देने में भाजपा विधायक, भाजपा जिलाध्यक्ष और अन्य भाजपा नेताओं की भूमिका है. विवाद 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती से ही शुरू हुआ, जब जिला प्रशासन ने किसी भी जुलूस के निकाले जाने की इजाजत नहीं दी थी. इसके बावजूद 500 कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाल दिया. प्रशासनिक अधिकारियों पर भी हमला किया गया. जमकर अराजकता हुई, लेकिन दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया. सपा कहती है कि राजनीतिक फायदे के लिए पूरी घटना कराई गई. सपा ने सहारनपुर मामले की न्यायिक जांच की मांग की. सपा की इस जांच रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि यह महज एक राजनीति-प्रेरित रिपोर्ट है. किसी राजनीतिक दल की जांच रिपोर्ट को कार्रवाई का आधार नहीं बनाया जा सकता. यह किसी पुलिस या अन्य एजेंसी की रिपोर्ट नहीं है.

दूसरी तरफ ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट से जुड़े सामाजिक संगठनों के 28 प्रतिनिधियों के जांच दल ने भी अपनी जांच रिपोर्ट दी है. जांच दल में उत्तर प्रदेश जन मंच, स्वराज अभियान जैसे संगठनों के सदस्य भी शरीक थे. जांच दल ने पांच मई और उसके बाद के घटनाक्रम को ही जांच के दायरे में रखा और बताया कि सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में दलितों के खिलाफ हिंसा हुई, जिसमें दलितों के 60 घर जले और 14 दलित जख्मी हुए. दूसरे पक्ष से कितने लोग जख्मी हुए और कितने घरों को नुकसान पहुंचा, जांच दल ने इसे अपनी जांच के दायरे में नहीं रखा. जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पांच मई को सहारनपुर के सिमलाना गांव में महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन किया गया था. स्थानीय प्रशासन ने केवल सभा करने की अनुमति दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने जुलूस निकाला. जांच दल का आरोप है कि जुलूस में महाराणा प्रताप की जय और अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए. इसपर दलितों ने आपत्ति की और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने हस्तक्षेप कर जुलूस को आगे बढ़ा दिया. जांच दल कहता है कि थोड़ी देर बाद कुछ लोगों ने दलित आबादी पर हमला कर दिया और रविदास मंदिर में तोड़फोड़ की. इस पर दलितों ने आत्म-रक्षा में पथराव किया. इस दौरान दूसरे पक्ष के जिस लड़के की हत्या हुई, उसके तथ्य जांचने के बजाय जांच दल ने कहा कि सुमित नाम के एक लड़के की संदेहजनक परिस्थितियों में मौत हो गई थी. जांच दल फिर खुद ही कहता है कि उसकी मौत का कारण दम घुटना पाया गया.जांच दल खुद ही यह प्रमाणित भी करता है कि घटनास्थल पर इस प्रकार का कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया जिससे यह कहा जा सके कि उस लड़के को दलितों ने मारा था. हिंसा में एक और युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ. इस बारे में जांच दल ने हल्का उल्लेख किया और इतना ही कहा कि वह जौली ग्रांट हॉस्पीटल में भर्ती है.

शब्बीरपुर घटना में पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं. कुल छह मुकदमे दर्ज किए गए हैं. जिला प्रशासन का कहना है कि सभी घायलों को चोटों की गंभीरता के मुताबिक आर्थिक सहायता दी गई है. घटना से प्रभावित दलितों को एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत मुआवजा देने की कार्रवाई चल रही है. 20 अप्रैल को हुई घटना के दोषी भाजपा सांसद राघव लखनपाल शर्मा के खिलाफ पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है.

दिल्ली के जंतर-मंतर तक गूंजा दलितों का ग़ुस्सा

सहारनपुर कांड के खिलाफ दलितों का गुस्सा 21 मई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर गूंजा. इस प्रदर्शन का आयोजन भीम आर्मी ने किया था. भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ सहारनपुर में दर्ज मुकदमों पर प्रदर्शन में रोष व्यक्त किया गया. सभा को भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर, विजय रतन, रवि कुमार गौतम, जयभगवान जाटव, कंवर सिंह बदलिया, शांति स्वरूप बौद्ध, प्रो. हंसराज सुमन, वीपी सिंह लिब्रा, गुजरात के जिग्नेश मेवानी, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत कई लोगों ने संबोधित किया. भीम आर्मी ने यहां तक धमकी दे डाली कि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो देश के ज्यादातर दलित बौद्ध धर्म अपना लेंगे. अपने ऊपर लगे नक्सली कनेक्शन के आरोप पर चंद्रशेखर ने कहा कि समाज के हित के लिए उन्हें नक्सली होना भी स्वीकार्य है.

दरअसल, सहारनपुर प्रकरण में भीम आर्मी का प्रवेश नौ मई को हुआ जब उनलोगों ने स्थानीय रविदास छात्रावास में बैठक बुलाई. पुलिस ने उन्हें हॉस्टल में बैठक करने की इजाजत नहीं दी और उन्हें गांधी मैदान जाने को कहा. भीम आर्मी के सदस्यों का कहना है कि वहां से भी पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया. इसके बाद भीम आर्मी ने शहरभर में तांडव मचाना शुरू कर दिया. पुलिस ने इस सम्बन्ध में भीम सेना के सदस्यों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए और तकरीबन तीन दर्जन गिरफ्तारियां कीं.

मायावती बोलें तब आपत्ति न बोलें तब आपत्ति

कुछ लोगों को मायावती कुछ बोलें तब भी आपत्ति होती है और वे कुछ न बोलें तब भी आपत्ति होती है. ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के प्रवक्ता एसआर दारापुरी ऐसे ही नेताओं में शुमार हैं. दारापुरी को आपत्ति है कि मायावती ने सहारनपुर कांड पर चुप्पी क्यों साधे रखी. दारापुरी ने उत्तर प्रदेश जनमंच के प्रवक्ता और स्वराज अभियान के सदस्य के बतौर बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि एक तरफ मायावती हरिशंकर तिवारी के घर पर दबिश के मामले में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष को गोरखपुर भेजती हैं और विधानसभा से वाक-आउट कराती हैं, लेकिन दूसरी तरफ सहारनपुर कांड पर चुप्पी साधे रहती हैं, न खुद मौके पर जाती हैं और न अपने किसी प्रतिनिधि को वहां भेजती हैं. दारापुरी को इस बात की नाराजगी है कि भीम सेना के सदस्यों की गिरफ्तारी के मसले पर भी मायावती खामोश क्यों हैं. बसपा नेता मायावती के चुप्पी तोड़ने और सहारनपुर का दौरा करने के बाद भीदारापुरी ने अपना अप्रासंगिक तथ्यहीन बयान वापस लेने सम्बन्धी कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की.

दारापुरी के दावे के विपरीत असलियत यह है कि पांच मई की घटना के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने अफसोस और चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि राज्य में साम्प्रदायिक घटनाओं के बाद अब जातीय संघर्ष की वारदात से उत्तर प्रदेश आक्रांत होने लगा है. इससे यह साबित होता है कि बेहतर अपराध-नियंत्रण और कानून-व्यवस्था सत्तारूढ़ भाजपा के वश की बात नहीं है. मायावती ने कहा कि बिना अनुमति के जुलूस निकालना और उस दौरान मनमानी करके वातावरण को प्रदूषित और हिंसक बनाना वास्तव में एक फैशन जैसा हो गया है, जिसको रोक पाने में प्रदेश सरकार नाकाम साबित हो रही है. राज्य सरकार असामाजिक और आपराधिक तत्वों के सामने बौनी दिख रही है. बिना अनुमति के जुलूस निकालने और इसे लेकर नई परंपरा की शुरुआत करने वाले लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए मायावती ने कहा था कि भाजपा सरकार को अब अपनी कथनी और करनी के अंतर को समाप्त करके प्रदेश में कानून-व्यवस्था बेहतर बनाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए. मायावती फिर 23 मई को सड़क मार्ग से सहारनपुर भी पहुंचीं और पीड़ित दलित परिवारों से मिलीं. मायावती ने पीड़ित परिवारों की मदद के लिए पार्टी फंड से मुआवजे का ऐलान किया और कहा कि जिनके घर जले उन्हें 50 हजार रुपए और जिनका अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ है उन्हें 25 हजार रुपए दिए जाएंगे. मायावती ने शब्बीरपुर गांव में मंच से यह घोषणा की. मायावती ने कहा कि सहारनपुर दंगा भाजपा ने कराया है. मायावती के शब्बीरपुर पहुंचने के पहले भी दलित समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों के घरों में आगजनी की और मायावती के वापस लौटने के बाद भी हिंसक घटनाएं जारी रहीं, जिसमें कई लोग जख्मी हुए. ■

सहारनपुर के साथ सियासत

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सम्पन्न सहारनपुर को राजनीतिक पार्टियों का ग्रहण लग गया है. सियासी रोटियां सेंकने वालों ने जिले को अपने घेरे में ले लिया है. मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, देहरादून, यमुना नगर और शामली से घिरा सहारनपुर यूपी को उत्तराखंड और हरियाणा से जोड़ता है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिले साम्प्रदायिक दंगों के हिसाब से संवेदनशील माने जाते हैं लेकिन सहारनपुर अपेक्षाकृत शांत और बेहतर जिला रहा है. सहारनपुर में कभी दंगे नहीं हुए. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सहारनपुर को जातीय और साम्प्रदायिक सियासत का केंद्र बना दिया गया. सहारनपुर की राजनीति में बसपा महत्वपूर्ण कड़ी रही है. साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण से पहले बसपा, सपा और कांग्रेस सहारनपुर की राजनीति को नियंत्रित करती थी. जातीय समीकरणों के हिसाब से भी सवर्णों के लिए यह सीट बहुत मज़बूत नहीं थी. मुसलमानों की संख्या 45 प्रतिशत से अधिक होने के कारण 26 प्रतिशत आबादी के ध्रुवीकरण की सियासत में भाजपा कामयाब हो गई. बसपा की इस जिले में पकड़ खास तौर पर दलित समुदाय के चमार जाति की बहुलता के कारण हुई थी. कहते हैं कि 1989 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित वोट बहुलता से नहीं पड़ता था, लेकिन बसपा के उदय से दलितों, पिछड़ों और पसमांदा मुसलमानों का गठबंधन मजबूत होता गया. इससे सवर्ण वर्चस्व कम होता गया. उत्तर प्रदेश के चुनावों में भारी जीत के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं. अब स्थानीय निकायों के चुनाव सामने हैं. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पूरे भारत में पंचायत से लेकर संसद तक भाजपा का नेतृत्व चाहते हैं. इसके लिए भाजपा को जो भी उपक्रम करना पड़े, वह करेगी. स्थानीय निकायों में जीतने के लिए दलितों का साथ भी चाहिए और उन्हें उकसाना भी चाहिए. सहारनपुर की घटना को गौर से देखें तो यह सवाल उठेगा कि जब अंबेडकर जयंती पूरे देश में 14 अप्रैल को मना ली गई थी तो 20 अप्रैल को सहारनपुर में जबरन जुलूस निकालने का क्या औचित्य था. जुलूस के कंधे पर रख कर गहरी सियासत की साजिश तो नहीं रची जा रही थी! सहारनपुर से भाजपा सांसद रामलखन पाल शर्मा ने पुलिस प्रशासन की परवाह किए बगैर जो शोभा यात्रा निकाली वह बिल्कुल गैरकानूनी थी, लेकिन शर्मा पर कोई कार्रवाई करने के बजाय हिंसक भीड़ के हमले का शिकार हुए एसएसपी लव कुमार का ही तबादला कर दिया गया. एसएसपी के शासकीय आवास पर सांसद के समर्थकों ने हमला किया लेकिन सरकार ने सांसद को आड़े हाथों लेने के बजाय एसएसपी को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया. लव कुमार की जगह सहारनपुर के जो नए एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे आए, उनके बारे में खबर है कि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान वे वहां के एसएसपी थे और पूर्व न्यायाधीश विष्णु सहाय की जांच में उन्हें दंगों को न रोक पाने का दोषी पाया गया था. बहरहाल, सहारनपुर के इस तरह के छोटे-बड़े बलवे लगातार बढ़ रहे हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो एक खुशहाल क्षेत्र रहा है, जहां के किसान राजनीतिक-आर्थिक तौर पर ताकतवर रहे हैं, आज वहां से खुशहाली गायब हो रही है. खेती खतरे में है, किसानों के मुद्दे गायब हैं. किसानों के मुद्दों को साम्प्रदायिकता और जातीय विद्धेष के जहर में घोल दिया गया है. इस क्षेत्र ने मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, बरेली, बिजनौर, मलियाना जैसे भयानक दंगे देखे हैं और उन्हें भुगता है. सहारनपुर हिंसा के कारणों की विस्तार से जांच होनी चाहिए. संसद या विधानसभा की शीर्ष सर्वदलीय समिति से मामले की जांच करानी चाहिए. सारे दलों को ऐसा वैधानिक रास्ता निकालना चाहिए कि जिन नेताओं का नाम जातीय या साम्प्रदायिक दंगा फैलाने में आए, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट न मिले. ■

feedback@chauthiduniya.com

कर्नाटक कैडर के आईएएस अफसर की लखनऊ में हत्या!

फिर मारा गया ईमानदार

- योगी ने की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश
- कर्नाटक का बड़ा घोटाला खोलने की थी तैयारी
- डिलीट पाए गए ई-मेल संदेश और कॉल डिटेल्स
- यूपी कैडर के बैच-मेट अफसर की संदिग्ध भूमिका

दीनबंधु कबीर

कर्नाटक कैडर के आईएएस अफसर अनुराग तिवारी की लखनऊ में पिछले दिनों हुई संदेहास्पद मौत पूरे प्रदेश में चर्चा के केंद्र में है. अनुराग के परिजनों का भी कहना है कि अनुराग की सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है. उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले अनुराग तिवारी की लाश पिछले दिनों लखनऊ के मीरा बाई मार्ग स्थित राजकीय अतिथि गृह के सामने सड़क पर पाई गई थी, उसी दिन आईएएस अफसर का जन्मदिन भी था. बहराइच के रहने वाले सामान्य मध्यवर्गीय परिवार के लिए अनुराग का आईएएस बनना पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय था, लेकिन उनका इस तरह मारा जाना प्रदेश के लोगों के लिए आज क्षोभ और नाराजगी का विषय बना हुआ है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की औपचारिक अनुशंसा कर दी है. सीबीआई से जांच कराने की मुख्यमंत्री की सिफारिश ने प्रथम द्रष्टया यह बता दिया है कि आईएएस अफसर अनुराग तिवारी की मौत हत्या है और इसके पीछे बहुत सुनियोजित साजिश है. लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात आईएएस प्रभु नारायण सिंह संदेह के घेरे में हैं. उनसे पूछताछ भी हुई है, लेकिन जो पूछताछ हुई है, वह काफी लचर है, पूछताछ की केवल औपचारिकता निभाई गई है. आईएएस अफसर अनुराग तिवारी के परिजन अनुराग के बैच-मेट रहे एलडीए वीसी प्रभु नारायण सिंह का पूरा सहयोग चाहते हैं ताकि मौत के रहस्य से पर्दा उठ सके. कर्नाटक कैडर के आईएएस अफसर अनुराग तिवारी और यूपी कैडर के आईएएस अफसर प्रभु नारायण सिंह, दोनों ही मीराबाई मार्ग के राजकीय अतिथि गृह में रुके हुए थे. अनुराग के भाई मयंक तिवारी ने आधिकारिक तौर पर कहा कि उनके पास कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो वे सीबीआई के सामने रखेंगे. मयंक बोले कि आईएएस अफसर प्रभु नारायण सिंह उनके भाई के बहुत निकट थे और उनका परिवार उन पर भरोसा करता था. अब हम चाहते हैं कि सिंह सामने आकर पूरी बात बताएं और इस मामले में अपनी सारी जानकारी परिवार को दें.

अनुराग तिवारी की मां सुशीला तिवारी, भाई मयंक तिवारी और भाभी सुधा तिवारी 22 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और मामले की सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने पहले उन्हें एफआईआर कराने की सलाह दी. एफआईआर के साथ लखनऊ के एसएसपी दीपक कुमार ने सीबीआई से जांच कराने सम्बन्धी अपना मंतव्य भी संलग्न कर दिया. एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद मुख्यमंत्री ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की औपचारिक सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी. गृह विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की. अनुराग तिवारी के भाई मयंक तिवारी की तहरीर पर हजरतगंज कोतवाली में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया. गृह विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार ने कहा कि जरूरी कार्रवाई शीघ्र पूरी कर मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाएगी. अनुराग तिवारी के भाई मयंक तिवारी की तहरीर पर दर्ज एफआईआर के मुताबिक 17 मई की अल्ल सुबह सड़क पर उनकी लाश का पाया जाना पूरी तरह संदेहास्पद है, क्योंकि अनुराग सुबह नौ बजे के पहले कभी उठते ही नहीं थे. अनुराग की ईमानदारी उनके लिए हमेशा संकट का सबब बनती रही. 10 वर्ष में उनका आठ बार तबादला हुआ. अनुराग ने अपने भाई को बताया था कि वे कर्नाटक का एक बड़ा घोटाला खोलने पर काम कर रहे हैं. उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे घोटाले की जांच दबा दें. अनुराग ने यह भी कहा था कि कुछ लोग उन पर कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी दबाव बना रहे हैं. दो महीने पहले अनुराग ने कहा था कि उनकी जान को खतरा है. इन तथ्यों के बाहर आने से यह स्पष्ट हो रहा है कि आईएएस अफसर अनुराग तिवारी सुनियोजित षडयंत्र का शिकार हुए.

मामले की पहले से जांच कर रही एसआईटी की भूमिका भी संदेह से परे नहीं है. एसआईटी ने एलडीए के वीसी प्रभु नारायण सिंह का बयान दर्ज किया, लेकिन दर्ज बयान को लचर और आधा-अधूरा बताया जा रहा है. फिर से बताते चलें कि मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में आईएएस अनुराग तिवारी अपने बैच-मेट प्रभु नारायण सिंह के साथ एक ही कमरे में रुके हुए थे. 17 मई की सुबह उनका शव संदिग्ध हालात में गेस्ट हाउस के सामने सड़क पर मिला था. परिवार के लोग पहले दिन से ही अनुराग की हत्या की आशंका जता रहे हैं. संदेहास्पद यह भी है कि एसआईटी ने अनुराग के शव का पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टरों के पैनल से कोई पूछताछ नहीं की. जबकि डॉक्टरों के पैनल का बयान इस मामले में काफी अहम है. इसके अलावा एसआईटी ने पीड़ित परिजनों से भी बातचीत नहीं की. एसआईटी ने गेस्ट हाउस के कर्मचारियों से पूछताछ की और यह जानने की कोशिश की कि कमरा नम्बर-19 में फीकी चाय किसके लिए जाती थी, लेकिन यह जानने की कोशिश नहीं की कि कमरे में ढेर सारे सिगरेट के बड क्यों जमा थे. कमरे से सिगरेट के इतने बड मिले, जिन्हें कोई चेन-स्मोकर भी एक रात में पी नहीं सकता. अनुराग गेस्ट हाउस से कब बाहर निकले और उस समय ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी ने क्या देखा.

अनुराग तिवारी की संदेहास्पद मौत के तार कितने लंबे और गहरे हैं कि प्रदेश की फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री की जांच को भी संदेह में लिपटा पाया गया और अचानक एफएसएल से जांच वापस ले ली गई. सरकार ने यह तय किया कि स्टेट एफएसएल से जांच नहीं कराई जाएगी. लखनऊ के एसएसपी दीपक कुमार ने कहा कि आईएमएस बीएचयू, एम्स और सेंट्रल फॉरेंसिक लैब को इस जांच में शामिल किया जाएगा. ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मामले की जांच स्टेट एफएसएल से वापस ले ली गई. संदेहास्पद तथ्य यह है कि अनुराग के शव के पोस्टमॉर्टम के लिए चार डॉक्टरों का पैनल होने के बावजूद स्टेट एफएसएल का एक अधिकारी पोस्टमॉर्टम कक्ष में हाजिर था और डॉक्टरों को निर्देश दे रहा था. वह अधिकारी कौन था, उसकी पहचान हो चुकी है और वह जांच के रडार पर है. अनुराग के परिजनों ने भी कहा था कि वे स्टेट एफएसएल के निदेशक की देख-रेख में अनुराग की मौत की जांच नहीं चाहते. अनुराग के परिजनों ने ऐसा क्यों कहा था, इसके भी सूत्र तलाशे जा रहे हैं. अनुराग के बड़े भाई मयंक का कहना है कि अनुराग ने उनको फोन करके उन्हें और परिवार के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा था. अनुराग ने यह आशंका जाहिर की थी कि सबके मोबाइल सर्विलांस पर हैं और उनकी बातें कहीं से सुनी जा रही हैं. अनुराग की मां सुशीला तिवारी ने कहा कि अनुराग ने उनसे नौकरी छोड़ने की बात कही थी. अनुराग के परिजनों ने पुलिस को कुछ वॉट्सऐप संदेश और एसएमएस भी दिखाए, जो धमकियों के रूप में कहीं से भेजे गए थे.

हजरतगंज के आर्यन होटल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें अनुराग तिवारी और लखनऊ एलडीए के वीसी प्रभु नारायण सिंह साथ-साथ दिख रहे हैं. जिस गेस्ट हाउस में अनुराग रुके थे, वहां का कमरा भी सिंह के नाम पर ही बुक था. विचित्र बात यह है कि इन सारी जानकारियों के बावजूद लखनऊ पुलिस ने एलडीए वीसी से गहराई से कोई पूछताछ नहीं की. अनुराग के भाई मयंक तिवारी जोर देकर कहते हैं कि उनके भाई की हत्या करवाई गई. मयंक का कहना है कि अनुराग तिवारी की फोन कॉल हिस्ट्री भी गायब है. अनुराग को उनकी मां व घर के अन्य सदस्यों ने फोन करके जन्मदिन की अग्रिम बधाई दी थी, लेकिन ये कॉल्स फोन की कॉल-हिस्ट्री से गायब हैं. अनुराग तिवारी हमेशा अपने मोबाइल में पैटर्न-लॉक लगा कर रखते थे. लेकिन जब मोबाइल बरामद हुआ तो वह अनलॉक पाया गया. अनुराग हमेशा अपना मोबाइल अपने साथ ही रखते थे, जबकि पुलिस को उनका फोन गेस्ट हाउस के कमरे से मिला. अनुराग तिवारी ने घर के सदस्यों के सामने ही कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी को ई-मेल भेजा था. यह मेल सेंट आइटम से डिलीट है. अनुराग तिवारी का वेतन स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के अकाउंट में जाता था. अनुराग के भाई कहते हैं कि अनुराग का डेबिट कार्ड उसके पर्स में ही रहता था, वह भी गायब है. मयंक तिवारी का कहना है कि अनुराग के मोबाइल पर दुबई से फोन आया था. कॉल रिसीव नहीं हुई थी. मयंक कहते हैं कि अनुराग उनसे कोई बात नहीं छुपाता था. अनुराग का कोई दोस्त या परिचित दुबई में नहीं रहता है. लिहाजा, दुबई से आने वाले फोन की जांच होनी चाहिए. अनुराग के भाई ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान भी कहा कि अनुराग किसी बड़े घोटाले की जांच कर रहे थे और उन पर किसी कागज पर साइन करने का दबाव बनाया जा रहा था. इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई. लखनऊ पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए मयंक तिवारी ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि संदेहास्पद मामला होने के बावजूद पुलिस ने गेस्टहाउस का कमरा सील नहीं किया. अनुराग के मोबाइल फोन की तमाम जानकारियां व ई-मेल डिलीट कर दिए गए हैं. ■

किसने पी इतनी ढेर सारी सिगरेट!

लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित गेस्ट हाउस के रूम नम्बर-19 से सिगरेट के ढेर सारे बड्स बरामद किए गए. सिगरेट में कहीं ड्रग्स या कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं मिलाया गया था? यह सवाल अभी अधूरा ही है. कोई चेन-स्मोकर भी इतनी अधिक मात्रा में सिगरेट नहीं पी सकता, कहीं उस रात कमरे में एक से अधिक लोग तो नहीं थे? गेस्ट हाउस के कर्मचारियों से पूछताछ हुई तो सबने एक सुर में जवाब दिया कि उन्होंने साहब को बाहर जाते नहीं देखा. स्पष्ट है कि यह रटा-रटाया जवाब था. अनुराग की लाश का सड़क पर पाया जाना ही एक सुर के जवाब की पोल खोलता है. मंगलवार 16 मई की रात 10 बजे से बुधवार सुबह 6 बजे तक मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस के कनिष्ठ सहायक जितेंद्र वर्मा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कृष्णा चतुर्वेदी ड्यूटी पर थे. ■

आईएएस-माफिया ने कराई अनुराग की हत्या

एमएन विजय कुमार

कर्नाटक के पूर्व आईएएस अधिकारी एमएन विजय कुमार ने खुल कर कहा है कि कर्नाटक के आईएएस-माफियाओं ने कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी अनुराग तिवारी की लखनऊ में हत्या करा दी. विजय कुमार ने कहा कि कर्नाटक में घोटाले का खुलासा करना बहुत ही जोखिम का काम है. घोटाला पकड़ने की वजह से ही कई वरिष्ठ अधिकारी अनुराग से नाराज थे, इनमें कर्नाटक के मुख्य सचिव एससी कुंठिया भी बराबर के शरीक हैं. कर्नाटक के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी विजय कुमार ने बंगलूरू में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सीधे तौर पर कर्नाटक सरकार और वहां की शीर्ष नौकरशाही को कठघरे में खड़ा कर दिया. विजय कुमार ने साफ-साफ कहा कि कर्नाटक में घोटाला उजागर करने वाले आईएएस अधिकारियों की मौत हो जाती है. अनुराग तिवारी की मौत भी इसी की कड़ी है. विजय कुमार ने बताया कि अनुराग तिवारी खाद्य एवं रसद विभाग का 2000 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर करने जा रहे थे. अनुराग ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी थी, इसीलिए सीनियर आईएएस अनुराग से खफा थे. मामला दबाने के लिए उन्हें मोटी रकम देने की पेशकश भी की गई थी. इन्कार करने पर उन्हें धमकियां मिल रही थीं. ट्रेनिंग पर जाने से दो दिन पहले उन्होंने घोटालों से जुड़े दस्तावेज कर्नाटक सरकार को सौंपे थे, लेकिन शासन ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की. विजय कुमार ने कहा कि उन्होंने अनुराग और कर्नाटक सरकार से जुड़े कई अहम दस्तावेज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी और आईजी समेत कई अन्य अधिकारियों को भेजे हैं, लेकिन इस बारे में यूपी की शीर्ष नौकरशाही भी चुप्पी साधे बैठी है. ■

ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से समाज की तस्वीर बदलना चाहते थे

कर्नाटक कैडर के आईएएस अफसर अनुराग तिवारी में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से समाज की तस्वीर बदलने की चाहत थी. अनुराग जिस जगह तैनात रहते थे, वहां के लोगों के काफी चहेते रहते थे. जानकार बताते हैं कि अनुराग ने सूखे से जूझते बिदार जिले की तस्वीर बदल दी थी. कर्नाटक के बिदार जिले के लोग वर्ष 2015-16 को कभी नहीं भूल सकते. उस साल बिदार में भयंकर सूखा पड़ा था. उस समय अनुराग तिवारी बिदार में ही तैनात थे. बिदार के लोग कहते हैं कि अनुराग तिवारी के योगदान को कोई कभी भूल नहीं सकता. अनुराग ने महज 18 महीने के अथक प्रयास से बिदार के लोगों को सूखे से राहत दिला दी थी. 'बेटर इंडिया' की रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है कि सदियों पुराने भूमिगत जलसेतु बावी-सुरंग के पुनरुत्थान के अलावा अनुराग ने 130 से ज्यादा तालाबों और 110 से ज्यादा खुले कुओं की सफाई कराई जिससे ज़िले के लोगों को पानी की कमी की समस्या से न जूझना होना पड़े. बिदार के लिए यह काम नए जीवन की तरह था. फिर बारिश हुई तो सारे तालाब और कुएं पानी से भर गए. लंबे समय तक के लिए बिदार के लोगों को पानी की भयंकर किल्लत से मुक्ति मिल गई. मध्यकालीन युग का एक ऐतिहासिक कुआं 'जहाज की बावड़ी' लगभग पूरा सूख चुका था और इसमें लोग कूड़ा डालने लगे थे. अनुराग ने 80 फीट गहरे इस कुएं से कूड़ा निकलवाकर उसे साफ कराया. इसी का नतीजा है कि 500 साल पुराना कुआं अब इतना साफ है कि लोग इसका पानी पीने और घर के बाकी काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. अनुराग तिवारी ने राज्य सरकार की योजना 'केरे संजीवनी' के माध्यम से भी कई टैंकों को साफ करवाया. जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक कैडर के अधिकारी अनुराग तिवारी ने हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में एक टूरिस्ट सर्किट बनवाया और बिदार का किला देखने के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए ऑडियो विजुअल गाइड्स की व्यवस्था भी की थी. बिदार जिले के स्थानीय निकायों और मजिस्ट्रेट कोर्ट को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत करने का श्रेय भी अनुराग तिवारी को ही जाता है. कर्नाटक के लोग अनुराग तिवारी को 'जलपुरुष' कहते हैं. आम लोग कहते हैं कि ऐसे ईमानदार और कर्तव्यपरायण अधिकारी को सिस्टम सहन नहीं करता और उसे रास्ते से हटा देता है. अनुराग के साथ भी ऐसा ही हुआ. ■

आधुनिक तकनीक से भारत बन सकता है विश्व का सबसे बड़ा लीची निर्यातक

लीची से किसानों की ज़िन्दगी में आई मिठास

राकेश कुमार

भारत में सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन बिहार प्रदेश में होता है और बिहार में सबसे ज्यादा पूर्वी चम्पारण जिला के मेहसी परिक्षेत्र में होता है. कभी केन, कैश और क्राइम के लिए पहचाने जाने वाले चम्पारण में चीनी मिलों के बन्द होने के बाद गन्ना का उत्पादन नाम मात्र रह गया है. केन (गन्ना) को एकमात्र कैश (नकदी) फसल माना जाता था. गन्ना के फसल से इतना नकद प्राप्त होता था कि केन और कैश जिले की पहचान बन गए थे. कालान्तर में चीनी मिल बन्द होते चले गए और किसानों की आर्थिक स्थिति बदतर होती चली गई. सरकारें बदलती रहीं, लेकिन किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ. गन्ना के फसल की बदहाली के बाद एक लीची का ही फसल है जो आज कैश क्रॉप के रूप में देखा जाता है. राजनैतिक और प्रशासनिक उदासीनता के कारण लीची से उत्पादकों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है.

मेहसी परिक्षेत्र का अधिकतर भाग केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह के संसदीय क्षेत्र एवं कुछ भाग शिवहर सांसद रमा देवी के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है. यहां व्यापक पैमाने पर शाही लीची के साथ चायना लीची का उत्पादन होता है. पिछले दस साल से उत्कृष्ट लीची उत्पादन एवं उत्पादकों के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर लीचीपुरम उत्सव का आयोजन किया जाता है. किसानों के सहयोग से आयोजित होनेवाले इस कार्यक्रम के जरिए लीचीपुरम उत्सव समिति केंद्र एवं राज्य सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है, ताकि उच्च गुणवत्ता की लीची का व्यापार देश से लेकर विदेशी बाजारों तक हो सके और युवाओं को भी रोजगार मिल सके.

शहद उत्पादन की भरपूर क्षमता

इसी प्रकार वर्तमान में करीब 5 हजार टन शहद का उत्पादन होता है, जिसे 5 लाख टन तक ले जाया जा सकता है. लीची के बाग के अनुपात में मधुमक्खियों की संख्या कम होने के कारण पूरी तरह मंजर से निकलनेवाली शहद का दोहन नहीं हो पाता और शहद जमीन पर टपक कर बर्बाद हो जाता है.

मधुमक्खियां कम होने के कारण लीची के मंजरों का दशमलव एक प्रतिशत से भी कम परागण हो पाता है. यही कारण है कि हजार मंजर से ज्यादा में पांच से दस फल लगते हैं. अगर शहद उत्पादन पर ध्यान दिया गया होता तो किसानों की आर्थिक समृद्धि ही नहीं बढ़ती, बल्कि उत्पादन भी सौ गुना ज्यादा होता, जिससे देश-विदेश की जरूरतों को पूरा किया जा सकता था.

लीची का शहद स्वाद एवं गुणवत्ता के अलावा खनिज पदार्थों, मिनरल व विटामिन से भी भरपूर होता है. इसे बढ़ावा दिया जाए तो हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है. यहां बाबा रामदेव की पतंजलि जैसी या अन्य समकक्ष कोई बड़ी कंपनी की इकाई लगे तो इस परिक्षेत्र के हजारों किसानों एवं युवाओं की किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी.

पारंपरिक तरीक़े से कर रहे उत्पादन

यहां के लीची उत्पादकों को बेहतर उत्पादन के लिए नियमित प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है. प्रशिक्षण के अभाव में किसान वैज्ञानिक तरीके की बजाय पारंपरिक तरीके से ही लीची का उत्पादन करते हैं. लीची का फल मौसम की मार से ज्यादा प्रभावित होता है. कई बार ऐसा होता है कि बारिश या तेज धूप की वजह से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है.

यहां के किसान केंद्र एवं राज्य सरकार से प्रतिवर्ष लीची के फसल की बीमा कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर अब तक कोई प्रयास नहीं हुआ है. लीची किसानों को मौसम की मार का डर सताता रहता है. प्राकृतिक प्रकोप से बचाव के लिए निरंतर शोध की आवश्यकता है. लीची के फलों का एक बार ही एक साथ पकना एक बड़ी समस्या है. पेड़ से तोड़ते ही इसे मंडी तक पहुंचाने की हड़बड़ी रहती है, क्योंकि इसका रंग तेजी से खराब होने लगता है और यह अनाकर्षक दिखने लगती है. इस क्षेत्र में भी शोध की आवश्यकता है.

लीची ही इस क्षेत्र के किसानों के लिए एक प्रमुख नकदी फसल है, जिसका व्यापार करीब सौ करोड़ के पास है. इसके विकास की काफी संभावनाएं हैं. अगर कोई फूड प्रोसेसिंग कंपनी यहां व्यापार शुरू करे तो उत्पादन एवं व्यापार 5 हजार करोड़ के आंकड़े तक पहुंच सकता है. चीनी मिलों के बंद होने के बाद हजारों किसानों की आर्थिक आमदनी टूट गई थी. लीची ने उनके बीच एक उम्मीद जगाई है, जिससे किसान समृद्ध हो सकते हैं.

लीचीपुरम उत्सव से जगी उम्मीद

लीचीपुरम उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष लीची के फल के पकने पर किया जाता है. इस वर्ष यह आयोजन 27 से 29 मई तक होगा. आयोजन के पूर्व किसानों को लीची उत्पादन के लिए जागरूक करने के लिए समिति अभियान चलाती है. किसान इस उत्सव का आयोजन आपसी सहयोग से करते हैं.

लीची के मौसम के दौरान इंसेफ्लाइटिस नामक जानलेवा बीमारी का कहर बच्चों पर होता था. पिछले साल समिति द्वारा सघन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने के कारण एक भी मौत दर्ज नहीं की गई.

लीचीपुरम उत्सव समिति एक गैर राजनीतिक मंच है. 4 जून 2008 को इसके प्रथम कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था. इसके बाद यहां बिहार सरकार के मंत्रीगण अपनी गौरवमयी उपस्थिति से मंच को सुशोभित करते रहे हैं. केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह ने यहां लीची पौध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की स्वीकृति दी है, जो अभी तक मूर्त रूप नहीं ले पाई है.

किसानों के विकास की असीम संभावनाएं

कहते हैं चीन में लीची ने जन्म लिया, लेकिन आज वह उत्पादन के मामले में भारत से काफी पीछे है. परंतु लीची के उत्पादों के कारण उसका विश्व बाजार पर 40 प्रतिशत कब्जा है, जबकि उसका उत्पादन महज 15 से 17 प्रतिशत है. चीन में शाही लीची का उत्पादन नहीं होता, जो पूरी दुनिया में अपने लाजवाब स्वाद एवं गुणवत्ता के लिए जानी जाती है. चीनी लीची भारतीय शाही लीची के सामने स्वाद एवं गुणवत्ता में कहीं नहीं टिकती. भारत में लीची की पैदावार विश्व का 37 प्रतिशत है, लेकिन निर्यात महज 4 प्रतिशत है. इसका मुख्य कारण लीची के उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया जाना है.

चीन लीची के छिलके, फल एवं गुठली का प्रयोग कर उसका उत्पाद बनाता है, जबकि भारत में इसके गूदा का ही प्रयोग किया जाता है. छिलका एवं बीज को फेंक दिया जाता है. चीन लीची के छिलके से दवा एवं उसके अवशिष्ट से सनमाइका तैयार करता है, जो काफी आकर्षक होता है. उसके गूदा से सीधे खाए जानेवाले उत्पाद बनाता है. बीज से चीन दवा एवं महंगा सौंदर्य प्रसाधन बनाता है. चीन में लीची के फलों का बीमा सरकार द्वारा किया जाता है. इसका सीधा लाभ किसानों को मिलता है. इसके अलावा किसानों को वहां रजिस्टर्ड किया जाता है. चीन लीची के फलों से उम्दा किस्म का अल्कोहल बनाकर शराब के लिए निर्यात करता है और उससे उसे करोड़ों डॉलर की आमदनी होती है.

लीची के बागों में औषधीय पौधे तैयार किए जा सकते हैं, जो छाया में उगनेवाले होते हैं. लीची उत्पादक किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है. अगर सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिले तो मेहसी परिक्षेत्र सहित पूर्वी चंपारण जिले में 5 हजार करोड़ के लीची का उत्पादन हो सकता है. यहां राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से किसानों को नवीनतम जानकारी व सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए. किसानों के उत्पाद की सीधी बिक्री के लिए सरकारी स्तर पर खरीद केंद्र की व्यवस्था करा कर इस क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि लाई जा सकती है.

लीचीपुरम देश का एकमात्र फल महोत्सव है, जो पिछले 10 साल से नियमित रूप से किसानों के सहयोग के माध्यम से नियत समय पर (लीची के फल के पकने पर) लगातार आयोजित किया जाता रहा है. अब इस आयोजन को सरकार के स्तर से कराने पर इस क्षेत्र में लीची सहित अन्य फलों की बागवानी की पहल की जा सकती है. लीचीपुरम महोत्सव समिति ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है कि वे सरकारी स्तर पर लीची के फसल को प्रोत्साहित कर पूरे क्षेत्र के किसानों की जिन्दगी में मिठास घोलने का प्रयास करें.

इतिहास में मेहसी

मेहसी एक ऐसी जगह है, जहां से अकबर के नौ-रत्नों में से एक टोडरमल ने भूमि की पैमाइश शुरू की थी. मेहसी मुगलकाल में कमिश्नरी का दर्जा रखती थी. आज भी यहां उसके कुछ अवशेष मौजूद हैं. यहां अकबर के शासन के पूर्व के एक सूफी संत दाता मिर्जा हलीम साहब का मजार है, जहां प्रतिवर्ष बकरीद पर उर्स मनाया जाता है. यहां के नागरिक पुस्तकालय में नेताजी सुभाषचंद्र बोस की पुस्तकालय के बारे में हस्तलिखित टिप्पणी मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि यहां वे आए थे.

मेहसी में 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में विश्व प्रसिद्ध सीप बटन उद्योग था. यहां के बने हुए बटन यूरोपीय देशों को निर्यात किए जाते थे. इंग्लैंड की महारानी की कोट में मेहसी की सीप के बटन टंकने की बात यहां रहनेवाले अंग्रेज अधिकारी भी कहते थे. सीप बटन उद्योग के बारे में विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जाता था. मेहसी का सीप बटन उद्योग हजारों लोगों को रोजगार देता था, लेकिन जबसे चीन में स्वचालित मशीनों से सीप की कटाई आरंभ हुई है और प्लास्टिक के बटनों की मांग बढ़ी है सीप बटन उद्योग दम तोड़ चुका है. इसका कारण है कि इस उद्योग को अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है.

विश्व का सबसे ऊंचा और पुराना केसरिया बौद्ध स्तूप यहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां प्रतिवर्ष हजारों विदेशी सैलानी आते हैं. विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कल्याणपुर के कैथवलिया में बन रहा है, जो मेहसी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है. मेहसी रेल एवं राजमार्ग से जुड़ा हुआ है. ईस्ट-वेस्ट कोरीडोर यहीं से गुजरी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र लीची पैदावार पर

- पूर्वी चंपारण के 17 प्रखंडों के 15 हजार हेक्टेयर भूखंड पर लीची की पैदावार होती है. इसमें मेहसी, तेतरिया, मधुबन, पताही, पकड़ीदयाल, मोतिहारी, पिपरा कोठी, कोटवा, कल्याणपुर, केसरिया, संग्रामपुर, हरसिद्धि, सुगौली, बंजरिया, चकिया एवं तुरकौलिया का नाम शामिल है.
- इसमें मेहसी, चकिया, तेतरिया, कल्याणपुर, केसरिया, कोटवा, पिपरा कोठी, संग्रामपुर, हरसिद्धि, मोतिहारी एवं तुरकौलिया प्रखंड केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, जहां लीची का उत्पादन होता है. जबकि मधुबन, पताही, पकड़ीदयाल प्रखंड शिवहर सांसद रमा देवी के संसदीय क्षेत्र में आता है.
- इसके अलावा मुजफ्फरपुर जिले का मोतीपुर एवं साहेबगंज प्रखंड का अधिकतर हिस्सा इसी परिक्षेत्र में आता है. दो डिस्मिल जगह में लीची का एक पेड़ होता है, ऐसे में 15 हजार हेक्टेयर में करीब 15 लाख लीची के पेड़ लगे हुए हैं. औसतन एक पेड़ से 60 किलोग्राम लीची का उत्पादन होता है, मतलब पूर्वी चंपारण जिले में 3.6 लाख टन लीची का उत्पादन हो रहा है. यहां शाही एवं चायना लीची का प्रमुखता से उत्पादन किया जा रहा है. इसके उत्पादक क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है. मेहसी की शाही लीची का जवाब पूरे देश में नहीं है. इस स्वाद एवं गुणवत्ता का फल देश के किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलता है.

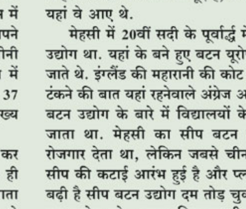
आत्म कल्याण केन्द्र
Email:aatmakalyankendra@gmail.com
www.acharyasudarshanjimaharaj.org
आचार्य सुदर्शन जी महाराज के संदेश

संसार के समस्त जीवों के ऊपर अंतरिक्ष से प्राण ऊर्जा की वर्षा होती रहती है जो भाग्शाली,विवेकशील व्यक्ति होता है, वे अपने मुख को ऊपर करके इस प्राण ऊर्जा को पीते रहते हैं। और अपने जीवन को सबल बनाते हैं। हमारे जीवन के चारों और प्रकृति फैली हुई है। हरे भरे पेड़ नदी झरना, पहाड़, बहती हुई हवाएं हरे-हरे घास एवं छोटे छोटे पौधे इन सबसे हमें प्राण ऊंजा मिलती रहती है। वृक्षों और पहाड़ियों के मध्य भ्रमण करना चांदनी रात में खुले बदन बैठना, लाल सूर्य के दर्शन करना, हरी घास पर पैदल चलना, नदी झरनों में स्नान करना आदि ऐसे कई उपाय हैं, जिनसे जीवनशक्ति बढ़ायी जा सकती है। मनुष्य जितना अधिक प्रकृति की गोद में खेलता है, वह उतना ही अधिक स्वस्थ्य रह पाता है। ध्यान रहे कि जीवन-ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमें वृक्षों के नीचे बैठना चाहिए। विशेषकर गायों के बीच मे रहें और गोपाल कृष्ण की तरह पशु उर्जा से लाभ उठाएँ। इतना ही नहीं, संतों के सम्पर्क में रहने से भी ऊर्जा मिलती है, उसे सात्विक ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा से जीवन में सात्विक वृत जन्म लेती है। आज का मनुष्य अशांति, भय और तनाव में जी रहा है। इस कारण उसका सारा जीवन नर्क बनता जा रहा है। जीवन हँसने और मुस्कराने के लिए है, उसको तनाव और चिंता में नष्ट करना समुचित नहीं है। इस संदर्भ में यह भी ध्यान रहे कि तनाव और चिंता मनुष्य स्वयं अर्जित करता है और उसके विषदंत से घायल होकर कराहने लगता है। यही कारण है कि जो जितना बड़ा आदमी है, वह उतना ही अधिक चिंतित दिखता है। ■

पर्यटकों से गुलज़ार हो रहा ककोलत

ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को अपने दामन में समेटे ककोलत एक खूबसूरत पहाड़ी से गिरता हुआ एक झरना है. फतेहपुर मोड़ से थाली नामक स्थान पहुंचने पर ही ककोलत जलप्रपात की शीतलता का अहसास होने लगता है. ककोलत जलप्रपात में 150 से 160 फीट से पानी नीचे गिरता है. पहले इस जलप्रपात के नीचे स्थित तालाब में उबड़-खाबड़ पत्थरों के रहने के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है. 1996 में गया के तत्कालीन वन पदाधिकारी वाईके सिंह चौहान ने नवादा जिला प्रशासन की मदद से इस तालाब की भूमि को बराबर कर आकर्षक रूप प्रदान किया था.

सुनील सौरभ

वर्षों से उपेक्षित बिहार का कश्मीर कहे जाने वाले ककोलत की वादियां एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो गई हैं. बिहार का प्रसिद्ध और चर्चित जलप्रपात ककोलत नवादा जिले के गोविन्दपुर प्रखंड में पड़ता है. पिछले डेढ़ दशक से यहां देशी-विदेशी पर्यटकों का आना बहुत कम हो गया था. कारण था ककोलत तक पहुंचने वाली जर्जर सड़क और पर्यटकों की सुरक्षा का अभाव. दूसरी ओर नक्सलियों की ककोलत के आस-पास बढ़ती सक्रियता से भी पर्यटक नहीं आना चाहते थे. इन्हीं कारणों ने डेढ़ दशक से ककोलत की रौनक को समाप्त कर दिया था. राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर नवादा जिला मुख्यालय से छह किलोमीटर की दूरी पर स्थित है फतेहपुर मोड़. यहीं से ककोलत जाने का रास्ता है. फतेहपुर से ककोलत जाने वाली सड़क बहुत जर्जर हुआ करती थी. हालत ये थी कि एक बार इस सड़क से गुजरने के बाद पर्यटक दोबारा इधर आने का साहस नहीं जुटा पाते थे. ऐसी स्थिति के कारण ककोलत जलप्रपात की रौनक समाप्त होने लगी थी. 2012 की बाढ़ में तो ककोलत की सीढ़ियां भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थीं. यहां पहुंचने पर सैलानियों की सुरक्षा भी प्रशासन के लिए बड़ी समस्या थी. नक्सलियों का आसपास के इलाकों में बढ़ती चहलकदमी की भी चर्चा अक्सर होती थी, जिसके कारण आसपास के जिले के लोग भी यहां आने से कतराने लगे. गर्मी के दिनों में बिहार का कश्मीर कहा जाने वाला ककोलत सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनकर रह गया था.

- सड़क बनी तो बढ़ने लगे पर्यटक
- पर्यटन विभाग भी करा रहा ककोलत की सैर
- विदेशी पर्यटक भी शीतल जलप्रपात में डुबकी लगा रे रहे हैं आनंद
- औसतन दस हजार सैलानी प्रतिदिन यहां आ रहे हैं

इस वर्ष के शुरू में फतेहपुर से थाली और थाली से ककोलत जाने वाली सड़क का निर्माण होने और वन विभाग की ओर से टूटी सीढ़ियों को बना देने से पर्यटकों का जलप्रपात तक पहुंचना आसान हो गया है. आवाजाही के बेहतर साधन होने के बाद गर्मी के शुरू से ही यानी फरवरी महीने से लोग ककोलत जलप्रपात का रुख करने लगे. बिहार का पर्यटन विभाग भी अपनी बसों से पर्यटकों को ककोलत की सैर कराने लगा है, जिससे विदेशी पर्यटकों का आना भी यहां शुरू हो गया है. आज गर्मी में प्रतिदिन औसतन दस हजार लोग ककोलत जलप्रपात के शीतल जल में डुबकी लगाकर गर्मी की तपिश मिटा रहे हैं. अब फिर से ककोलत की रौनक लौटने लगी है. ककोलत विकास परिषद के अध्यक्ष मसीउद्दीन बताते हैं कि परिषद के कार्यकर्ता यहां आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा व उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं. वाहनों की सुरक्षा से लेकर नाश्ता-भोजन कराने की जिम्मेवारी भी ककोलत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं की है.

ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को अपने दामन में समेटे ककोलत एक खूबसूरत पहाड़ी से गिरता हुआ एक झरना है. फतेहपुर मोड़ से थाली नामक स्थान पहुंचने पर ही ककोलत जलप्रपात की शीतलता का अहसास होने लगता है. ककोलत जलप्रपात में 150 से 160 फीट से पानी नीचे गिरता है. पहले इस जलप्रपात के नीचे स्थित तालाब में उबड़-खाबड़ पत्थरों के रहने के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है. 1996 में गया के तत्कालीन वन पदाधिकारी वाईके सिंह चौहान ने नवादा जिला प्रशासन की मदद से इस तालाब की भूमि को बराबर कर आकर्षक रूप प्रदान किया था. वन विभाग का गेस्ट हाउस भी तब वहां बना था, तब ककोलत जलप्रपात के नए रंग-रूप से दूर-दराज के लोगों का भी आना शुरू हो गया था. कुछ वर्षों तक गर्मी में देशी-विदेशी पर्यटकों का आना जारी रहा, धीरे-धीरे जब यहां पहुंचने वाली सड़क जर्जर हो गई और सुरक्षा का अभाव दिखने लगा, तब लोगों का आना बहुत कम हो गया. लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है.

ककोलत जलप्रपात के संबंध में चर्चित पौराणिक आख्यान के अनुसार त्रेता युग में एक राजा को किसी ने शाप दे दिया. शाप के कारण राजा अजगर बन गया और वह यहां रहने लगा. द्वापर युग में पांडव अपना वनवास व्यतीत करते हुए यहां आए थे. पांडव के आशीर्वाद से राजा को इस शाप से मुक्ति मिली. शाप से मुक्ति मिलने के बाद राजा ने भविष्यवाणी की कि कोई भी इस झरने में स्नान करेगा, वह कभी भी सर्प योनि में जन्म नहीं लेगा. यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग ककोलत जलप्रपात में स्नान करने आते हैं. वैशाखी और चैत्र संक्रांति के अवसर पर विसुआ मेले का आयोजन किया जाता है. इसी मेले के बाद ककोलत आने की शुरुआत भी मानी जाती है. वैसे लोग फरवरी से ही यहां आने लगते हैं. जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है, ककोलत जलप्रपात की रौनक भी बढ़ती जाती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

शैक्षणिक गुणवत्ता पर हावी वित्तीय अनियमितता

चौथी दुनिया ब्यूरो

मगध विश्वविद्यालय में पढ़ना कभी छात्रों के लिए गौरव की बात थी. बिहार के सबसे बड़े मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत तब तीन प्रमंडल मगध, पटना और शाहाबाद के अंगीभूत और संबद्ध कॉलेज आते थे. यहां के स्नातकोत्तर विभागों में देश के जाने-माने विद्वान शिक्षक पढ़ाते थे. छात्र-छात्राओं से भी ऐसे शिक्षकों को बहुत मान-सम्मान मिलता था. 90 के दशक के बाद जब विद्वान शिक्षक एक-एक कर रिटायर होते गए और बिहार सरकार के सूबे के 36 कॉलेजों को विभिन्न विश्वविद्यालयों के तहत अंगीभूत किया गया, तब इन कॉलेजों के ऐसे शिक्षक भी स्थायी सेवा में आ गए, जिनकी शैक्षणिक योग्यता सिर्फ प्रमाण-पत्र तक थी. नतीजा यह हुआ कि मगध विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित हुई. बाद के दिनों में आए कुलपतियों व अन्य पदाधिकारियों की रुचि भी मगध विश्वविद्यालय में पठन-पाठन से ज्यादा विकास कार्यों यथा भवन व सड़क आदि निर्माण कार्यों पर रही. यही कारण है कि कई पूर्व कुलपति आज भी जांच के घेरे में हैं और कई पर वित्तीय अनियमितता का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है. मगध विश्वविद्यालय की नींव तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन ने 20 अगस्त 1964 को रखी थी, ताकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का यह विश्वविद्यालय मील का पत्थर साबित हो सके. स्थापना के कुछ वर्षों में ही यह विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराने लगा था. इस विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों में देश के जाने-माने विद्वान शिक्षकों के योगदान से इसकी गरिमा में चार-चांद लगते गया. तब मगध विश्वविद्यालय में पढ़ना और पढ़ाना गौरव की बात मानी जाती थी. लेकिन नब्बे के दशक में इस विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक व्यवस्था में गिरावट आने लगी. इसके कारण मगध विश्वविद्यालय से पढ़ने वाले छात्रों का पलायन होने लगा. सेटिंग से आने वाले कुलपति भी इस विश्वविद्यालय को सुधारने की बजाय अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में ही लगे रहे. यही कारण है कि वर्तमान कुलपति से पूर्व आए चार कुलपतियों पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा, मुकदमा चला. कई मामलों की जांच तो निगरानी विभाग भी कर रहा है.

- शिक्षकों के 190 पद रिक्त
- पठन-पाठन से ज्यादा भवन-सड़क निर्माण पर जोर
- कई पूर्व कुलपति फंसे हैं वित्तीय गड़बड़ी में

छात्र संघों की मांग और राज्य सरकार के आदेश के बाद पीजी (स्नातकोत्तर) में पचास फीसदी सीटें तो बढ़ा दी गईं, लेकिन शिक्षकों के पद 1977 बजट के अनुसार स्वीकृत पदों से भी घटाकर आधे से भी कम हो गई. रेशनलाइजेशन के नाम पर शिक्षकों के पद घटा दिए गए. मगध विश्वविद्यालय में अंगीभूत कॉलेजों समेत 1300 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं. पीजी में ही करीब 190 पद रिक्त हैं. कई पीजी विभाग तो इकलौते शिक्षक के सहारे संचालित हो रहे हैं. राज्य सरकार ने शिक्षकों की कमी की भरपाई करने के निर्देश दिए हैं. हालांकि बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति कर पैनल मगध विश्वविद्यालय को भेज दिया गया है. लेकिन मगध विश्वविद्यालय उन शिक्षकों को योगदान नहीं करा रहा है. यही कारण है कि इस विश्वविद्यालय में न तो स्तरीय शोध हो रहे हैं और न ही स्तरीय शिक्षण. नैक ने भी अपनी जांच के बाद मगध विश्वविद्यालय को सी ग्रेड दिया, जो किसी विश्वविद्यालय के लिए शर्म की बात है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सम्मेलनों की बदौलत परिवर्तन की क़वायद

वाल्मीकि कुमार

केंद्र में भाजपा सरकार के तीन साल गुजरने के बाद अब बिहार में पार्टी स्तर पर आगामी चुनावी फतह की रणनीति बनने लगी है. इसके तहत बिहार के प्रत्येक जिले में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों और राज्य सरकार की विफलताओं का बखान किया जाएगा. खासकर पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं में जोश का प्रवाह किया जा रहा है. हाल में सीतामढ़ी एवं शिवहर जिले में आयोजित भाजयुमो के एक कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नीतीन नवीन ने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व का मिलना गौरव की बात है. वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के राजनैतिक चातुर्य का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि इनका सपना आने वाले समय में गांव से लेकर महानगरों तक कमल निशान का झंडा लहराना है. उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद व वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद अपनी करनी से जेल गए थे, अब इनके परिवार की बारी है. वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं. उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से लालू - नीतीश गठजोड़ को समाप्त करने की अपील की. इससे पूर्व जिले के अलग - अलग स्थानों पर पार्टी कार्यसमिति की बैठकों का दौर चला. इसके अलावा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किए गए. कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचा कर बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए जुट जाने का आह्वान किया गया.

सवाल यह है कि क्या केंद्र व यूपी समेत भाजपा शासित प्रांतों की सफलता का राग अलाप कर भाजपा बिहार में जड़ मजबूत कर पाएगी? चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे से लेकर जातीय विद्वेष पर शिकंजा कसा जाएगा?

सवाल यह है कि क्या केंद्र व यूपी समेत भाजपा शासित प्रांतों की सफलता का राग अलाप कर भाजपा बिहार में अपना जड़ मजबूत कर पाएगी? चुनाव के समय टिकट बंटवारे से लेकर उपजने वाला जातीय विद्वेष पर शिकंजा कस पाएगी? उत्तरी बिहार के तिरहुत व दरभंगा प्रमंडल के जिलों में इस पर राजनीतिक मंथन का दौर शुरू हो गया है. राजनीतिक गलियारों में चौपाल सजाने वालों का कहना है कि भाजपा को सबसे पहले दलगत खामियों को दूर कर आम कार्यकर्ताओं में एक विश्वास का प्रवाह करना होगा. चुनाव के दौरान समर्पित कार्यकर्ताओं से किनारा करने की प्रवृत्ति का त्याग करना होगा. गठबंधन की राजनीति के तहत खासकर राजद और जदयू के कब्जे वाले क्षेत्रों में मजबूत प्रत्याशी को मौका देकर जातीय वर्चस्व को चुनौती देनी होगी. धनकुबेरों की जगह समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान देना होगा. साथ ही संबंधित जिलों के दलगत सांसद, विधायक व विधान पार्षदों को भी जातीय जकड़न से हटकर आम लोगों के बीच एक बेहतर माहौल बनाना होगा. भाजयुमो के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र की योजनाओं के कार्यान्वयन में कोताही को लेकर सड़क पर संघर्ष का ऐलान किया है. लेकिन इसे जमीन पर सच्चाई के तौर पर उतारना आवश्यक होगा. वैसे अभी बिहार के चुनाव में वक्त है. अब देखना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में कमल खिलाने को लेकर भाजपा राजनीतिक बिसात पर क्या करती है. ■

यूरिन की समस्या और आप

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

डॉ. दिलिप कुमार सिंह

एम एस (जेनरल सर्जरी) यूरोलॉजिस्ट एण्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जन बस स्टैण्ड के पास, मधेपुरा

मधेपुरा के अनुभवी यूरोलॉजिस्ट चिकित्सक डॉ. दिलिप कुमार से हुई टेलिफोनिक बातचीत के कुछ अंश प्रस्तुत है- डॉ दिलिप ने बताया कि यूरीन की समस्या को यदि आप नजरअंदाज करते हैं तो आगे जाकर यह घातक हो जाती है। कई केस तो ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों को बचपन या मां के पेट के साथ ही कई बीमारियां हो जाती है। जिनमें एक पीयूभी की भी समस्या है। जो बच्चे के उम्र बढ़ने पर पता चलता है। यदि आपका बच्चा यूरिन में जलन या पेशाब करने में दर्द का अनुभव करता हो या फिर पेशाब की अधिकता हो यानि बहुमूत्र की शिकायत हो तो तुरंत कुशल यूरोलॉजिस्ट चिकित्सक से सम्पर्क करें। उपरोक्त समस्या केवल बच्चों में नहीं बड़ों में ज्यादातर बूढ़े व्यक्तियों में पायी जाती है तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। पेशाब की धार पतली होना, पेशाब की तेजी में कमी आना। पेशाब की समस्या ज्यादातर 40-50 से अधिक उम्र वालों में पाया जाता है। यूरिन की स्मस्याओं में स्टोन की समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है। इन समस्याओं के आने में तुरंत कुशल यूरोलॉजिस्ट से सम्पर्क करें। स्टोन के लक्षण - पेट के निचले हिस्से में आपको पथरी के लक्षण देखने को मिलते हैं मतलब टुंडी से नीचे और गुप्तांग के ठीक ऊपर के हिस्से में इसका दर्द होता है और ये दर्द कभी बहुत तेज होता है तो कभी धीरे धीरे और ये दर्द कभी कुछ देर के लिए होता है और कभी कभी बहुत लम्बे समय तक लगातार बन रहता है बीच बीच में इस दर्द में थोड़ी राहत भी रोगी को मिलती रहती है. पथरी के लक्षण का एक और रूप देखने को मिलता है जिसमे रोगी को उल्टी होने की शिकायत या जी मचलाने लगता है। ऐसा होने पर तुरंत चिकित्सक से सम्पर्क करें। डॉ. दिलिप ने बताया कि इसमें 10 एमएम तक हम प्रयास करते हैं कि बिना ऑपरेशन के निकाल दें नहीं तो आगे जांच करने के बाद निर्णय लिया जाता है कि क्या करें। ■ भारती

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.

A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil

Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus

Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg

Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

मस्जिद नहीं भारत की गौरवमयी परम्परा टूटी है

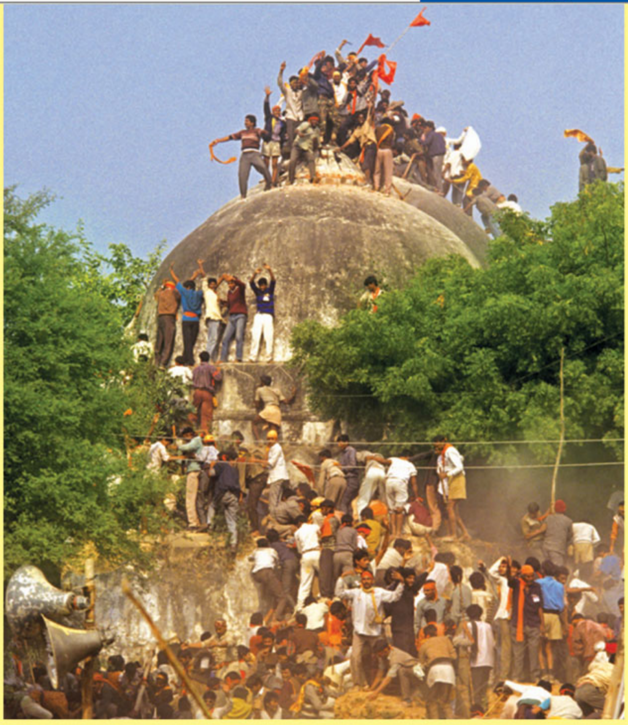

(अयोध्या में ढांचा गिराये जाने पर 17 दिसम्बर, 1992 को लोकसभा में चन्द्रशेखर)

आज मैं अटल जी से निवेदन करूंगा और जसवंत जी से निवेदन करूंगा कि आज हमने अपने अति उत्साह में या अपने क्षणिक राजनीतिक लाभ के लिए उन सारी मान्यताओं को तोड़ दिया. आज फ्रांस के सबसे बड़े अखबार 'लामोन्ड' ने लिखा है- 'हिन्दुस्तान में धर्मनिरपेक्षता हमेशा के लिए मर गई.' हमारे सामने भारत में कई बार उतार-चढ़ाव आए हैं, लेकिन दुनिया में एक ही सभ्यता, अगर मिस्र की सभ्यता को छोड़ दिया जाए, जो कभी मिटी नहीं, कभी टूटी नहीं और कभी गिरी नहीं. हिन्दू धर्म अकेला धर्म है. मैंने एक बार इस सदन में कहा था, मुझे हिन्दू होने का इसलिए गर्व है कि हिन्दू धर्म ने सबको अपनाया, किसी को ठुकराया नहीं. हिन्दू धर्म ने सबकी इज्जत की, सब धर्मों के जो अच्छे गुण थे, उनको लिया. बौद्ध ने हिन्दू में ब्राह्मण धर्म को मिटाने की कोशिश की, लेकिन हिन्दू धर्म ने उसको अवतार बनाकर उसकी पूजा की. यह हमारी परम्परा रही है, यह हमारी भावना रही है और यह सभ्यता तथा संस्कृति रही है.

आडवाणी जी कहते हैं कि डेढ़ लाख लोग संयत थे और पांच सौ लोग मस्जिद गिरा रहे थे. डेढ़ लाख लोग इतने निष्क्रिय थे कि पांच सौ लोगों को रोक नहीं सकते थे. दुनिया में आप किसको विश्वास दिलाना चाहते हैं. दुनिया में किसके सामने आप यह अपनी सफाई देना चाहते हैं. हो सकता है, आप ये नारे देकर सफल हो जाएं. हो सकता है, संसद में यहां बड़ी संख्या में आ जाएं. तीन दिन पहले मैंने अपने कुछ मित्रों को कहते-सुनते हुए सुना कि किसमें हिम्मत है, मस्जिद बनाएगा, एक ईंट रखेगा, उसका घर-दरवाजा सब खत्म हो जाएगा. अगर दरवाजा खत्म कर दोगे, लेकिन याद रखो, उसी के साथ भारत के अतीत को समाप्त करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी. भारतीय संविधान और सभ्यता को कब्र में पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी होगी.

मैं साम्प्रदायिक शक्तियों की बात नहीं करता, यह लड़ाई देश की मर्यादा को, प्रतिष्ठा को बचाने की लड़ाई, इस देश को जिन्दा रखने की लड़ाई है. इसमें एक मस्जिद नहीं टूटेगी, एक मन्दिर नहीं टूटा, मस्जिद टूटे, मन्दिर टूटे हमें उसकी कोई चिन्ता नहीं है. लेकिन आज करोड़ों का दिल टूट गया और इस दिल को आप नहीं जोड़ सकते. आप अपने भाषणों से उसको फिर से जागृत नहीं कर सकते. 15 करोड़ लोगों की आस्था को चोट पहुंची. मुझे याद है, हर बार मुझे ऐसे ही बात करनी पड़ती है, जो लोगों को अच्छी नहीं लगती. डेढ़ करोड़ सिक्खों के साथ जब कुछ हुआ था तब भी मैंने कहा था मत करो इस काम को. उस समय हमारा बड़ा उपहास हुआ था, बड़ी आलोचना हुई थी.

मैं अटल जी से निवेदन करूंगा कि आज भी छोटे दायरे को तोड़ें, वह हम नहीं जानते कि वे भर्त्सना करेंगे या नहीं करेंगे. क्या आडवाणी की गिरफ्तारी से सब कुछ बदल गया, क्या परिस्थितियां, वास्तविकताएं बिल्कुल टूट गईं. सारी दुनिया आज कहे कि भारत में धार्मिक आजादी मिटाने की कोशिश हो रही है. क्या इसके लिए हमको और आपको लज्जा नहीं आनी चाहिए.

आपने बयान दिया, कहा कि यहां पर हमने सही तस्वीर नहीं रखी. हमने यह नहीं कहा कि यह ढांचा मात्र था, पूजा होती थी, नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, सही है अटल जी, लेकिन कुछ नहीं था फिर भी 500 वर्षों की, 421 वर्षों की इमारत थी. दुनिया के किसी देश में आप कहोगे कि 400 वर्ष पुरानी इमारत, चाहे वह पूजा का स्थान हो या नहीं, हमने राजनीतिक कारणों से तोड़ दिया है, तो दुनिया में कोई आपकी तरफ मुंह उठा कर नहीं देखेगा, दुनिया आपके मुंह पर कालिख लगाकर रहेगी, क्योंकि हमारी सभ्यता, संस्कृति, गौरवमयी इतिहास का अंग है और आपने उसको उठाकर धरा-ध्वस्त कर दिया. क्या भारतीय जनता पार्टी के साथी यह समझते हैं कि इससे उनको दुनिया में गौरव मिलने वाला है? मुझे इस बात को कहने में थोड़ी भी हिचक नहीं है कि दुनिया के इस्लामिक देशों ने जो रुख दिखाया है, 1-2 देशों को छोड़कर, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं. उन्होंने अपना संयम नहीं छोड़ा.

अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि दुनिया के दूसरे देशों ने भारत की पुरानी गरिमामयी परम्परा को, जो मित्रता की परंपरा है, उसको कायम रखा है. याद रखिए, इस्लामिक देशों ने हमारी सैकड़ों वर्षों की दोस्ती की परम्परा को कायम रखा है और आपने इस देश की हजारों वर्षों की परम्परा को तोड़ा है. आप अपने को हिन्दू धर्म का सिपहसालार, सभ्यता-संस्कृति का दावेदार कहें, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अटल जी, आपसे हमें उम्मीद थी, जसवन्त सिंह जी, आपसे हमें उम्मीद थी. राजमाता जी से भी हमको उम्मीद थी, यह तो उम्मीद थी कि वे धर्म के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मस्जिद गिरने देंगी, यह उनसे उम्मीद नहीं थी.

मैं यह बात सीधे तौर से कहता हूं, इन्द्रजीत जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया, वह शब्द तो मैं इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, जो सारी दुनिया को चुनौती दे सकते थे, अपने 500 कार्यकर्ताओं के सामने खड़े नहीं हो सकते थे? क्या आप देश को चलाओगे, क्या आप राष्ट्र को इस कठिन समय से निकालोगे, यह बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसका जवाब इतिहास आपसे पूछेगा.

हमारे कई मित्र इधर से बोल रहे हैं कि क्या करते, गोली चला देते, नहीं गोली मत चलाइए. पुलिस और फौज बैठी हुई है, उसकी गोली को मखमल का गद्दा बिछाकर रख दीजिए और जब जरूरत पड़े, वह आपको सेल्यूट दे सके, उन्हें गोली चलाने की जरूरत नहीं है. यह फौज, पुलिस जिस पर हर साल बजट पास करते हैं, किसलिए बनी हुई है. क्या गोली चलाने के लिए नहीं बनी हुई है? राज्य की कल्पना कैसे बनी? राज्य कोअर्सिव पावर्स का समुच्चय है, दमन की शक्तियों को समाज ने आपके हाथ में दिया है, ताकि समाज को तोड़ने वाली ताकतों का मुकाबला कर सकें और उन शक्तियों का अगर आप उपयोग नहीं करते हैं, तो आप अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं. इसलिए यह हमसे मत कहिए.

अटल जी ने कहा अर्जुन सिंह जी से कि इतना गुस्सा कर रहे हो, तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? अर्जुन सिंह जी ने बड़े नाटकीय ढंग से कहा कि मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं लड़ने वाला हूं. मंत्री पद से हट जाते तो लड़ने में कुछ कमी आ जाती? इतने कांग्रेस के मेम्बर्स बैठे हैं वे नहीं लड़ेंगे? केवल मंत्री लोग ही लड़ेंगे? अगर मंत्री पद नहीं रहेगा, तो लड़ाई नहीं लड़ सकते. मैं आपसे कहना चाहता हूं राजनीति एक अभिनय नहीं है, राजनीति एक सुविधा का खेल नहीं है, राजनीति कठोर निर्णय देने के लिए हर क्षण आपको निमंत्रण देती है.

आज यहां पर अटल जी ने कहा, वे मुलायम सिंह सरकार पर बड़े नाराज हैं. उस समय भी नाराज थे. लेकिन, मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, तो केवल 16 लोग मरे थे और कल्याण सिंह ने गोली नहीं चलवाई थी, तो कम से कम 1200 लोग मरे. आप फिर कहते हैं हम जिम्मेदार नहीं? आडवाणी साहब का बयान है, 'कल्याण सिंह, मुलायम सिंह नहीं हो सकते.' मैं जानता हूं मुलायम सिंह और कल्याण सिंह में कोई तुलना नहीं है. मुलायम सिंह संविधान की रक्षा के लिए कुछ भी कर

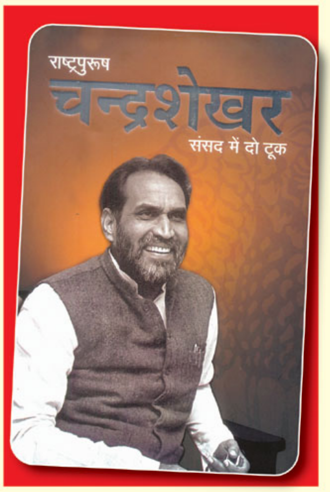

सकते थे, कल्याण सिंह संघ के आदेश के पालन के लिए कुछ भी कर सकते थे. एक को संविधान का आदेश था और दूसरे को संघ परिवार का आदेश था. दोनों आदेशों में अंतर है. इस अंतर को हमें और आपको पूछना पड़ेगा. यह अंतर हम जानते थे. मुझे अंतर मालूम था, यह अंतर हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं मालूम था, यह अंतर अर्जुन सिंह जी को नहीं मालूम था, यह अंतर नहीं मालूम था शरद पवार जी को.

अध्यक्ष महोदय, हमसे दुनिया के लोग जब पूछते हैं, हम सब चीजों का जवाब दे सकते हैं, क्या हमारे पास जवाब है 6 तारीख को, 11.45 बजे या 11.30 बजे मस्जिद पर लोग चढ़े, 6.15 तक आप देखते रहे. ऐसी पंगु सरकार कहे कि हमसे गलती हो गई, हमें धोखा हो गया. धोखा आपको नहीं हो गया, आपने अपने को धोखा दिया और आपने देश की जनता को धोखा दिया.

प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि बहुत हो गया. लेकिन अनिर्णय की स्थिति से आपकी छवि को जो धक्का लगा, उससे बचने के लिए कोई भी कदम बिना सोचे-समझे मत उठाइए. अनावश्यक रूप से सरकारों को बर्खास्त करने का काम आप समझें कि पुरुषार्थ का प्रतीक है. लेकिन आपकी बिगड़ी हुई छवि को सुधारने का ढोंढा प्रयास है. मैं समझता हूं कि जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं आडवाणी जी के ऊपर, तो क्या उन आरोपों को किसी भी न्यायालय में साबित कर सकते हैं. इस समय निर्णय लेने के लिए आडवाणी जी के ऊपर पुलिस इंस्पेक्टर ने आरोप लगाया है, तो उस आरोप को लेकर आडवाणी जी को गिरफ्तार करते हो. किसने यह सलाह दी थी, किसने यह बात कही थी आज आप बैन करते हो दूसरे दिन हाईकोर्ट आपके ऊपर कहते हैं, यह गलत बैन आर्डर है. एक समय अपने कर्तव्य से चित होने के बाद निरन्तर अपनी साख बढ़ाने के लिए गलत काम न कीजिए. इससे देश का अहित होगा, टकराव और बढ़ेगा.

मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि यह जो कलंक का धब्बा राष्ट्र के ऊपर लगा है, इसकी जिम्मेदारी आप पर है. आप अर्जुन सिंह जी को जानते हैं. आपको ज्यादा ज्ञान है. मेरी इनसे बड़ी दोस्ती रही है. आज भी कहता हूं कि इनमें से बहुत से लोगों को मैं बहुत निहित और बहुत आदर्शवादी व्यक्ति मानता हूं. मुझे कहने में हिचक नहीं है कि आप सरकार के पद पर बैठे थे. आप सब कुछ जानते थे और चुपचाप बैठे रह गए. आपको भी क्या कोई कृष्ण चाहिए, गीता का उपदेश देने के लिए अर्जुन की तरह. कहां से कोई कृष्ण आता? आप महाभारत की बात करते हो. महाभारत आपने पढ़ा है और कुछ सीखा है और बुना है, केवल पढ़कर यहां भाषण देने के लिए, उसके दो शब्द याद कर लिए.

अध्यक्ष महोदय, आज यह देश एक ऐसे बिन्दु पर खड़ा है, जहां हमारे और आपके लिए निर्णय लेना कठिन है. मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारी मान्यताएं दांव पर हैं. आज हमारी विश्वसनीयता दांव पर है. पहली बार ऐसी सरकार इस देश में है जिसकी विश्वसनीयता पर किसी को कोई भरोसा नहीं है. पहली बार ऐसा विरोध पक्ष है जिसके बारे में दुनिया को कोई गलतफहमी नहीं है, कम से कम मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, जो किसी मूल्य को नहीं रखना चाहते. इस देश की अजीब हालत है. जो सरकार को चला रहे हैं वे अपंग हैं और जो विरोध में बैठे हुए हैं वे सरकार पर हावी होना चाहते हैं. वे देश की मान्यताओं को तोड़ना चाहते हैं और देश की परम्पराओं के विरुद्ध काम कर रहे हैं. अपने गुरुदेव से, उन्होंने कहा कि शिष्य बहुत ही मदद कर सकता है. मैं गुरुदेव से चाहूंगा कि आप मेरी मदद करें. ऐसे में हम क्या करें और किधर जाएं. आपके लिए भी निर्णय करना होगा. भीष्म पितामह बन जाने से कलंक लेकर ही मरेंगे, तो कोई ऊपर मर्यादा नहीं मिलने वाली है. आपका उपदेश कोई नहीं सुनेगा.

अध्यक्ष महोदय, आज यह विकट परिस्थिति इस देश के सामने है. मैं चाहता हूं कि यह सदन एक बार इसकी वास्तविकता को समझे. मैंने पहले भी कहा था कि एक-दूसरे के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप को छोड़कर हम अपनी सही हैसियत को मानने के लिए तैयार हों. अगर हमसे अपराध हुआ है, तो उसको स्वीकार करें. अटल जी, आपने जो 'इण्डिया एब्रोड' को बयान दिया था, उससे मत डरिए. हर समय बदल जाना कोई राजनीति नहीं. परिस्थिति के अनुसार मुड़ जाना और हालत के रुख से अपने को बचा लेना, यह कोई राजनीति का कर्तव्य नहीं है.

प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि बहुत हो गया. लेकिन अनिर्णय की स्थिति से आपकी छवि को जो धक्का लगा उससे बचने के लिए कोई भी कदम बिना सोचे-समझे मत उठाइए. अनावश्यक रूप से सरकारों को बर्खास्त करने का काम आप समझें कि पुरुषार्थ का प्रतीक है. लेकिन आपकी बिगड़ी हुई छवि को सुधारने का ढोंढा प्रयास है. मैं समझता हूं कि जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, आडवाणी जी के ऊपर तो क्या उन आरोपों को किसी भी न्यायालय में साबित कर सकते हैं. इस समय निर्णय लेने के लिए आडवाणी जी के ऊपर पुलिस इंस्पेक्टर ने आरोप लगाया है, तो उस आरोप को लेकर आडवाणी जी को गिरफ्तार करते हो. किसने यह सलाह दी थी, किसने यह बात कही थी आज आप बैन करते हो दूसरे दिन हाईकोर्ट आपके ऊपर कहता है, यह गलत बैन आर्डर है. एक समय अपने कर्तव्य से चित होने के बाद निरंतर अपनी साख बढ़ाने के लिए गलत काम न कीजिए. इससे देश का अहित होगा, टकराव और बढ़ेगा.

आपने सहमति की राजनीति से शुरू किया था, लेकिन शायद किसी प्रधानमंत्री ने इतनी बुरी टकराव की राजनीति नहीं की. इसलिए हर समय बोलते समय कुछ अपने पौरुष का, अपने व्यक्तित्व का, अपनी क्षमता का, अपनी मर्यादा का ध्यान रखकर अगर लोग बोलें, जो सत्ता में हैं, तो ज्यादा अच्छा होगा. आपने कह दिया कि उसी स्थान पर मस्जिद बनेगी. बना सकते हैं क्या? गृहमंत्री ने कहा थोड़े दिन बाद बनेगी, रक्षामंत्री ने कहा कि एक साल बाद बनेगी या एक साल के अंदर बनेगी. कह कहते हैं दोनों बनेंगे. जो काम बजरंग दल और वी.एच.पी. कह रही थी कि मन्दिर बनेगा लेकिन नक्शा नहीं बताएंगे उसी तरह से नरसिंह राव मन्दिर और मस्जिद दोनों बनाएंगे, नक्शा नहीं दिखाएंगे. मैं नहीं जानता कि इनका आपस में क्या रिश्ता है. जो शरद यादव ने कहा था, लेकिन सोचने के तरीके हैं, आज देश विपदा में है. यह अचानक हो गया है या इसके पीछे कोई रहस्य है, मैं नहीं जानता कि रहस्य में क्या है? अगर रहस्योद्घाटन करना है, तो आप लोगों को करना होगा, जो इधर बैठे हुए हैं. लेकिन मैं कहता हूं कि इस तरह की निष्क्रियता से, इस तरह की उहापोह से राष्ट्र की मर्यादा को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है. ■

(साभार: राष्ट्रपुरुष चंद्रशेखर, संसद में दो टूक)

मूल्यों में परिवर्तन से क्रांति आती है: महादेव विद्रोही

सर्व सेवा संघ, एक ऐसा संगठन जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी और जिसे साकार किया था आचार्य विनोबा भावे ने. सर्वोदय आंदोलन इसी संगठन की उपज था. आज इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महादेव विद्रोही. वर्तमान में क्या है इस संगठन की कार्यशैली और क्या ये आज गांधी जी की विरासत को आगे बढ़ा रहा है, इस मुद्दे पर महादेव विद्रोही से बात की चौथी दुनिया के वरिष्ठ संवाददाता **शशि शेखर** ने. प्रस्तुत हैं बातचीत के प्रमुख अंश...

आप लंबे समय से इस संगठन से जुड़े रहे हैं. अभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. तब और अब के बीच सर्व सेवा संघ में आप क्या अंतर देखते हैं?

सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि पहले इस संगठन के पास विनोबा भावे और लोकनायक जयप्रकाश जी जैसा बड़ा नेतृत्व था. उनके जाने के बाद अब मुझे लगता है कि सर्व सेवा संघ का राष्ट्रीय महत्व कम हुआ है. उनके बाद की भी एक पीढ़ी थी, दादा धर्माधिकारी की, धीरेंद्र मजूमदार की. वे भी हमारे बीच नहीं रहे. हम तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, जिनके भरोसे ये आंदोलन चल रहा है. ये सही बात है कि हमारी राष्ट्रीय छवि अभी नहीं है. लेकिन सर्वोदय आंदोलन भूदान से जुड़ा रहा है और देश के अधिकांश भागों में भूदान की जमीनें मिली हैं. जिन लोगों को भूदान की जमीनें मिली हुई हैं, वे सब आज भी सर्वोदय को नाम से जानते हैं. इसलिए अभी भी गांव-गांव में सर्वोदय को याद करने वाले लोग हैं. भले ही अखबारों में हमारा नाम कम आता हो, लेकिन गांवों में अब भी हमारा गुडविल है और अब भी सर्व सेवा संघ में लोगों की बहुत आस्था है.

आपने कहा कि मौजूदा समय में आपकी राष्ट्रीय पहचान नहीं है. क्या कारण है कि वर्तमान समय में लोग आपकी विचारधारा के साथ नहीं जुड़ रहे हैं और इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं?

हमारे संगठन का सदस्य बनने के लिए जरूरी शर्त है कि आपकी सत्य और अहिंसा में पूरी आस्था हो और आप किसी भी राजनीतिक दल से नही जुड़े हों. साथ ही आप किसी भी तरह का कोई पद धारण नहीं करेंगे, चाहे वो ग्रामसभा के प्रधान का पद ही क्यों न हो. पिछले कुछ समय में सत्ता का आकर्षण बहुत बढ़ा है. अभी जब ग्राम पंचायतों के पास बहुत से कोष आने लगे, तो कई लोग सोचने लगे कि कम से कम पंचायत का प्रधान तो मैं बन ही जाऊं. हमारे यहां इन सबकी पाबंदी है. कई लोगों को लगता है कि यहां आना अपना विकास रोकने जैसा है. सर्व सेवा संघ की स्थापना से पहले गांधी जी ने इसके लिए तैयार किए गए दस्तावेज में लिखा था कि भारत के सात लाख गांवों में मुझे सात लाख जिंदा शहीद चाहिए. ऐसे कार्यकर्ता को समाज की कुरीतियों से लड़ना होता है, जातिवाद से लड़ना होता है, रूढ़िवादी परम्पराओं से लड़ना होता है. इसलिए ये आसान काम नहीं है. इस काम में कोई ग्लैमर नहीं है, इसलिए आम लोग इससे प्रभावित नहीं हो पाते हैं. भूदान कार्यक्रम का एक आर्थिक पक्ष था, इसलिए भी लोग उससे प्रभावित हुए. जो लोग विचारों की गहराई में जाते हैं, वे हमसे जुड़ते हैं.

आजादी की लड़ाई के साथ-साथ गांधी जी वैचारिक और सामाजिक सुधारों की भी एक लड़ाई लड़ते थे. उससे जुड़ने वाले लोगों के लिए उन्होंने ऐसी कोई पाबंदी नहीं रखी कि वे राजनीति नहीं कर सकते. क्या ये पाबंदी भी एक वजह है, लोगों के सर्व सेवा संघ के साथ नहीं जुड़ने का?

गांधी जी ने अपना अंतिम वसीयतनामा 29 जनवरी 1948 को लिखा. उसमें उन्होंने लिखा कि देश को आजादी मिलने के साथ ही अब कांग्रेस का काम खत्म हो गया है. कांग्रेस आजादी के लिए बना हुआ संगठन था. देश आजाद हो गया, अब उसका काम खत्म हो गया. इसको अब लोकसेवक संघ के रूप में बनाना चाहिए. यानि कांग्रेस एक राजनीतिक दल था. इसलिए राजनीतिक दल में सबको आने की छूट थी. लेकिन गांधी जी ने खुद कहा था कि अब उसका काम खत्म हो गया और उसको लोक सेवक संघ में विकसित करना चाहिए. हम भी उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं.

आपके अनुसार भूदान एक आर्थिक कार्यक्रम था, जिससे लोग जुड़े. मौजूदा समय में क्या आपके पास इस तरह का कोई कार्यक्रम है, जो जनसाधारण को अपने साथ जोड़ सके?

भूदान की तरह आज भी हमने भूमि से जुड़े सवालों को अपने हाथ में लिया है. नई आर्थिक नीति के बाद और खासकर पिछले चार-पांच वर्षों में सरकार छोटे किसानों और आदिवासी क्षेत्रों की जमीनें अधिग्रहीत कर रही है. पहले तो सरकार सार्वजनिक कामों के लिए जमीन अधिग्रहीत करती थी, लेकिन अब कंपनियों के लिए सरकार ने जमीन अधिग्रहीत करना शुरू कर दिया है. एक बार जमीन छिन जाती है, तो फिर वो लौटकर नहीं आती. लोगों के पास पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो दोबारा जमीन खरीदते हैं. जब तक पैसे रहते हैं, मौज करते हैं. एक जमाने में जो लोग जमींदार थे, उनमें से अनेक लोग आज झोपड़पट्टियों में रहते हैं. जब तक पैसे थे गाड़ियां खरीदी, मौज किए. सरकार से हमारा कहना है कि लोगों की जमीनें न छीनी जाएं. आर्थिक संसाधनों पर जनता का अधिकार रहना चाहिए. एक दूसरा मुद्दा है, पानी का. इसका भी व्यापारीकरण हो रहा है. इन दोनों मुद्दों को केंद्र में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. हमारा मानना है कि प्राकृतिक संसाधन पर जनता का अधिकार होना चाहिए. विकास के नाम पर जनता को संसाधनों से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए. इस मुद्दे पर जनता हमारे साथ है. गुजरात में हमारा एक आंदोलन चल रहा है. शहरों की कंपनियों से निकलने वाले वेस्ट केमिकल को गांवों में डंपिंग साइट बनाकर उसमें डाल दिया जाता हैं. उस वेस्ट केमिकल से ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो जाता है. इससे गांवों में अनेक तरह की बीमारियां फैलती हैं. इसके कारण ही अहमदाबाद के बटवा में इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास के गांवों में लोग चर्म रोग से प्रभावित हैं. वहां का पूरा ग्राउंड वाटर रंगीन हो गया है. शुरू में जब वहां कंपनियां स्थापित हुईं, तब लोग बहुत खुश थे कि उन्हें रोजगार मिलेगा. लेकिन अब उन्हें इसका अहसास हो रहा है कि ये अभिशाप बन गया है.

गुजरात में लगभग 60 हजार एकड़ भूदान की जमीन अभी तक वितरित नहीं हो सकी है. बिहार में भी भूदान की जमीन है. जमीन सही लोगों तक पहुंचे, इसमें सर्व सेवा संघ की क्या भूमिका रहेगी?

एक लाख तीन हजार एकड़ जमीन हमें गुजरात में मिली थी. उसमें से 52 हजार एकड़ जमीन बांटी गई. अभी भी 53 हजार एकड़ जमीन बची हुई है. इसके लिए हमारे ही कुछ लोग जिम्मेदार हैं, जो आंदोलन से जुड़े हुए थे. इसका एक और कारण है. विनोबा जी के समय में जब सभी राज्यों में भूदान एक्ट बना, जिसका ड्राफ्ट हमारे संगठन ने ही तैयार किया था, तब उस समय गुजरात नहीं था. उस समय बाम्बे राज्य था. बाम्बे राज्य में भूदान एक्ट नहीं बना. बाम्बे राज्य के नाम से एक नोटिफिकेशन निकाला था. वही नोटिफिकेशन आज तक गुजरात और महाराष्ट्र में चल रहा है. इसे कुछ लोगों ने हाई कार्ट में चैलेंज किया था कि ये नोटिफिकेशन एक्ट नहीं है, अधिनियम नहीं. भूदान में ये नियम है कि भूदान की जमीन बिक नहीं सकती है. अहमदाबाद में एक बड़े वकील ने भूदान की जमीन खरीदी जिनका सत्ता पक्ष से संबंध है. उन्होंने कोर्ट में कहा कि कोई कानून नहीं है, जिसके द्वारा आप हमें जमीन खरीदने से रोक सकें. लेकिन हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दिया और कहा कि भूदान की जमीन गरीबों के लिए है, बेचने खरीदने के लिए नहीं. एक तो इसे लेकर कानूनी ढिलाई रही और दूसरा ये कि जमीनें कई संस्थाओं के पास चली गईं. भूदान की जमीन भूमिहीन लोगों को मिलनी चाहिए. कुछ साल पहले बिहार सरकार ने लैंड रिफॉर्म कमीशन बनाया था. जिसकी अंतरिम रिपोर्ट में डी बंदोपाध्याय ने लिखा था कि 11,500 एकड़ भूदान की जमीन 59 संस्थाओं को दी गई है. ये सभी गांधी के नाम पर चलने वाली संस्थाएं हैं. विनोबा भावे जी ने जो जमीन गरीबों के लिए मांगी थी, वो संस्थाओं ने ले ली. वो या तो सर्वोदय की संस्था हो या कोई और सरकारी संस्था. यदि इसके कारण जनता का विश्वास आपके ऊपर से घटता है या आपके प्रति गुस्सा बढ़ता है, तो वो गलत नहीं है. इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर लड़ रहा हूं. मैंने गुजरात में इस मुद्दे को उजागर किया. वहां के अखबारों ने भी इसे प्रमुखता से उठाया. शासन को भी नहीं मालूम था कि क्या करना है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि भूदान की जमीन लैंडलेस एग्रीकलचर के लिए है. ये फैसला 1988 में आया था. प्रावधान ये है कि जमीन नहीं बिकनी चाहिए, जबकि जमीन बिक रही थी. आरटीआई के जरिए जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछा, तो कहा गया कि लॉ डिपार्टमेंट से पूछो. इस तरह से टाल-मटोल किया जाता रहा. हम उन लोगों को संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी जमीनें छिन गई हैं. हाल ही में अहमदाबाद के साइंस सिटी में भूदान की 11 एकड़ जमीन एक करोड़ दस लाख में बेची गई. गौर करने वाली बात है कि उनमें से एक एकड़ जमीन की कीमत सात करोड़ है. गुजरात के सौराष्ट्र में भूदान की जमीन बड़े-बड़े राजनीतिक लोगों के पास है और वे नहीं चाहते हैं कि इसे भूमिहीनों में वितरित किया जाय.

ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सर्व सेवा संघ का उद्देश्य है, सत्य, अहिंसा और शोषण से मुक्त समाज की स्थापना करना. लेकिन मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक दौर में ये कैसे संभव हो पाएगा?

ये एक दीर्घकालीन लक्ष्य है, साथ ही एक कठिन काम भी है. अब तक जो भी क्रांति हुई, चाहे वो कम्युनिस्टों की क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो या कोई और क्रांति, सभी का एक ही लक्ष्य था, शोषण से मुक्ति और अन्याय से मुक्ति. वो लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं, ये अलग सवाल है. आमतौर पर लोग सत्ता में परिवर्तन को क्रांति मानते हैं. लेकिन सर्वोदय में हम मानते हैं कि मूल्यों और सम्बंधों में परिवर्तन से क्रांति होती है. व्यक्ति का बदलना क्रांति नहीं है, व्यवस्था का बदलना क्रांति होता है. यदि वही व्यवस्था रही, सिर्फ लोग बदल गए, तो ये क्रांति नहीं हुई. हमारे लक्ष्य में कठिनाइयां जरूर हैं, लेकिन उस लक्ष्य को पाए बिना हमारा उद्देश्य सिर्फ उद्देश्य रह जाएगा.

सर्व सेवा संघ नए लोगों को, खासकर युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या कोई कार्यक्रम लेकर आएगी?

जब मैं अध्यक्ष बना, तो सर्व सेवा संघ का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष था. अब तक अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की बीच में बहुत दूरी हुआ करती थी. लेकिन अब हमारे कार्यकर्ताओं को लगता है कि आज उनका एक साथी अध्यक्ष है. उनके साथ साथी की हैसियत से मेरी बातचीत होती है. इससे मुझे प्रसन्नता होती है. मैं चाहता हूं कि आगे का नेतृत्व उनके हाथ में आए और जो भी निर्णय होते हैं, उसमें उनकी भी भागीदारी हो. जिससे उन्हें लग सके कि ये उनका संगठन है. सरकार में कुछ खास लोगों के पास ही सब कुछ केंद्रित होता है, लेकिन हमारे संगठन में ऐसा नहीं है. सर्वोदय लोगों का संगठन है, समाज का संगठन है. युवा कार्यकर्ताओं को शोषण से लड़ने में मजा आता है. मैनेजमेंट के स्टुडेंट, टेक्नोलॉजी के स्टुडेंट बड़े पैमाने पर गांधी जी के विचारों से आकर्षित होते हैं. वे संगठन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन अपने-अपने तरह से काम कर रहे हैं.■

आरटीआई से मांगें जॉब कार्ड का हिसाब

हर योजना की तरह मनरेगा भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गई है. देशभर में मनरेगा से जुड़ी धांधलियों की खबरें मीडिया में लगातार आती रहती हैं. जैसे, कहीं किसी ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत फ़र्ज़ी जॉब कार्ड बनाकर मज़दूरी का धन हड़प लिया जाता है या फिर प्रधान और पंचायत सचिव मिलकर विद्यालय के प्रबंधक, ठेकेदार और व्यापारियों तक के नाम से जॉब कार्ड जारी कर देते हैं. धन की बंदरबांट के लिए चहेतों के नाम जॉब कार्ड बनाकर धन निकाल लिया जाता है. सरकार भी मानती है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है. सरकार के पास भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत कामगारों को जॉब कार्ड प्रदान नहीं किए जाने के बारे में शिकायतें आती हैं. इस अंक में हम अपने पाठकों और उनके ज़रिए गांव-देहात के लोगों तक मनरेगा और जॉब कार्ड बनवाने से सम्बंधित जानकारी पहुंचा रहे हैं. हम पाठकों से अपेक्षा करते हैं कि वे गांव-देहात में रहने वाले लोगों को भी इस कॉलम के बारे में बताएंगे और दिए गए आवेदन के प्रारूप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे. यहां हम मनरेगा योजना से जुड़े कुछ सवाल आवेदन के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं. आप इस आवेदन के माध्यम से मनरेगा के तहत बने जॉब कार्ड के बारे में सूचनाएं मांग सकते हैं, ताकि ज़रूरतमंदों तक इस सरकारी योजना का लाभ पहुंच सके.■

रोजगार गारंटी के तहत जॉब कार्ड के आवेदन का विवरण

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

मैं....................ग्राम का निवासी हूं. मैंने मनरेगा के तहत दिनांक................को जॉब कार्ड के लिए आवेदन किया था. इस सम्बंध में निम्न विवरण प्रदान करें:

1. मेरे आवेदन पर की गई प्रतिदिन की कार्रवाई अर्थात दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं. मेरा आवेदन किन-किन अधिकारियों के पास गया तथा किस अधिकारी के पास कितने दिनों तक रहा और इस दौरान उन अधिकारियों ने उसपर क्या कार्रवाई की? पूरा विवरण उपलब्ध कराएं.

2. मनरेगा के तहत रोजगार जॉब कार्ड के लिए आवेदन करने के कितने दिनों के अंदर जॉब कार्ड बन जाना चाहिए? इससे सम्बंधित नियमों या नागरिक चार्टर या किसी अन्य आदेशों/दिशा निर्देशों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं.

3. कृपया उन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम तथा पद बताएं, जिन्हें मेरे आवेदन पर कार्रवाई करनी थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की.

4. अपना काम ठीक से न करने और जनता को परेशान करने वाले इन अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? ये कार्रवाई कब तक की जाएगी?

5. अब मेरा जॉब कार्ड कब तक मिल जाएगा?

6. मनरेगा के तहत रोजगार जॉब कार्ड बनाने के लिए मेरे गांव से अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? इसकी सूची निम्नलिखित विवरणों के साथ उपलब्ध कराएं:

क. आवेदक का नाम व पता
ख. आवेदन संख्या
ग. आवेदन की तारीख
घ. आवेदन पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण (जॉब कार्ड बना/जॉब कार्ड नहीं बना/विचाराधीन)
ङ. यदि जॉब कार्ड नहीं बना, तो उसका कारण बताएं.
च. यदि बना तो किस तारीख को.

मैं आवेदन फीस के रूप में 10रु. अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

भवदीय
नाम:
पता:
फोन नं:
संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

अगर आपके पास आरटीआई से संबंधित कोई ख़बर या सवाल है, तो हमें इमेल करें:
rti@chauthiduniya.com

कटरीना कैफ ठुमके लगाकर ठगेंगी हिंदुस्तान

अभिनेत्री कटरीना कैफ की किस्मत इस समय अच्छी चल रही है. काफी समय से कटरीना बॉलीवुड से गायब हो चुकी थीं. लेकिन जब से सलमान खान ने उनका हाथ थामा है, तब से कटरीना की मानो किस्मत ही चमक गई. जी हां, कटरीना को पहले तो सलमान के साथ टाईगर जिंदा है में काम मिला और अब आमिर खान और अमिताभ बच्चन के साथ ठग ऑफ हिंदुस्तान में भी प्रमुख भूमिका निभा रही हैं. ख़बरों की मानें तो फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान में कटरीना डांसर का किरदार निभाती नज़र आएंगी. इसके साथ ही वह इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग भी करती नज़र आएंगी. आपको बता दें कि यह फिल्म यशराज बैनर तले बनाई जाएगी. यह पहली बार होगा जब अमिताभ और आमिर सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ नजर आएंगे. फिल्म में अमिताभ, आमिर के पिता की भूमिका में दिखेंगे.■

सलमान-ऋतिक को पछाड़कर टाईगर श्रॉफ बने रैंबो

सिल्वेस्टर की जगह कोई नहीं ले सकता टाईगर श्रॉफ

बचपन से मार्शल आर्ट और एक्शन फिल्मों का फैन होने के बाद ऐसा मौका मिलना बहुत बड़ा सपना पूरा होने जैसा है. निश्चित रूप से मैं महान सिल्वेस्टर स्टेलॉन को रिप्लेस नहीं कर सकता हूं, लेकिन यह ऐसा है, जैसे मैं बचपन से इसी की तैयारी कर रहा था.

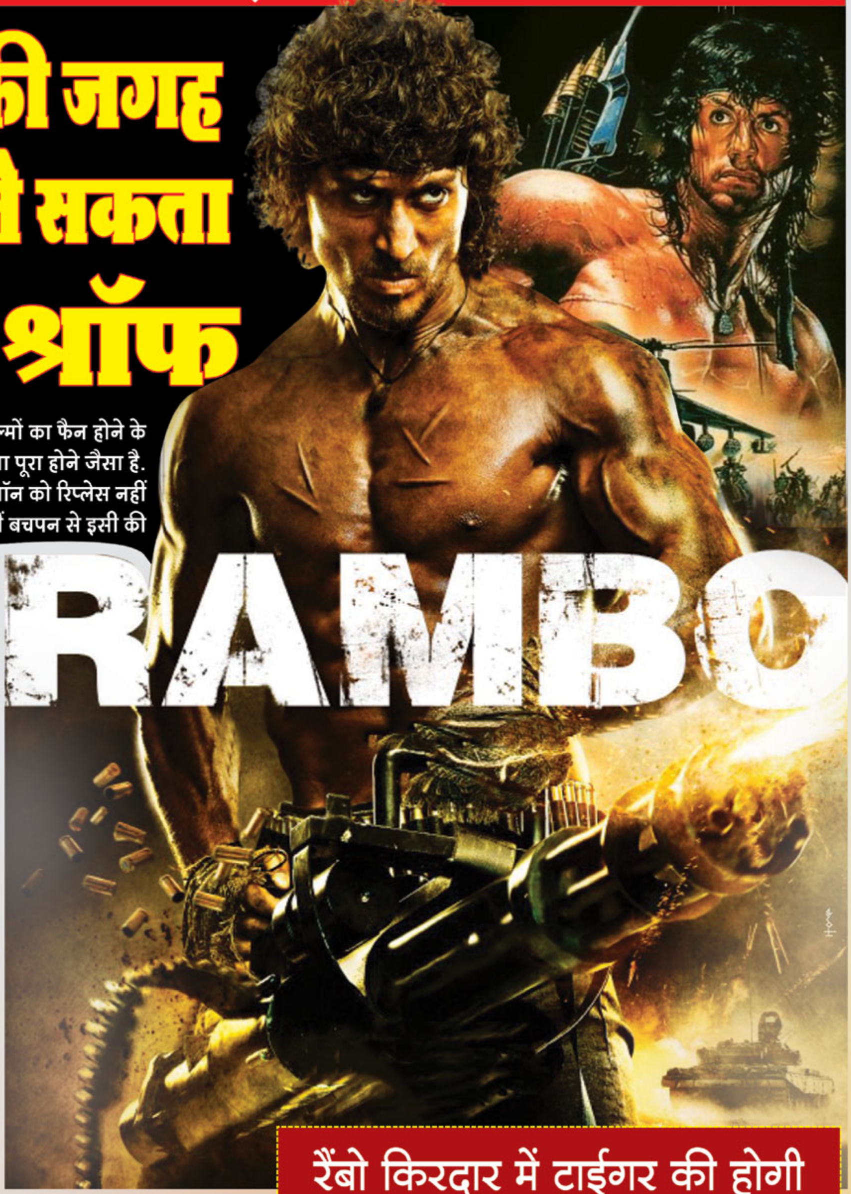

प्रवीण कुमार

हीरोपंती से लाखों दिलों में जगह बनाने वाले टाईगर श्रॉफ को हॉलीवुड फिल्म *रैंबो* के रीमेक में काम करने का मौका मिला है. वे मानते हैं कि इस फिल्म को करना उनके लिए एक चैलेंज से कम नहीं है. यह हॉलीवुड फिल्म रैंबो की रीमेक है, जिसमें सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टेलॉन ने शानदार भूमिका निभाई थी. यह वह दौर था जब वे अपने करियर को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे. रैंबो फिल्म के बाद से उनके दुनियाभर में करोड़ों फैन बने और आज भी उन्हें लोग अपना आदर्श मानते हैं. अब बॉलीवुड में भी सिल्वेस्टर की फिल्म रैंबो को बनाया जा रहा है, जिसमें टाईगर श्रॉफ मुख्य किरदार निभाते नज़र आएंगे. फिल्म का निर्देशन बैंग बैंग डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं.

हॉलीवुड सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टेलॉन को जब यह बात पता चली कि बॉलीवुड में उनकी फिल्म का रीमेक बनाया जा रहा है, तो उन्होंने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, *मैंने पढ़ा है कि इस फिल्म का रीमेक इंडिया में बनाया जा रहा है.. महान किरदार. उम्मीद है वह इसका कबाड़ा नहीं करेंगे...*

इसके जवाब में टाईगर श्रॉफ ने लिखा, *आपके रास्ते पर चलकर बहुत खुश और धन्य महसूस कर रहा हूं, आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता. उम्मीद है कि आपको निराश नहीं करूंगा.*

इसके बारे में टाईगर कहते हैं, बचपन से मार्शल आर्ट और ऐक्शन फिल्मों का फैन होने के बाद ऐसा मौका मिलना बहुत बड़ा सपना पूरा होने जैसा है. निश्चित रूप से मैं महान सिल्वेस्टर स्टेलॉन को रिप्लेस नहीं कर सकता हूं, लेकिन यह ऐसा है जैसे मैं बचपन से इसी की तैयारी कर रहा था.

स्टार किड होने के बाद भी टाईगर श्रॉफ एक ऐसे अभिनेता हैं, जो अपने दम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं. लेकिन आज तक उन्हें उनकी स्टारडम का वो हिस्सा नहीं मिला है, जिसके वो हकदार हैं. टाईगर श्रॉफ जब बॉलीवुड में आए, तो सबको लगा कि एक और स्टार किड बिना किसी टैलेंट के बॉलीवुड का इस्तेमाल करने आ गया. ख़ासतौर से इसलिए कि टाईगर की पहली फिल्म के लिए जैकी श्रॉफ की ब्लॉकबस्टर फिल्म हीरो की ट्यून का इस्तेमाल किया गया. ये साफ हो गया कि टाईगर अपने पापा जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल कर रहे हैं. जब टाईगर की पहली फिल्म हीरोपंती दर्शकों ने देखी तब माना कि स्टार किड होना एक बात होती है और फिल्मों में अभिनय करना या सफल होना दूसरी बात. आप स्टार किड होने के दम पर बॉलीवुड में एंट्री तो मार सकते हैं, लेकिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ना सिर्फ आपके हाथ में होता है, जो कड़ी मेहनत और लगन से ही निखरती है. टाईगर में वे सभी गुण मौजूद हैं, जो एक सफल अभिनेता में मौजूद होने चाहिए.

या यूं कहिए कि वो जितने भी स्टार बने हैं, ख़ुद की मेहनत से बने हैं और इसलिए टाईगर श्रॉफ के फैन्स जितने ईमानदार हैं, उतना ही टाईगर पर लोग जान भी छिड़कते हैं. क्योंकि वो स्टार किड होने के बावजूद, स्टार अपने दम पर बने.

अब आलम ये है कि टाईगर श्रॉफ वो फिल्म करने जा रहे हैं, जिसे करने के लिए सलमान से लेकर ऋतिक रोशन तक लाइन में लगे थे. सलमान इस दुनिया के सबसे बड़े सिल्वेस्टर फैन हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि इस फिल्म के लिए उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा. वहीं सिल्वेस्टर स्टोलॉन ने भी माना था कि अगर भविष्य में बॉलीवुड में कोई उन्हें रिप्लेस कर सकता है तो वह सलमान खान ही है. सलमान के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए ऋतिक के नाम की भी चर्चा ज़ोरों पर रही पर वो भी रिजेक्ट हो गए और अब लाइमलाइट में आ चुके हैं टाईगर श्रॉफ. टाईगर श्रॉफ ने अभी अपना करियर शुरू ही किया है. उन्होंने 2014 से 2017 तक में कुल 3 फिल्में की हैं, जिनमें *हीरोपंती (2014)*, *बाग़ी (2016)* और *अ फ्लाइंग जट्ट (2016)* शामिल है. इसके अलावा उनके पास तीन प्रोजेक्ट और है. उनकी इस साल मुन्ना माईकल रिलीज होने जा रही है, जबकि बाग़ी-2 और रैंबो 2018 में रिलीज होगी. टाईगर अपने छोटे से करियर में स्टारडम की सीढ़ी कितनी तेज़ी से चढ़े हैं, ये आप खुद देखिए-

अब टाईगर एक्टिंग में भले थोड़े कमजोर हों, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो इस समय बॉलीवुड में एक्शन के लिए बेस्ट हैं. अभी तक उन्होंने जितना एक्शन दिखाया है, वो शायद उनके टैलेंट का एक परसेंट है. इसके बावजूद टाईगर बिज़नेस में बेस्ट हैं. उनकी जेनरेशन का कोई एक्टर उनके आस पास भी नहीं फटकता.

टाईगर का स्टारडम: टाईगर ने साल 2014 में हिट फिल्म हीरोपंती से डेब्यू किया था. फिल्म रिलीज होने से पहले यही कहा जा रहा था कि टाईगर को जैकी श्रॉफ के बेटा होने का लाभ मिलेगा. लेकिन हीरोपंती रिलीज होने से पहले ही टाईगर श्रॉफ की अच्छी फिटनेस, स्टंट्स और मार्शल आर्ट्स की चर्चा हर तरफ होने लगी थी. इसके बाद जब टाईगर की हीरोपंती रिलीज हुई तो दर्शकों को कहना पड़ा कि बंदे में दम है. हीरोपंती में टाईगर के स्टंट्स लोगों को इतने पसंद आए कि हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा था.

अब ये उनकी फैन फॉलोइंग हो या फिर उनकी किस्मत, लेकिन टाईगर श्रॉफ बॉक्स ऑफिस पर हिट हैं. टाईगर श्रॉफ की आख़िरी फिल्म अ फ्लाइंग जट बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली. लोगों को पसंद भी नहीं आई, फिर भी फिल्म ने मुनाफा ना सही, अपनी लागत तो निकाल ही ली थी.

डांस में ऋतिक से होती है तुलना: बॉलीवुड में डांसिंग में अगर कोई नंबर एक है तो वह ऋतिक रोशन ही हैं. इसके बाद शाहिद कपूर का नंबर आता है, लेकिन टाईगर ने शाहिद को पीछे कर दिया और अब उनकी तुलना ऋतिक रोशन से की जाती है. वैसे भी टाईगर ऋतिक के डांस के कायल हैं और वे ऋतिक को अपना आदर्श मानते हैं. उनके अंदर बॉलीवुड के डांसिंग स्टार बनने वाले सारे लक्षण हैं और ये बात वो अपनी फिल्मों और सिंगल गानों से साबित कर चुके हैं.

मुन्ना माईकल से लग जाएगी मुहर: टाईगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म मुन्ना माईकल में टाईगर माईकल जैक्सन को ट्रिब्यूट दे रहे हैं. इस फिल्म के पोस्टर से ही लोगों ने उन्हें पास कर दिया है. वहीं माना जा रहा है कि जिसने भी फिल्म के पाट्‌र्स देखे हैं, उसने ये कह दिया है कि फिल्म से टाईगर श्रॉफ अपना झंडा गाड़ देंगे.

बेस्ट एक्शन हीरो: अब टाईगर एक्टिंग में भले थोड़े कमजोर हों, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो इस समय बॉलीवुड में एक्शन के लिए बेस्ट हैं. हालांकि अभी तक उन्होंने जितना एक्शन दिखाया है, वो शायद उनके टैलेंट का एक परसेंट है, लेकिन इसके बावजूद टाईगर बिज़नेस में बेस्ट हैं. उनकी जेनरेशन का कोई एक्टर उनके आस पास कहीं नहीं फटकता.

एक से बढ़कर एक टॉप के अभिनेताओं को पछाड़ते हुए टाईगर के हाथ फिल्म रैंबो लगी है. अब टाईगर श्रॉफ अपनी स्टारडम से एक ही कदम दूर हैं और इस फिल्म के साथ बॉलीवुड को उसका एक्शन किंग मिल जाएगा. वहीं सबसे अच्छी बात ये है कि रैंबो पूरी सीरीज़ है, ऐसे में अगर टाईगर पर पूरी सीरीज़ प्लान कर ली जाती है तो यह कहना पड़ेगा कि फिर उन्हें बॉलीवुड में कोई टक्कर नहीं दे पाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

रैंबो किरदार में टाईगर की होगी अग्निपरीक्षा

हॉलीवुड की सुपरहिट एक्शन फिल्म रैंबो के हिंदी रीमेक में टाईगर श्राफ का जबसे फर्स्ट लुक आया है, तब से सोशल मीडिया पर वे छा गए हैं. उनका ये लुक वाकई शानदार है. हर किसी को टाइगर श्रॉफ से बहुत उम्मीदें हैं कि वो हर हाल में इस किरदार के साथ न्याय करेंगे.

कोई शक नहीं कि टाईगर इस रैंबो लुक में बेहद दमदार दिख रहे हैं. वहीं, एक्शन के मामले में वो किसी से कम नहीं हैं. यह टाईगर अपनी पहले की फिल्मों में साबित कर चुके हैं. हालांकि टाईगर ने खुद कहा है कि मैं सिल्वेस्टर स्टैलॉन को रिप्लेस नहीं कर रहा. फिल्म फरवरी 2018 में फ्लोर पर आ जाएगी, जबकि 2018 के अंत तक फिल्म रिलीज हो सकती है.■

जून 2017 में आने वाली फिल्में

इस महीने बॉक्स ऑफिस पर आठ फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. इनमें से तीन फिल्में 2 जून को हॉरर मूवी दोबारा के अलावा डियर माया और बहन होगी तेरी रिलीज हो चुकी है. जून महीने की ख़ास बात यह है कि इस महीने ईद है और पूरे भारतवासियों को सलमान खान ईदी के तौर पर अपनी बहुचर्चित फिल्म ट्यूबलाइट दे रहे हैं. इसका दर्शक काफी समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. ज़ाहिर है कि हर बार की तरह सलमान खान की यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफलता के कई झंडे गाड़ने वाली है.

9 जून 2017

1

राबता

सुशांत सिंह राजपूत और क्रीति सेनन

16 जून 2017

2

बैंक चोर

रितेश देशमुख, रिहा चक्रवर्ती और विवेक ओबेराय

16 जून 2017

3

गेस्ट इन लंदन

कार्तिक आर्यन, परेश रावल और तनवी आज़मी

4

23 जून 2017

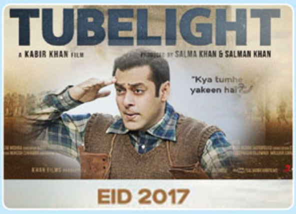

ट्यूबलाइट

सलमान खान, सोहेल खान और ज़ूह ज़ूह

30 जून 2017

5

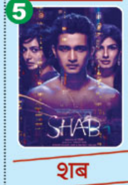

शब

आशिष बिष्ट, अर्पिता चटर्जी, संजय सूरी और रवीना टंडन